नवबिहार टाइम्स

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी दैनिक

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को बुके भेंट करते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार

• बोकारो, शुक्रवार 3 जुलाई 2026 • वर्ष : 10 • अंक : 47 • पृष्ठ : 12 • मूल्य : 3.00 रु. • RNI No. : JHAHIN2017/72655 • बोकारो, पटना व औरंगाबाद से प्रकाशित

संक्षिप्त समाचार

बच्ची को ढाल बना की चोरी

जमशेदपुर(नबिटा ब्यूरो)। परसुडीह थाना क्षेत्र में संत रॉबर्ट स्कूल के पास एक घर में दिनदहाड़े चोरी की घटना सामने आई है। गुलगुलिया गैंग की दो महिला सदस्यों ने एक मासूम बच्ची को ढाल बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि स्थानीय लोगों की सतर्कता के कारण दोनों महिलाओं को मौके से कुछ ही दूरी पर पीछा कर पकड़ लिया गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों ने लगभग 45 मिनट से अधिक समय तक इंतजार किया लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची।

पोलपोल बाजार में लगी भीषण आग

मेदिनीनगर(नबिटा ब्यूरो)। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत पोलपोल बाजार में बुधवार रात एक हार्डवेयर सह सैनिटरी दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरी दुकान उसकी चपेट में आ गई और लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दुकान संचालक नागेंद्र विश्वकर्मा को रात करीब 9 बजे आग लगने की सूचना मिली जिसके बाद वे तुरंत मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका।

सड़क किनारे मिला युवक का शव

देवघर(नबिटा ब्यूरो)। जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र में अंधरीगादर से कोरीडीह जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। मृतक की पहचान जसीडीह थाना क्षेत्र के जोरमो गांव निवासी पिंटू यादव के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर जसीडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पिंटू यादव बिहार में जेसीबी चालक के रूप में काम करता था।

अस्थायी कर्मचारियों को भी मिलेगा पेंशन का लाभ

रांची (नबिटा ब्यूरो)। झारखंड हाइकोर्ट जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने पेंशन लाभ से जुड़े मामले में दायर एक याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि तदर्थ आधार पर काम कर रहे अस्थायी कर्मचारी पेंशन लाभ के हकदार होंगे। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दशकों तक काम कर चुके कर्मचारियों की पेंशन को रोका नहीं जा सकता, भले ही वे अस्थायी कर्मचारी हों।

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भरा गणना प्रपत्र, नागरिकों से एसआईआर में शामिल होने की अपील

मतदान का अधिकार सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी : हेमंत

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

रांची। मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत गुरुवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में स्वयं गणना प्रपत्र भरकर एवं उस पर हस्ताक्षर कर रांची विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या-16 के बूथ स्तर पदाधिकारी मंजू कच्छप को सौंपा। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत उपस्थित रहे। इस मौके पर राज्यपाल ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों से आह्वान किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जब बूथ स्तर पदाधिकारी उनके घर गणना प्रपत्र लेकर आएं तो वे उसे तत्काल भरकर हस्ताक्षर सहित बीएलओ को उपलब्ध कराएं ताकि प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जा सके। राज्यपाल ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को इस महत्वपूर्ण अभियान के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शुभकामनाएं दीं और विश्वास जताया कि उनके समर्पित प्रयासों से राज्य के प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित रूप से दर्ज किया जा सकेगा। मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के तहत राज्य के 2 करोड़ 64 लाख 63 हजार 236 वोटरों की जांच होगी। प्रत्येक वोटर के लिए दो-दो इन्म्यूरेशन फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें हस्ताक्षर कर वोटर बीएलओ को सौंपेंगे। 29 जुलाई तक चलनेवाले इन्म्यूरेशन के दौरान बीएलओ घर-घर जाकर प्रत्येक वोटर से संपर्क करेंगे।

इन्म्यूरेशन फॉर्म में पिछले एसआईआर में दर्ज वोटर की जानकारी जिक्र करना अनिवार्य होगा और उसपर हस्ताक्षर कर बीएलओ को हर वोटर सौंपेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आज एसआईआर गणना प्रपत्र अपने आवासीय कार्यालय में भरा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने स्वयं एन्यूमरेशन प्रपत्र भरकर बीएलओ के समक्ष जमा किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंड के सभी पात्र मतदाताओं से तय समय सीमा के भीतर एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदान का अधिकार सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री के समक्ष निर्वाचन अधिकारियों की उपस्थिति में हटिया विधानसभा क्षेत्र के बूथ नम्बर-290 की बीएलओ ने एन्यूमरेशन फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी की। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने भी स्वयं अपना एन्यूमरेशन प्रपत्र भरकर जमा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे समय पर अपना एसआईआर प्रपत्र भरें तथा मतदाता सूची में अपनी जानकारी का सत्यापन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक की लोकतांत्रिक भागीदारी ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। मतदाता सूची का शुद्ध एवं अद्यतन होना स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की आधारशिला है। मुख्यमंत्री ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि सभी पात्र मतदाता एसआईआर अभियान में बढ़-चढ़कर अपनी महती भूमिका निभाएं तथा अपने परिवार, आसपास, पड़ोस और समाज के अन्य लोगों को भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित होकर एसआईआर प्रपत्र भरने के लिए प्रेरित करें।

दुमका कोर्ट को उड़ाने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

दुमका। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम से स्पीड पोस्ट के माध्यम से आए धमकी भरे पत्र ने दुमका में हड़कंप मचा दिया है। इसके बाद पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यह धमकी दुमका और गोड्डा दोनों जिलों के लिए दी गई है। दुमका एसपी खुद जांच के लिए कोर्ट पहुंचे। एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक पत्र आया है जिसमें कोर्ट पर हमले की धमकी दी गई थी। बांग्ला भाषा में लिखे इस पत्र में बकायदा चंचल राय के नाम से एक आधार कार्ड अटैच किया गया है जिसमें उसका पता पश्चिम बंगाल का जिला पूर्वी बर्दमान लिखा हुआ है। एसपी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से उन्हें इस पत्र की प्रति भेजी गई है। पत्र मिलने के बाद हमने त्वरित एक्शन लेते हुए आधार कार्ड में दिए गए एड्रेस को लोकेट किया और संबंधित थाने को फोन करके चंचल राय से संबंधित जानकारी ली।

अवैध शराब बनाने के आरोप में पूर्व एमएलसी गिरफ्तार

रांची(नबिटा ब्यूरो)। राजद के पूर्व एमएलसी सुबोध राय को अवैध शराब बनाने के आरोप में रांची पुलिस ने गिरफ्तार है। उत्पाद विभाग की छापेमारी के दौरान पूर्व एमएलसी की फैक्ट्री से अवैध शराब जब्त किया था। इसके बाद उन्हें बुधवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। रांची के ओरमांझी स्थित तरंगनी लिकर्स प्राइवेट लिमिटेड में पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 303 पेटी विदेशी शराब जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के मालिक राजद नेता और पूर्व एमएलसी सुबोध राय, उनके चालक देवेंद्र भगत और कर्मचारी रविकांत राय को गिरफ्तार किया गया है। ओरमांझी थाना प्रभारी मनोज कुमार ने तीनों के गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

झारखंड में पहली बार दागियों की जिलास्तरीय परेड

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

धनबाद। धनबाद पुलिस ने अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गुरुवार को झारखंड में पहली बार जिला स्तरीय दागियों की परेड आयोजित की। एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से लगभग 700 चिन्हित दागी व्यक्तियों को पुलिस लाइन बुलाया गया। यहां उनकी उपस्थिति दर्ज करा पहचान सत्यापित की गई और उन्हें अपराध छोड़कर सामान्य जीवन जीने की सलाह दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि दागियों की सूची पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर तैयार की जाती है। उन्होंने कहा कि अब तक ऐसी परेड थाना स्तर पर होती थी लेकिन यह पहली बार है जब पूरे जिले के चिन्हित दागियों को एक साथ बुलाकर उन्हें दागी सूची में शामिल होने के प्रभावों, कानून के पालन के महत्व और अपराध के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया है। एसएसपी ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपराध छोड़कर सामान्य जीवन जीना चाहता है तो पुलिस उसका पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों का नाम गलती से दागियों की सूची में शामिल हो गया है या जो लंबे समय से अपराध से दूर हैं वे संबंधित थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर अपना नाम सूची से हटाने का अनुरोध कर सकते हैं। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने चेतावनी दी कि यह सभी के लिए सुधार का अवसर है। यदि इसके बाद भी कोई व्यक्ति अपराध में संलिप्त पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब सहित जिले के सभी थाना प्रभारी और अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। पुलिस का उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय पैदा करना और जिले में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

रिम्स में एमबीबीएस, पीजी और सुपर स्पेशियलिटी सीटों में होगी बढ़ोतरी

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

रांची। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में मेडिकल शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। रिम्स में एमबीबीएस (यूजी), पीजी और सुपर स्पेशियलिटी की सीटों में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है। बढ़ी हुई सीटों के अनुरूप आधारभूत संरचना विकसित करने और केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगने के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष सचिव डॉ नेहा अरोड़ा, अपर सचिव शशि प्रकाश सिंह, संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला, रिम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ हिरेंद्र बिरूआ, मार्श एंड वॉइस के परामर्शी और जेएसबीसीसीएल के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को रिम्स में सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव के अनुसार एमबीबीएस की सीटें 176 से बढ़ाकर 250, पीजी सीटें 180 से बढ़ाकर 275 और सुपर स्पेशियलिटी सीटें 11 से बढ़ाकर 100 करने की योजना है। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि सीटों में प्रस्तावित वृद्धि को देखते हुए रिम्स में भवन, हॉस्टल, विभागीय कक्ष, प्रयोगशालाएं, ऑपरेशन थिएटर (ओटी), आधुनिक उपकरण, फैकल्टी, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य मानव संसाधनों की आवश्यकता का विस्तृत आकलन किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी आकलन के आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा ताकि केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रत्येक अतिरिक्त सीट पर लगभग 1.5 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सके। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि रिम्स की वर्तमान सुविधाओं और भविष्य की आवश्यकताओं का विस्तृत मूल्यांकन कर प्रस्ताव तैयार किया जाए, ताकि किसी भी संसाधन की कमी न रहे। उन्होंने जेएसबीसीसीएल को निर्देश दिया कि 15 दिनों के भीतर संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) विभाग को सौंपा जाए, जिससे समय पर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा सके। बैठक में पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेजों में भी मेडिकल सीटें बढ़ाने की योजना की समीक्षा की गई। दोनों मेडिकल कॉलेजों के विस्तार और उन्नयन के लिए संबंधित उपायुक्तों की ओर से अतिरिक्त भूमि उपलब्ध करा दी गई है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि भविष्य में दोनों मेडिकल कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा।

जगन्नाथपुर रथ यात्रा महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

रांची। जिले के धुर्वा में ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथपुर रथ यात्रा महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। 16 जुलाई से शुरू होने वाले इस भव्य धार्मिक आयोजन को लेकर मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में युद्धस्तर पर तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन और आयोजन समिति इस बार भी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करने में जुटी है। जिस रथ पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा विराजमान होंगे, उसकी मरम्मत और साज-सज्जा का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस काम के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल से आए अनुभवी कारीगर और मैकेनिक जुटे हुए हैं। रथ को पारंपरिक स्वरूप में तैयार किया जा रहा है ताकि वर्षों पुरानी परंपरा और धार्मिक गरिमा बरकरार रहे। इस वर्ष जगन्नाथपुर रथ यात्रा मेले का ठेका 2.27 करोड़ रुपये में दिया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। ठेका राशि बढ़ने के कारण मेले में लगने वाली दुकानों, स्टॉलों और झूलों के किराये में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसका असर कारोबारियों के साथ-साथ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और आम लोगों पर भी पड़ सकता है।

वेतन विसंगति सुलझाने के लिए हाईलेवल कमेटी गठित

रांची(नबिटा ब्यूरो)। झारखंड की हेमंत सरकार ने राज्य सरकार के कर्मियों के वेतन विसंगति, एमएसीपी एवं अन्य सेवा शर्तों की विसंगतियों के संबंध में बड़ा कदम उठाते हुए छह सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। वित्त विभाग के द्वारा जारी पत्र के अनुसार सदस्य राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के पांच सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को इस कमेटी में बतौर सदस्य बनाया गया है। वित्त सचिव प्रशांत कुमार के हस्ताक्षर से जारी वित्त विभाग के पत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी ओम प्रकाश साह, राज्य पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी राज नारायण सिंह, राज्य शिक्षा सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी जयंत कुमार मिश्रा, राज्य अभियंत्रण सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी उमेश मेहता को शामिल किया गया है। यह उच्चस्तरीय समिति समय-समय पर राज्य की विभिन्न सेवा संघों द्वारा उठाई गई वेतन विसंगति विभिन्न सेवाओं की सेवा शर्तों में एकरूपता लाने और एमएसीपी संबंधी मामलों का निराकरण के संबंध में सुझाव और अनुशंसा राज्य सरकार को देने का काम करेगी। राज्य सरकार द्वारा वेतन विसंगति, एमएसीपी सहित अन्य मामलों के समाधान के लिए उच्चस्तरीय समिति के गठन का निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 8 अक्टूबर 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। कर्मचारी संगठनों के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री के समक्ष वेतन विसंगति को लेकर मांग होती रही थी। इधर, उच्चस्तरीय समिति के गठन का झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने स्वागत किया है। महासंघ के उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने कहा है कि इसको लेकर विभिन्न मंचों पर सरकार से यह मांग की जा रही थी, जिसे देर से ही सही इस ओर अब पहल की गई है। बिहार से अलग होकर झारखंड गठन के बाद यहां पदस्थापित कर्मचारियों की समस्या अलग-अलग हैं। वेतन विसंगति से लेकर प्रोन्नति और एमएसीपी का मुद्दा उच्चस्तरीय समिति के माध्यम से सुलझाने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि आज भी राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का तृतीय वर्ग में प्रोन्नति का मामला लटका हुआ है, जबकि बिहार में यह बहुत पहले हो चुका है।

एसआईआर में वॉलंटियर्स निभाएंगे भूमिका, कोई भी मतदाता नहीं छूटेगा : उपायुक्त

बीएलओ के साथ मिलकर घर-घर पहुंचेंगे स्वयंसेवक, 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं के नाम जोड़ने पर रहेगा विशेष फोकस

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

गिरिडीह। विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर 2026) अभियान के तहत जिले के प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि अभियान में वॉलंटियर्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले का कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे।उपायुक्त ने बताया कि प्रत्येक बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) के साथ एक-एक वॉलंटियर की प्रतिनियुक्ति की गई है।

ये वॉलंटियर्स निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेर्शों के अनुरूप बीएलओ का सहयोग करते हुए नए मतदाताओं की पहचान, दस्तावेजों के सत्यापन, नामांकन प्रपत्र भरवाने तथा मतदाता सूची से संबंधित अन्य कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान वृद्ध, दिव्यांग, गंभीर रूप से बीमार, आर्थिक रूप से कमजोर तथा अन्य संवेदनशील वर्गों के मतदाताओं को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसी भी पात्र नागरिक को पंजीकरण में परेशानी न हो उपायुक्त ने बताया कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए वॉलंटियर्स गांव-गांव जाकर ऐसे युवाओं और अन्य पात्र नागरिकों की पहचान करेंगे, जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो सका है। बीएलओ बीएलए-2 बैठकों और चुनावी पाठशालाओं के माध्यम से भी नए मतदाताओं का पंजीकरण कराया जाएगा।उन्होंने कहा कि वॉलंटियर्स जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ बीएलओ-बीएलए-2 बैठकों के दस्तावेजीकरण, एएसडीडीएफ सूची के सत्यापन तथा अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों में भी सहयोग करेंगे। यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या, फर्जी दस्तावेज, गलत घोषणा पत्र या संदिग्ध गतिविधि सामने आती है तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दी जाएगी, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी बीएलओ, सुपरवाइजर, वॉलंटियर्स एवं निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों से समन्वय के साथ पूरी निष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एसआई आर 2026 केवल मतदाता सूची के पुनरीक्षण का अभियान नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में जनभागीदारी का व्यापक अभियान है।

बूथों पर पहुंचे डीसी, एसआईआर अभियान का लिया जायजा

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

गिरिडीह। लगातार बारिश के बावजूद जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर फ2026) अभियान जारी है। गुरुवार सुबह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 18 व 19 सहित विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा कर अभियान की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण, दस्तावेजों के सत्यापन तथा डिजिटाइजेशन कार्य का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर एवं वॉलंटियर्स से अभियान की प्रगति की जानकारी ली तथा कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी पात्र मतदाता अभियान से वंचित नहीं रहना चाहिए। सभी परिवारों तक पहुंचकर गणना प्रपत्र भरवाने तथा प्राप्त प्रपत्रों का समयबद्ध और त्रुटिरहित डिजिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए।

जमशेदपुर हत्याकांड में पुलिस पर एफआईआर हो : बाबूलाल मरांडी

सिर्फ एसपी का तबादला पर्याप्त नहीं, निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

गिरिडीह। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को गिरिडीह स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिम्मेदार हैं मरांडी ने हाल ही में जमशेदपुर में करणी सेना के एक नेता की पुलिस की मौजूदगी में हुई हत्या का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने मामले में केवल खानापूर्ति की है।

उन्होंने कहा कि घटना के बाद जमशेदपुर और सरायकेला के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) का तबादला कर देना पर्याप्त कार्रवाई नहीं है। यदि पुलिस की मौजूदगी में हत्या हुई है तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि जिस होटल में मृतक ने भोजन किया था, उसके संचालकों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। मरांडी ने सवाल उठाया कि जब हत्या सड़क पर पुलिस के सामने हुई, तो होटल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करने का औचित्य क्या है नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर बाहरी दबाव हावी है। उन्होंने दावा किया कि एक एएसआई के प्रभाव में कई विभागों के अधिकारी काम करने को मजबूर हैं और थानों में पदस्थापन तक उसी के इशारे पर होने की बातें सामने आ रही हैं। इससे अधिकारियों की स्वतंत्रता प्रभावित हुई है और कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है मरांडी ने मांग की कि जमशेदपुर हत्याकांड में पुलिस और प्रशासन की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो तथा पीड़ित परिवार की सभी जायज मांगों को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई से ही जनता का कानून-व्यवस्था पर विश्वास बहाल हो सकेगा।

संक्षिप्त समाचार

क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में बरगंडा शिशु विद्या मंदिर का शानदार प्रदर्शन, जीता रजत पदक

गिरिडीह (नवबिहार टाइम्स संवाददाता)। विद्या भारती द्वारा पर्वत श्रेणी, बेतिया में आयोजित 37वीं क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता-2026 में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, बरगंडा की कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उपविजेता बनने का गौरव हासिल किया। टीम ने पूरे टूनार्मेंट में दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया विद्यालय की टीम ने आचार्या श्रीमती अनीता दीदी एवं श्री प्रसून आचार्य के मार्गदर्शन में फाइनल तक का सफर तय किया। खिलाड़ियों ने अनुशासन, तकनीकी कौशल और खेल भावना का उत्कृष्ट परिचय देते हुए विद्यालय का नाम पूरे क्षेत्र में गौरवान्वित किया प्रतियोगिता से लौटने पर गुरुवार सुबह विद्यालय की वंदना सभा में विजेता खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। प्राचार्य आनंद कमल ने सभी खिलाड़ियों को प्रमाण-पत्र एवं रजत पदक प्रदान कर सम्मानित किया इस अवसर पर प्राचार्य आनंद कमल ने कहा कि यह उपलब्धि केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्कार, अनुशासन और कठिन परिश्रम की भी जीत है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने विद्या भारती के 'खेलो और खिलो' के मंत्र को साकार किया है। उन्हें विश्वास है कि छात्र-छात्राएं आगे भी इसी समर्पण के साथ मेहनत कर राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम में विद्यालय के आचार्य-बंधु, आचार्या भगिनी एवं विद्यार्थियों ने करतल ध्वनि से विजेता खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

डीएवी सीसीएल गिरिडीह के प्राचार्य ने नवपदस्थापित सीसीएल जीएम कन्हैया शंकर गाइवाल का किया स्वागत

गिरिडीह (नवबिहार टाइम्स संवाददाता)। सीसीएल गिरिडीह क्षेत्र के नवपदस्थापित महाप्रबंधक कन्हैया शंकर गाइवाल का डीएवी सीसीएल गिरिडीह के प्राचार्य ओम प्रकाश गोयल ने सीसीएल कार्यालय पहुंचकर पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर प्राचार्य ने गाइवाल को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की प्राचार्य ओम प्रकाश गोयल ने कहा कि गाइवाल के नेतृत्व में सीसीएल गिरिडीह क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सीसीएल और डीएवी विद्यालय के बीच शिक्षा, सामाजिक सरोकार तथा जनकल्याण से जुड़े सहयोगात्मक कार्यों को और अधिक गति मिलेगी।वहीं, नवपदस्थापित महाप्रबंधक कन्हैया शंकर गाइवाल ने आत्मीय स्वागत के लिए प्राचार्य का आभार व्यक्त किया। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक विकास और जनहित से जुड़े कार्यों में डीएवी विद्यालय के साथ निरंतर सहयोग एवं समन्वय बनाए रखने का आश्वासन दिया।

एलआईसी को कमजोर करने की हर कोशिश का करेंगे विरोध : धर्म प्रकाश

गिरिडीह (नवबिहार टाइम्स संवाददाता)। एलआईसी गिरिडीह शाखा कार्यालय में बुधवार को अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ (एआईआईईए) का 76वां स्थापना दिवस समारोह उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की शुरूआत संघ की उपाध्यक्ष कुमकुम बाला वर्मा द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुई। कार्यक्रम का संचालन मंडलीय सांगठनिक सचिव अनुराग मुर्मू ने किया संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ की स्थापना 1 जुलाई 1951 को हुई थी। स्थापना के समय से ही संघ ने बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण की मांग को लेकर लगातार संघर्ष किया, जिसके परिणामस्वरूप देश की 250 निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की स्थापना की गई धर्म प्रकाश ने कहा कि एलआईसी ने मात्र 5 करोड़ रुपये की पूंजी से अपनी यात्रा शुरू की थी और आज इसकी परिसंपत्तियां 55 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी हैं। यह देश की सबसे मूल्यवान वित्तीय संस्थाओं में से एक है और देश की आर्थिक रीढ़ के रूप में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार निगम विरोधी नीतियों पर आगे बढ़ती है तो अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ देशव्यापी आंदोलन करेगा स्थापना दिवस के अवसर पर एलआईसी शाखा कार्यालय परिसर में सत्तू-शर्बत वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें 500 से अधिक लोगों ने शर्बत ग्रहण किया कार्यक्रम में पेंशनर संघ के लक्ष्मी नारायण गुप्ता, संहिता सरकार, डेनियल मरांडी तथा बीमा कर्मचारी संघ के अनुराग मुर्मू, कुमकुम बाला वर्मा, विजय कुमार, राजेश कुमार उपाध्याय, उमानाथ झा, रोशन कुमार, सुनील कुमार वर्मा, विनय कुमार, अंशु सिंघानिया, सबा प्रवीण, प्रदीप कुमार, अभय कुमार, मो. महफूज अली, कुलजीत कुमार, देवनाथ दास, प्रभाष कुमार, संजय कुमार शर्मा, प्रदीप प्रसाद, घनश्याम साव सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे।

बेंगाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस शिविर के दौरान सड़क सुरक्षा का दिया संदेश, 200 से अधिक आवेदक हुए जागरूक

गिरिडीह (नवबिहार टाइम्स संवाददाता)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार, माननीय परिवहन मंत्री श्री दीपक बिरुवा के निर्देश तथा उपायुक्त श्री रामनिवास यादव के मार्गदर्शन में जिले के सभी प्रखंडों में ड्राइविंग लाइसेंस (नवशिखुवा चालक अनुज्ञप्ति/लर्निंग लाइसेंस) निर्माण के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है इसी क्रम में गुरुवार को बेंगाबाद प्रखंड में आयोजित विशेष शिविर के दौरान नवशिखुवा चालक अनुज्ञप्ति (लर्निंग लाइसेंस) के लिए आवेदन प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। अधिकारियों ने सुरक्षित वाहन संचालन, हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन, नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने तथा यातायात संकेतों का पालन करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी।शिविर के दौरान लगभग 200 से 250 इच्छुक आवेदकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया। अधिकारियों ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए वाहन चालकों का प्रशिक्षित और जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है।

154 आवेदनों को मंजूरी, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की प्रगति की डीसी ने की समीक्षा

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

गिरिडीह। उपायुक्त रामनिवास यादव ने गुरुवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को मिल रहे लाभ की जानकारी ली गई जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत अब तक कुल 154 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बैठक में इन सभी आवेदनों की समीक्षा के बाद 154 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक पात्र लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति योजना से वंचित न रहे।बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह, गांडेय, धनवार एवं डुमरी के विधायक प्रतिनिधि तथा कल्याण विभाग के अधिकारी एवं अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे।

तमिलनाडु गैस रिसाव के बाद सकुशल लौटे गिरिडीह के तीन प्रवासी श्रमिक

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

गिरिडीह। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले स्थित सेंट पीटर्स एंड पॉल सेफ्टेक्स एक्सपोर्ट फैसिलिटी में 21 जून को हुए अमोनिया गैस रिसाव के बाद झारखंड सरकार की पहल पर प्रभावित प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी कराई गई। इसी क्रम में गुरुवार को गिरिडीह जिले के तीन प्रवासी श्रमिक—सुंदर राम किरकू, जितेंद्र बेसरा और लखीधर मुर्मू—सकुशल अपने घर लौट आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, राज्य नियंत्रण कक्ष, तिरुवल्लूर जिला प्रशासन, तमिलनाडु श्रम विभाग, रेलवे अधिकारियों और गिरिडीह जिला प्रशासन के समन्वय से राहत कार्य संचालित किया गया। संयुक्त प्रयास से झारखंड के कुल 42 प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई। विशेष अनुरोध पर रेलवे प्रशासन ने चेन्नई से धनबाद तक प्रभावित श्रमिकों के लिए विशेष रेल टिकट उपलब्ध कराया गिरिडीह पहुंचने पर सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक कार्यालय के अधिकारियों ने श्रमिकों का स्वागत किया। इसके बाद जिला प्रशासन ने सरकारी वाहन से उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की। साथ ही श्रम विभाग ने तीनों श्रमिकों को विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने और नियमानुसार लाभ दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

बरही में अवैध डोडा का जखीरा बरामद, 697 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

हजारीबाग ब्यूरो । हजारीबाग पुलिस ने नशा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बरही थाना क्षेत्र के रसोईयाधमना गांव से करीब 697 किलोग्राम अवैध डोडा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 47 बोरा डोडा जब्त किया है। मामले में दो लोगों को आरोपी बनाया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक को 1 जुलाई को गुप्त सूचना मिली थी कि रसोईयाधमना गांव में बंगाली साव उर्फ बबलू साव के मुर्गी फॉर्म के पास बने कार्कट के कमरे में अवैध डोडा का भंडारण कर उसकी तस्करी की तैयारी की जा रही है।

सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बरही राधाप्रेम किशोर के नेतृत्व में छापेमारी दल ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान कमरा बंद मिला। काफी प्रयास के बाद भी मालिक के नहीं पहुंचने पर स्थानीय मुखिया, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए ताला तोड़ा गया। कमरे की तलाशी लेने पर प्लास्टिक के 47 बोरों में भरा डोडा बरामद हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन से वजन कराने पर सभी बोरों का कुल वजन 697 किलोग्राम पाया गया। इसके बाद विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए दो स्थानीय गवाहों की उपस्थिति में जब्ती सूची तैयार कर सभी मादक पदार्थ को जब्त कर थाना लाया गया। इस मामले में बंगाली साव उर्फ बबलू साव और सुनील राणा, दोनों निवासी रसोईयाधमना, थाना बरही, को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बरही राधाप्रेम किशोर, बरही थाना प्रभारी बिनोद कुमार सहित बरही थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल शामिल रहे।

डॉ. मिहिर किडनी केयर हॉस्पिटल ने शुरू किया जागरूकता अभियान

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

धनबाद । भारत में क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी सीकेडी एक बड़े स्वास्थ्य संकट के रूप में उभर रही है। देश में 13.8 करोड़ से ज्यादा वयस्क सीकेडी से प्रभावित हैं और हर साल 2.2 लाख नए मरीजों को डायलिस की जरूरत पड़ती है। 2011 से 2023 के बीच 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में सीकेडी के मामले 11.12% से बढ़कर 16.38% हो गए हैं। सबसे चिंताजनक बात ये है कि 90% से अधिक लोगों का निदान तब होता है जब बीमारी अंतिम अवस्था में पहुंच जाती है। इसी 'साइलेंट किलर' से लड़ने के लिए डॉ. मिहिर किडनी केयर हॉस्पिटल पिछले 1 साल से झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के मरीजों को विशेषज्ञ किडनी देखभाल दे रहा है। ये धनबाद का एकमात्र समर्पित किडनी हॉस्पिटल है। डॉ. मिहिर कुमार ने कहा, "सीकेडी शुरूआती स्टेज में कोई लक्षण नहीं दिखाती। मरीज को तब पता चलता है जब डायलिस या ट्रांसप्लांट ही विकल्प बचता है। हमारा मिशन है कि हर डायबिटीज और बीपी के मरीज हर साल अपना [illegible] और यूरिन टेस्ट जरूर कराएं।"

भूमि अधिग्रहण कानून लागू कराने को कांग्रेस का अभियान तेज 6 जुलाई को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे मंत्री व वरिष्ठ नेता

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

केरेडारी (हजारीबाग)। कोयला परियोजनाओं से प्रभावित विस्थापितों, किसानों और ग्रामीणों के अधिकारों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। आगामी 6 जुलाई को प्रस्तावित जन-अधिकार कार्यक्रम की तैयारियों के लिए गुरुवार को केरेडारी पंचायत भवन में रणनीतिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाने की रूपरेखा तैयार की गई।

बैठक की अध्यक्षता प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष रविन्द्र कुमार गुप्ता ने की, जबकि संचालन वरिष्ठ कांग्रेस नेता मो. दिलदार अंसारी ने किया। बैठक में पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसमें कांग्रेस पदाधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने व्यापक भागीदारी की। बैठक में बताया गया कि 6 जुलाई को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के. राजू, राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई विधायक प्रस्तावित दौरे पर क्षेत्र में पहुंचेंगे। इस दौरान कोयला परियोजनाओं और अन्य विकास योजनाओं से प्रभावित लोगों की समस्याओं एवं मांगों को उनके समक्ष रखा जाएगा। पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव ने कहा कि लंबे समय से भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से जुड़े मामलों में प्रभावित परिवारों को अपेक्षित न्याय नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू कर विस्थापितों, किसानों और प्रभावित परिवारों को उनका वैधानिक अधिकार दिलाने की दिशा में कांग्रेस संघर्ष जारी रखेगी। बैठक में उपस्थित नेताओं और ग्रामीणों ने 6 जुलाई के कार्यक्रम को व्यापक जनभागीदारी के साथ सफल बनाने का संकल्प लिया। प्रखंड के सभी पंचायत अध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रतिनिधिमंडल रसदा (छाया डैम), गोंदलपुरा, चेपा कला, समाधान भवन, कण्डाबेर बाजार टांड, बसरिया बाजार, पगार और पचड़ा गांव का दौरा करेगा, जहां प्रभावित ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं और मांगों को सुना जाएगा।

स्कूल भवन निर्माण के नाम पर आए फंड के गबन का आरोप, जांच की मांग तेज

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

गिरिडीह। बिरनी प्रखंड के खाखीपीपर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में वर्ष 2009-10 में विद्यालय भवन निर्माण के लिए स्वीकृत ₹4.75 लाख की राशि के कथित गबन और अन्य अनियमितताओं का मामला एक बार फिर चर्चा में है। गांव निवासी राजू अंसारी ने इस संबंध में उपायुक्त, गिरिडीह को लिखित आवेदन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है आवेदन में कहा गया है कि विद्यालय भवन निर्माण के लिए सरकार से राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन आज तक भवन का निर्माण नहीं हो सका।

आरोप है कि स्वीकृत राशि का दुरुपयोग कर उसका बंदरबांट कर लिया गया। इसके अलावा विद्यालय में मध्याह्न भोजन (एमडीएम), साइकिल वितरण और छात्रवृत्ति जैसी सरकारी योजनाओं के संचालन में भी अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया गया है।आवेदन में यह भी कहा गया है कि विद्यालय के दो शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते हैं और उपस्थिति पंजी में कथित रूप से फर्जी हाजिरी दर्ज की जाती है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है मामले की जानकारी मिलने पर माले नेता राजेश सिन्हा ने शिक्षा विभाग के एडीपीओ प्रकाश सिन्हा से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। राजेश सिन्हा का आरोप है कि विभागीय अधिकारी ने दो महीने पहले जांच का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

महिला कॉलेज में झारखण्ड एसआईआर अभियान को मिली रफ्तार

बीएलओ टीम ने घर-घर पहुंचकर जुटाए प्रपत्र, वार्ड पार्षद संगीता कुमारी व समाजसेवी रमेश सिन्हा ने किया सहयोग

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

गिरिडीह। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत गुरुवार को वार्ड संख्या-9 स्थित महिला कॉलेज परिसर में बूथ संख्या 36, 37, 40 एवं 41 पर मतदाता सत्यापन एवं प्रपत्र संग्रहण का कार्य उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। अभियान के दौरान बीएलओ रेखा शर्मा, शिवम कुमार, शमीमा खातून एवं जूली बरनवाल ने मतदाताओं के दस्तावेजों का सत्यापन कर निर्धारित प्रपत्रों का संग्रह किया वार्ड पार्षद संगीता कुमारी ने अभियान का निरीक्षण करते हुए मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर समय पर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शुद्ध एवं अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती का आधार है अभियान में समाजसेवी रमेश सिन्हा ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने बीएलओ टीम के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों को एसआईआर अभियान के प्रति जागरूक किया तथा पात्र मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेजों के साथ सत्यापन कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में प्रशासन का सहयोग करे, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहे अभियान के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने दस्तावेज जमा कर सत्यापन प्रक्रिया पूरी की। बूथों पर लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गईं, जिससे पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई।

डीएमएफटी योजनाओं की समीक्षाः 15 अगस्त तक लंबित कार्य पूरे करने का निर्देश

गुणवत्ता से समझौता नहीं, मानक के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले संवेदकों को नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

हजारीबाग। उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) मद से स्वीकृत विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एनआईपी, जिला परिषद, भवन प्रमंडल एवं विशेष प्रमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने संबंधित विभागों के कनीय अभियंताओं को कार्यस्थलों पर नियमित रूप से उपस्थित रहकर संवेदकों द्वारा कराए जा रहे कार्यों की सतत निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी संवेदक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य नहीं किया जाता है,

तो उसे परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाए। उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की सभी लंबित योजनाओं को हर हाल में 15 अगस्त 2026 तक पूरा कराने का निर्देश दिया। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 की स्वीकृत योजनाओं को 26 जनवरी 2027 तक पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित करते हुए सभी विभागों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में नए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि सभी नए आंगनवाड़ी भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली तथा तड़ित चालक (लाइटनिंग अरेस्टर) की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए, ताकि भवन पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ सुरक्षित भी रहें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं विभिन्न प्रखंडों का दौरा कर डीएमएफटी योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करेंगे। सभी कार्यपालक अभियंताओं एवं संबंधित अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में उप विकास आयुक्त रिया सिंह, प्रशिक्षु आईएएस पूर्वा अग्रवाल, जिला योजना पदाधिकारी पंकज कुमार तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं अभियंता उपस्थित रहे।

हिमांशु हत्याकांडः जमशेदपुर बंद की पूर्व संध्या पर एनडीए का मशाल जुलूस, सरयू राय हुए शामिल

जपा ने 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद का किया आह्वान

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

जमशेदपुर। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के डबल डाउन बार के बाहर चाकूबाजी से गंभीर रूप से घायल हुए हिमांशु की मौत के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। शहर में बढ़ते अपराध को देखते हुए भाजपा ने 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद का आह्वान किया है। एनडीए की सहयोगी पार्टियां आजसू और जदयू भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। बंद से एक दिन पहले, भाजपा, जदयू और आजसू की अलग-अलग इकाइयों ने शहर के कई हिस्सों में मशाल जुलूस निकाला और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल हुईं। जदयू

विधायक सरयू राय भी इस मार्च में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शहर में लगातार बढ़ते अपराध से लोग डरे हुए हैं। इसलिए, जमशेदपुर में 3 जुलाई का बंद सरकार के लिए एक चेतावनी है। उन्होंने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि जिला प्रशासन की मिलीभगत से अपराध बढ़ रहे हैं। शहर में चापड़ बाजी, चेन स्नेचिंग और दूसरी आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि राज्य के दूसरे शहरों में भी जमशेदपुर जैसी स्थिति न बने।

उन्होंने कहा कि आम नागरिकों और दुकानदारों ने भी कल के बंद को अपना समर्थन देने का वादा किया है। उन्होंने यह भी बताया कि छात्रों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट से 3 जुलाई को स्कूल बंद रखने के बारे में बातचीत की गई है।

गौरतलब है कि अपराधी पुलिस के सामने हिमांशु और उसके साथी प्रत्युष पर चापड़ से हमलाकर फरार हो गए थे। इस घटना से लोगों में भारी आक्रोश है।

खेल विभाग की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग, आदिवासी छात्र संघ का प्रदर्शन

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

रांचीः डॉ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (DSPMU) में गुरुवार को आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले छात्रों ने खेल विभाग में कथित अनियमितताओं और जांच में देरी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ रोष जताया और खेल विभाग से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कहा कि यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा।प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि खेल विभाग में सामने आए कथित मामलों को लेकर संगठन पहले भी दो बार कुलपति को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। इसके बावजूद अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। छात्रों का आरोप है कि शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा और जांच प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी खींची जा रही है। आदिवासी छात्र संघ ने आरोप लगाया कि खेल विभाग में खिलाड़ियों के नाम पर वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। इसके अलावा महिला खिलाड़ियों के साथ कथित शोषण के आरोपों की भी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग की गई। छात्रों का कहना है कि इन आरोपों के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच समिति का गठन तो किया, लेकिन करीब डेढ़

माह बीत जाने के बाद भी समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। इससे छात्रों के बीच असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है।

प्रदर्शनकारियों ने यह भी दावा किया कि मामले को राज्यपाल के समक्ष भी उठाया जा चुका है। इसके बावजूद अब तक किसी भी स्तर पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। उनका आरोप है कि जांच रिपोर्ट को जानबूझकर रोका जा रहा है और संबंधित शिक्षक को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रों ने कहा कि यदि जांच निष्पक्ष है तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

छात्रों के अनुसार कई विद्यार्थियों ने जांच समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा और लिखित शिकायतें भी सौंपीं। इसके बावजूद शिकायतकर्ताओं को अब तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। उनका कहना है कि पारदर्शिता के अभाव में छात्रों का विश्वविद्यालय प्रशासन पर भरोसा कमजोर हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण रहा, हालांकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। छात्रों ने मांग की कि जांच समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र सार्वजनिक करे और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों की अनदेखी होने पर आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और तेज किया जाएगा। आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष विवेक तिर्की खेल विभाग से जुड़े गंभीर मामलों को लेकर कहा कि हम पहले भी दो बार कुलपति को ज्ञापन दे चुके हैं। जांच समिति बने डेढ़ माह से अधिक समय हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। हमारी मांग है कि निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। जबकि छात्रा सीमा मुर्मू ने कहा कि कई छात्र-छात्राओं ने जांच समिति के सामने अपना पक्ष रखा और लिखित शिकायत भी दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विश्वविद्यालय को पारदर्शिता दिखाते हुए रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए और छात्रों को न्याय दिलाना चाहिए।

क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर राज्यस्तरीय कॉन्क्लेव आयोजित

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

जमशेदपुर। रांचीः पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने रांची स्थित खुद के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 जुलाई को रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में झारखंड की नौ मान्यता प्राप्त जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन को लेकर राज्यस्तरीय कॉन्क्लेव आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य गठन के बाद पहली बार संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ख, खड़िया, नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा समेत सभी नौ भाषाओं को एक मंच पर लाया जाएगा।

मातृभाषाओं से दूर होती जा रही है नई पीढ़ीः पूर्व मंत्री

बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड बनने के 26 साल बाद भी इन भाषाओं के संरक्षण और शिक्षा

में अपेक्षित कार्य नहीं हो सका है, जिससे नई पीढ़ी अपनी मातृभाषाओं से दूर होती जा रही है। उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव में करीब 2,500 छात्र-छात्राएं, शोधार्थी, प्रोफेसर और भाषाविद शामिल होंगे। बंधु तिर्की ने कहा कि यह आयोजन जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होगा।

पूर्व शिक्षा मंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि राज्य में राजनीति करने वाले, जो भी दल जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को नजरअंदाज करेंगे, वह राज्य की राजनीति से मिट जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में नकारात्मक खबरों के बीच शिक्षा और उसमें भी मान्यता प्राप्त 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का राज्यस्तरीय कॉन्क्लेव का आयोजन अपने आप में खास होगा।

पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान साफ शब्दों में कहा कि झारखंड निर्माण के 26 साल में जितनी भी सरकार बनी है, उसमें से किसी सरकार ने राज्य की मान्यता प्राप्त 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए उतना काम नहीं किया जितना होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पहली बार उन्होंने अपने स्तर से यह पहल की है कि राज्यस्तरीय कॉन्क्लेव में एक साथ 2500 से ज्यादा छात्र-छात्राएं, रिसर्च फेलो और इन भाषाओं के पुरोधा एक साथ बैठकर अपनी भाषा के विकास और संवर्धन पर व्यापक चर्चा करेंगे।

रांची में मनाई गई होम्योपैथी के जनक डॉ. हैनीमेन की पुण्यतिथि

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

रांची। झारखंड होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की रांची ईकाई के तत्वावधान गुरूवार को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक डॉ. सैमुअल हैनीमेन की पुण्यतिथि सादगी और श्रद्धापूर्वक मनाई गई। रांची के अपर बाजार में झारखंड होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व विधायक और होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. जीतू चरण राम, जेएचएमए रांची के संयोजक डॉ. अरविंद सहित कई होम्योपैथिक चिकित्सकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व विधायक डॉ. जीतू चरण राम ने डॉ. सैमुअल हैनीमेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जर्मनी में डॉ। सैमुअल हैनीमेन का जन्म हुआ था, उन्होंने दुनिया के कई देशों का भ्रमण किया और बीमारी के साथ उनके इलाज की होम्योपैथिक पद्धति का आविष्कार भी किया। पूर्व विधायक ने कहा कि लोगों तक गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा पहुंचाकर ही डॉ। सैमुअल हैनीमेन को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है।

जून में सामान्य से आधी भी नहीं हुई झारखंड में मानसूनी बारिश

रांची/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। इस बार समय पर झारखंड में दस्तक देने के बावजूद जून महीने में मानसून की बारिश सामान्य से 54% कम हुई है। मौसम केंद्र,रांची द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार जून 2026 में राज्य में सामान्य औसत बारिश 189।5mm की जगह महज 86।5mm (सामान्य वर्षापात से 54% कम) बारिश हुई है। जून महीने में सिर्फ दुमका ही ऐसा जिला रहा जहां

वर्षा सामान्य रहा, जबकि अन्य 23 जिलों में जून महीने में सामान्य से कम बारिश ही हुई है। साहिबगंज, गढ़वा, चतरा, गोड्डा, कोडरमा, पलामू जिले की स्थिति तो बेहद खराब है। इन जिलों में सामान्य वर्षापात से 77% से 99% तक कम बारिश हुई है। जून 2026 में झारखंड के 24 में से 23 जिलों में सामान्य से कम बारिश होने की परेशान करने वाली खबर के बाद अच्छी खबर यह है कि मौसम केंद्र,रांची ने अपने पूर्वानुमान में अगले 10 दिनों तक राज्य में अच्छी बारिश होने की जानकारी दी है। वरीय मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 03 जुलाई को उत्तर बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से अगले करीब 10 दिनों तक राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी वर्षा होगी।

बिहारशरीफ में बैंक ऑफ बड़ौदा की नई शाखा का शुभारंभ

जिले की सातवीं और शहर की चौथी शाखा शुरू

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

बिहारशरीफ। नालंदा जिले के लोगों के लिए बैंकिंग सुविधाओं का दायरा और बढ़ गया है। बिहारशरीफ के किसान कॉलेज के सामने बैंक ऑफ बड़ौदा की नई शाखा का भव्य उद्घाटन किया गया। यह बिहारशरीफ की चैथी तथा पूरे नालंदा जिले की सातवीं शाखा है। नई शाखा के खुलने से स्थानीय लोगों, छात्रों, व्यवसायियों और ग्राहकों को आधुनिक बैंकिंग सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी।शाखा का उद्घाटन बैंक के महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख (पटना अंचल) सुमंत सुब्रत कुमार

स्वाईं ने फीता काटकर किया। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रमुख (गया क्षेत्र) संजय कुमार तिवारी, उप क्षेत्रीय प्रमुख (बिहार क्षेत्र) प्रभात कुमार श्रीवास्तव समेत बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।महाप्रबंधक सुब्रत कुमार स्वाईं ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों को बेहतर, सुरक्षित और आधुनिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि नई शाखा के माध्यम से बचत खाता, ऋण, एटीएम, डिजिटल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि नई शाखा क्षेत्र के लोगों को तेज, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के साथ बैंक की पहुंच को भी और मजबूत करेगी।

31 जुलाई तक हर हाल में पूरी करें सीएमआर आपूर्ति

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

बिहारशरीफ। जिला पदाधिकारी उदिता सिंह ने खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान अधिप्राप्ति एवं कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) आपूर्ति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को लंबित कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा में बताया गया कि जिले में 1,32,967.46 मीट्रिक टन धान की खरीद के बदले 90,285.19 मीट्रिक टन सीएमआर राज्य खाद्य निगम को दिया जाना है। इसके विरुद्ध अब तक 74,189.757 मीट्रिक टन (82.17 प्रतिशत) सीएमआर प्राप्त

हुआ है, जबकि 16,095.433 मीट्रिक टन सीएमआर की आपूर्ति शेष है। भारत सरकार ने सीएमआर जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है।बैठक में बताया गया कि 229 पैक्स एवं व्यापार मंडलों में से 77 समितियां शत-प्रतिशत सीएमआर जमा कर चुकी हैं, जबकि 39 समितियों पर पांच लॉट से अधिक सीएमआर लंबित है। डीएम ने इन समितियों की अनुमंडलवार सूची तैयार कर एसडीओ को नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। साथ ही जिला प्रबंधक को 15 जुलाई तक शत-प्रतिशत सीएमआर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रखंडवार दैनिक लक्ष्य निर्धारित करने को कहा। डीएम ने स्पष्ट किया कि निरीक्षण के दौरान किसी भी स्तर पर गड़बड़ी मिलने पर संबंधित समिति, गोदाम प्रबंधक और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जवाबदेही तय की जाएगी।

रजरप्पा पिकनिक से लौट रहे राजगीर के युवक की संदिग्ध मौत

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

बिहारशरीफ। राजगीर थाना क्षेत्र के पिलखी गांव निवासी 38 वर्षीय सोनू रविदास की झारखंड के बरही में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह राजगीर से 20-25 लोगों के समूह के साथ टूरिस्ट बस से रजरप्पा में पिकनिक और पूजा-अर्चना के लिए गए थे। परिजनों के अनुसार, बरही के एक होटल में भोजन करने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए हजारीबाग ले जाने के दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई। सोनू रविदास राजगीर में एक डॉक्टर के यहां कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे। मृतक के साढ़ू वीरेंद्र कुमार रवि ने बताया कि बुधवार की रात करीब 11ः 30 बजे सोनू से फोन पर बातचीत हुई थी और तब वह पूरी तरह स्वस्थ थे। बरही के पास स्थित शिवम होटल में भोजन करने के कुछ देर बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें बरही सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पूर्व रेलवे

निविदा सूचना सं. एसजी.निविदा/डीएसटीई/एसडीएएच/622, दिनांक 01.07.2026, वरिष्ठ डीएसटीई, पूर्व रेलवे, सियालदह, दूसरी मंजिल, कंट्रोल बिल्डिंग, डीआरएम बिल्डिंग, काइजर स्ट्रीट, सियालदह, कोलकाता-700014 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है: **ई-निविदा सं.: एसडीएसटीई/एसआईजी/टी/12/26-27/आरआरएसके। कार्य का नाम एवं इसका स्थान:** उम्र सह स्थिति के आधार पर नए आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन (2023) से पुराने आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन (2004) के आईपीएस का प्रतिस्थापन। **निविदा मूल्य:** रु.7,44,25,962.10, **बयाना राशि/बोली प्रतिभूति जमा की जाएगी:** रु.14,88,500/- **निविदा कागजात का मूल्य :** शून्य। **कार्य की समापन अवधि:** 12 माह। **निविदा जमा देने की प्रारंभिक तिथि:** 14.07.2026, **निविदा जमा देने की अंतिम तिथि:** 28.07.2026 को 14.00 बजे तक। **निविदा बोली के खोलने की तिथि:** 28.07.2026 को 14.30 बजे। **विवरण यहाँ से देखा जा सकता है: www.ireps.gov.in तकनीकी पात्रता मानदंड:** निविदाकार ने निविदा आमंत्रण से पूर्व महीने के अंतिम दिन को समाप्त, पिछले 07 (सात) वर्षों के दौरान, निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक कार्य का सफलतापूर्वक पूरा या पर्याप्त रूप से निष्पादन किया है: (i) तीन समरूप कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत निविदा के विज्ञापित मूल्य के 30% की समान राशि से कम न हो, या (ii) दो समरूप कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत निविदा के विज्ञापित मूल्य के 40% की समान राशि से कम न हो, या (iii) एक समरूप कार्य जिसकी लागत निविदा के विज्ञापित मूल्य के 60% की समान राशि से कम न हो। **वित्तीय पात्रता मानदंड:** निविदाकार का न्यूनतम औसत वार्षिक ठेकाजनित कारोबार V/N या 'V' होना चाहिए, जो भी कम हो, जहाँ V = निविदा का विज्ञापित मूल्य करोड़ रुपये में, N = कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या जिसके लिए बोलियाँ आमंत्रित की गई हैं। औसत वार्षिक ठेकाजनित कारोबार की गणना लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में "कुल ठेकाजनित भुगतान" के औसत के रूप में की जाएगी। तथापि, यदि पिछले वर्ष का तुलन-पत्र अभी तैयार किया जाना है/लेखापरीक्षित नहीं है, तो औसत वार्षिक ठेकाजनित कारोबार की गणना के लिए चौथे पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र को विचार में लिया जाएगा। निविदाकार जीसीसी 2022 के अनेक्सर-VIबी (मौजूदा निविदा कागजात का फॉर्म-6) के अनुसार आवश्यक जानकारी के साथ सनदी लेखापाल द्वारा यथा प्रमाणित लेखापरीक्षित तुलन पत्र की प्रतियाँ/लेखापरीक्षित तुलन पत्र द्वारा यथा समर्थित सनदी लेखापाल से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। **जमा किए जाने वाले अन्य कागजात:** निविदा कागजात में उल्लिखित अनुसार। **समरूप कार्य की प्रकृति:** कोई भी एस एंड डी कार्य जिसमें शामिल है पावर सप्लाई सिस्टम (आईपीएस/बैटरी चार्जर) की आपूर्ति, स्थापना, आरंभ। **टिप्पणी:** निविदाकार अपने निविदा प्रस्ताव के साथ निविदा कागजात में उल्लिखित पात्रता मानदंड को पूरा करने के अपने दावे के समर्थन में कागजात प्रस्तुत करेंगे। निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्रों के समर्थन में कागजातों/प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपि का प्रत्येक पृष्ठ निविदाकार या निविदाकारी फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्व-सत्यापित/डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा। स्व-सत्यापन में हस्ताक्षर, मुहर और तिथि (प्रत्येक पृष्ठ पर) शामिल होंगे।

SDAH-111/2026-27

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पूर्व रेलवे

सं.: ओ-एसी-टी-96 से 97-26-27 (खुली), दिनांक 01.07.2026, मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे, आसनसोल मंडल, स्टेशन रोड, आसनसोल, पिन-713301 द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदाएं (खुली) आमंत्रित की जाती हैं: **क्रम सं. 1, केस सं. ओ-एसी-टी-96-26-27, कार्य का नाम:** डीईएन/4/आसनसोल के अधिकार क्षेत्र में भीमगड़ा- पलस्थली खंड में ब्रिज नं. 3 एवं 15, बखतारनगर-अण्डाल डीएसईवाई खंड में ब्रिज नं. 7 एवं 12 तथा अण्डाल-सोनाचारा खंड के बीच किमी 3/27-29 में ब्रिज नं. 7 के जैकेटिंग, सुदृढ़ीकरण एवं अन्य सहायक कार्यों के लिए खुली निविदा। **निविदा मूल्य :** रु.8,00,64,582.08, **बयाना राशि :** रु. 16,01,300/- **क्रम सं. 2, केस सं. ओ-एसी-टी-97-26-27, कार्य का नाम:** डीईएन/4/आसनसोल के अधिकार क्षेत्र में अण्डाल यार्ड, हजरतपुर साइडिंग एवं उखरा में सीटीआर(एस), टीआरआर(एस) तथा डीएसईवाई में डायमंड क्रॉसिंग के रूपांतरण और शंटिंग नेक के विस्तार के साथ अन्य सहायक कार्यों के लिए खुली निविदा। **निविदा मूल्य :** रु. 3,24,54,221.61, **बयाना राशि:** रु. 6,49,100/- **कार्य की समापन अवधि:** 12 माह (प्रत्येक हेतु)। **बंद होने की तिथि और समय:** दिनांक 27.07.2026 को 12.00 बजे। संपूर्ण विवरण रेलवे की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** में देखा जा सकता है।

ASN-160/2026-27

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

दक्षिण पूर्व रेलवे-निविदा

भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से मंडल विद्युत अभियंता (जी)/आद्रा, दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा यहां नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार विद्युतीय कार्यों के निष्पादन के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं: **क्रमांक एवं निविदा सूचना सं., कार्य का विवरण, निविदा मूल्य:** (1) **ईलेक्ट-जी-एडीए-2026-09, दिनांक 24.06.2026;** (क) सहायक मंडल अभियंता/पुरुलिया, (ख) सहायक मंडल अभियंता/पूर्व, (ग) सहायक मंडल अभियंता/बोकारो स्टील सिटी, (घ) मंडल अभियंता/पूर्व/आद्रा के अधिकार क्षेत्र के अधीन लेवल क्रॉसिंग के साथ पहुंच सड़क तथा लेवल क्रॉसिंग की रबड़युक्त सतह के सुधार तथा जल आपूर्ति की व्यस्था तथा लेवल क्रॉसिंग गेट में एटी की आपूर्ति के लिए विद्युतीय कार्य; रु. 1,05,64,665/-। (2) **ईलेक्ट-जी-एडीए-2026-10, दिनांक 24.06.2026;** आद्रा मंडल में (क) वरिष्ठ अनुभाग अभियंता/सिग्नल/बांकुड़ा के अनुभाग में 4 अदद लेवल क्रॉसिंग गेटों (बीआर-67, बीआर-101, बीआर-10 एवं बीआर-58) की इंटरलॉकिंग एवं (ख) वरिष्ठ अनुभाग अभियंता/सिग्नल/आद्रा के अनुभाग में 2 अदद लेवल क्रॉसिंग गेटों (आरसी-5 एवं डीके-2) की इंटरलॉकिंग के लिए विद्युतीय कार्य; रु. 34,84,730/-। (3) **ईलेक्ट-जी-एडीए-2026-11, दिनांक 24.06.2026;** आद्रा मंडल के तहत भागा (2 अदद), मधुकुंडा (2 अदद) तथा ओंडाग्राम (3 अदद) स्टेशनों में 07 अदद लिफ्टों के प्रावधान के लिए विद्युतीय कार्य; रु. 17,19,759/-। **ई-निविदाओं के बंद होने की तारीख एवं समय** प्रत्येक के लिए 17.07.2026 को दोपहर 12.00 बजे है तथा **निविदाएं** दिनांक 17.07.2026 को दोपहर 12.30 बजे के उपरांत **खोली** जाएंगी। उपरोक्त ई-निविदाओं का विवरण वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देखे जा सकते हैं। **(PR-410)**

पूर्व रेलवे

मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे, हावड़ा मंडल, नई डीआरएम बिल्डिंग, चतुर्थ तल, रेल म्यूजियम के पास, हावड़ा-711101 (**वरिष्ठ डीईएन/1/हावड़ा** के कार्यक्षेत्र हेतु) निम्नलिखित कार्य के लिए सिंचाई/सीपीडब्ल्यूडी/एसईबी/एमईएस या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से पंजीकृत समेत समप्रकृति के कार्य के अनुभवी एवं अपेक्षित वित्तीय संपन्न निविदाकारों से निम्नलिखित ई-निविदा ऑनलाइन आमंत्रित करते हैं: **एनआईटी सं.137_2026-27, कार्य का विवरण** : वरिष्ठ डीईएन/1/हावड़ा के अधिकार क्षेत्र में लेवल क्रॉसिंग गेट के हाइट गेज का मानकीकरण। **अनुमानित मूल्य :** रु.2,14,86,384.93, **बयाना राशि:** रु. 4,29,700/-, **निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु.):** शून्य। **समापन अवधि:** 09 (नौ) माह। यदि निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित अंतिम तिथि को किसी भी कारण से अवकाश/बंद/हड़ताल घोषित किया जाता है, तो ऑनलाइन निविदा की अंतिम तिथि नहीं बदली जाएगी क्योंकि आईआरईपीएस की वेबसाइट में किया गया आवेदन, निविदा की अंतिम तिथि और समय के बाद किसी भी प्रस्ताव को जमा करने की अनुमति नहीं देता है। तथापि निविदाओं का ऑनलाइन खोला जाना अगले कार्यदिवस में किया जाएगा। **निविदा की अंतिम तिथि और समय** : दिनांक 16.07.2026 को 14.00 बजे। निविदा का विवरण वेबसाइट: **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदाकारों से अनुरोध किया जाता है कि अपने प्रस्ताव को उपर्युक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करें। ईएमडी और टीडीसी का भुगतान : ई-निविदा प्रणाली के मामले में बयाना राशि जमा (ईएमडी) और निविदा कागजात की लागत (टीडीसी) का भुगतान, केवल नेट बैंकिंग या पेमेंट गेटवे के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। कोई मैनुअल प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा।।

HWH-185/2026-27

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

अवर सचिव को निगरानी ने रंगे हाथ दबोचा

एरियर भुगतान के एवज में मांगी थी घूस

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

पटना। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। ब्यूरो की मुख्यालय टीम ने शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग में तैनात अवर सचिव अमोद मिश्रा को 20 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है । यह गिरफ्तारी राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र स्थित मिनिस्टर इन्क्लेव मोड़ के पास से की गई है ।

नालंदा जिले के बिहार शरीफ थाना अंतर्गत नई सराय के रहने वाले उमा शंकर ने निगरानी ब्यूरो में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि अवर सचिव अमोद मिश्रा ने उनके एरियर का भुगतान करने के बदले में रिश्वत की

मांग की है। शिकायत मिलने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मामले का गोपनीय सत्यापन कराया। जब सत्यापन में आरोपी अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण सही पाया गया तो जुलाई की पहली तारीख को निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस उपाधीक्षक श्याम बाबू प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेष धावा दल का गठन किया गया।

विशेष धावा दल ने रणनीति के तहत जाल बिछाया और गुरुवार को अवर सचिव को 20 हजार रुपये की घूस की रकम के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। निगरानी ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त अमोद मिश्रा से मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे का अनुसंधान जारी है। पूछताछ के बाद आरोपी को पटना स्थित विशेष निगरानी न्यायालय में पेश किया जाएगा।

भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अभियान के तहत वर्ष 2026 में यह 79वीं प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इनमें से 74 मामले ट्रैप (जाल बिछाकर पकड़ने) से संबंधित हैं, जिनमें अब तक कुल 74 अभियुक्तों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया जा चुका है। इस साल अब तक कुल 28,05,300 की रिश्वत राशि बरामद की जा चुकी है। वर्ष 2025 में निगरानी ने कुल 101 ट्रैप कांड दर्ज किए थे और 37,80,300 की रिश्वत राशि बरामद की थी।

खून से लथपथ वृद्ध की लाश बरामद

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

छपरा। सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में गुरुवार सुबह एक 70 वर्षीय वृद्ध की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। वृद्ध का खून से लथपथ शव उनके घर के बाहर पड़ा मिला। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या करने के बाद शव को घर के बाहर फेंक दिया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और मातम का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मृतक की पहचान माधोपुर बड़ा गांव निवासी 70 वर्षीय शिवजी सहनी के रूप में हुई है। गुरुवार सुबह उनका शव घर के बाहर खून से लथपथ हालत में मिला। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और घटना की जानकारी तरैया थाना पुलिस को दी गई।

महाराष्ट्र पुलिस ने की हाजीपुर साइबर कैफे में छापेमारी

- खंगाले गए डिजिटल साक्ष्य
- कार्रवाई से इलाके में हड़कंप

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

पटना। महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच अब बिहार के वैशाली जिले तक पहुंच गई है। बुधवार रात महाराष्ट्र पुलिस की एक विशेष टीम ने हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के कचहरी रोड स्थित एक साइबर कैफे में अचानक छापेमारी की। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और देर रात तक पुलिस की गतिविधियां जारी रहीं।

जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र पुलिस के आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों की टीम स्थानीय नगर थाना पुलिस के सहयोग से कचहरी रोड पहुंची। पुलिस ने साइबर कैफे को चारों ओर से घेर लिया और संचालक से लंबे समय तक गहन पूछताछ की। इस दौरान कैफे में मौजूद कंप्यूटर, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की भी बारीकी से जांच की गई।

सूत्रों के मुताबिक, यह छापेमारी टीईटी परीक्षा से जुड़े फर्जी पहचान पत्र, जाली प्रमाण पत्र तैयार करने और ऑनलाइन धोखाधड़ी के संदिग्ध नेटवर्क की जांच के सिलसिले में की गई है। हालांकि जांच टीम के अधिकारियों ने फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। उनका कहना है कि जांच अभी जारी है और पूरी जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

इस संयुक्त कार्रवाई में नगर थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रही। थाना अध्यक्ष ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस ने स्थानीय स्तर पर संपर्क कर सहयोग मांगा था, जिसके बाद संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की गई।

करीब एक घंटे से अधिक समय तक चली इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने साइबर कैफे से जुड़े कई डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच की। जांच एजेंसियां डिजिटल गतिविधियों और पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए अलग-अलग स्थानों पर भी तलाशी अभियान चला रही हैं।

जांच एजेंसियां आरोपियों के लैपटॉप, मोबाइल फोन, ईमेल और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की मदद से पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं। अधिकारियों का प्रयास है कि इस कथित फर्जीवाड़े से जुड़े सभी लोगों की पहचान कर पूरे गिरोह का खुलासा किया जा सके।

तालाब में डूबने से आठवीं की दो छात्राओं की मौत

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

छपरा। बिहार के सारण जिले में दोस्ती की एक ऐसी दर्दनाक कहानी सामने आई है, जिसने पूरे गांव को गम में डुबो दिया। अमनौर थाना क्षेत्र के अमनौर कल्याण पंचायत के नरसिंहभानपुर गांव में बुधवार शाम तालाब में डूबने से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली दो सहेलियों की मौत हो गई। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। साथ पढ़ना, साथ स्कूल जाना और हर जगह एक-दूसरे का साथ निभाने वाली दोनों सहेलियों ने जिंदगी की आखिरी यात्रा भी साथ ही पूरी कर ली। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और दोनों परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है।

मृत छात्राओं की पहचान दशरथ प्रसाद की बेटी आंचल कुमारी और दिनेश प्रसाद की बेटी खुशबू कुमारी के रूप में हुई है। दोनों नरसिंहभानपुर मध्य विद्यालय की आठवीं कक्षा की छात्राएं थीं और बचपन से एक-दूसरे की बेहद करीबी दोस्त थीं।

परिजनों ने बताया कि गांव के एक पड़ोसी के शादी समारोह में शामिल होने के लिए दोनों छात्राओं के माता-पिता मशरक गए हुए थे। इसी कारण आंचल उस दिन स्कूल नहीं गई। आंचल के स्कूल नहीं जाने पर उसकी सबसे करीबी दोस्त खुशबू ने भी स्कूल जाने का फैसला बदल दिया। गांव के लोगों के अनुसार, दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि अगर एक स्कूल नहीं जाती थी तो दूसरी भी स्कूल नहीं जाती थी।

घर से निकलने से पहले आंचल ने अपनी दादी से 10 रुपये मांगे और कहा कि वह दुकान से कुछ खरीदकर खाएगी। इसके बाद वह घर से बाहर निकल गई। उसी समय उसकी बड़ी बहन हंसा गांव के शिव मंदिर के सामने स्थित तालाब में स्नान कर रही थी। आंचल और

खुशबू भी वहां पहुंच गईं और दोनों तालाब में नहाने लगीं। कुछ देर बाद हंसा तालाब से बाहर निकल आई, लेकिन आंचल और खुशबू नहाते-नहाते गहरे पानी में चली गईं। दोनों डूबने लगीं और खुद को बचा नहीं सकीं।

हंसा ने दोनों को बचाने की पूरी कोशिश की। पहले उसने रस्सी फेंककर उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन रस्सी छोटी पड़ गई। इसके बाद वह दौड़कर गांव पहुंची और शोर मचाकर लोगों को बुलाया।

रोड टैक्स में बढ़ोतरी जनविरोधी फैसला

गया। लोक समिति के राष्ट्रीय संयोजक कौशल गणेश आजाद और बिहार के महामंत्री शिवजी सिंह ने एक संयुक्त बयान जारी कर बिहार में रोड टैक्स में बेतहाशा बढ़ोतरी की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार के इस फैसले से लोगों की यात्रा दूभर हो जाएगी। नेशनल हाईवे की तर्ज पर बिहार में स्टेट हाइवे और पुलों पर भी टैक्स 1.25 से लेकर 8.10 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से लगेगा, जिससे यात्रा बहुत महंगी हो जाएगी और आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा बिहार के वृद्धों को समय पर पेंशन नहीं मिल रहा है जिससे उनको परेशानी हो रही है। बिहार के युवा बेरोजगारी की मार से त्रस्त हैं। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से सभी जरूरी समान की कीमतें बढ़ गयी हैं, यात्रा महंगी हो गयी है। ऐसे में स्टेट हाइवे और पुलों पर टैक्स वसूलना बिहार वासियों के साथ ज्यादती है। बिहार सरकार का यह फैसला जनविरोधी है। नेता द्वय ने बिहार सरकार से स्टेट हाइवे और पुलों पर लगे सभी तरह के टैक्स को तत्काल वापस लेने की मांग की है।

एक ही परिवार की मां-बेटी और पतोहू को मिला आवास योजना का लाभ

आरटीआई से हुआ खुलासा, खाते में भेजी गयी एक-एक लाख की राशि

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

पूर्णिया। नगर परिषद कसबा में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ असहाय गरीबों के बदले पार्षद के परिजनों को खुलेआम मिल रहा है। इस खुलासे से प्रधानमंत्री आवास योजना पर प्रश्नचिह्न लग गया है। पूरा मामला नगर परिषद कसबा के वार्ड संख्या-2 का बताया जा रहा है। पूरे मामले का खुलासा नगर परिषद के वार्ड संख्या-2 के पार्क टोला निवासी कोकिल कुमार के द्वारा आरटीआई से मांगी सूचना के जवाब के बाद हुआ, जिसमें वार्ड संख्या-2 से कुल 217 लाभुकों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था।

इनमें से 15 लाभुकों का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हुआ। इन सभी 15 लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में 1-1 लाख रुपए की राशि उनके बैंक खातों भेज भी दी गई है। इन सभी 15 लाभुकों में से 4 लाभुक वार्ड संख्या के पार्षद मो. इफ्तेखार आलम के परिजन खुद हैं।

लाभुकों की चयनित सूची में पहले स्थान पर वार्ड

पार्षद मो इफ्तेखार आलम की मां अख्तरी बेगम, दूसरे स्थान पर वार्ड पार्षद की सगी बहन रोशन आरा, जबकि तीसरे स्थान पर वार्ड पार्षद सगे भाई की पत्नी सना परवीन तथा सूची के 13वें स्थान पर वार्ड पार्षद का फुफेरे भाई मो समीम का नाम दर्ज है।

इन सभी लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में 1 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रतीक्षा सूची में वार्ड पार्षद की सास जलिसा बेगम पहले स्थान पर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जनप्रतिनिधि ही सरकारी योजना का लाभ आम जनता को ना दिला कर खुद ही अपने परिवारों को लाभ देते रहेंगे तो आम गरीब लोगों का एवं आम जनता की आवाज कौन उठाएगा।

नगर परिषद कसबा के प्रधानमंत्री आवास योजना के जेई अमित कुमार ने बताया कि जो योग्य लाभुक है, उनका ही सूची में नाम है। कुल 15 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त प्रदान की गई है, जबकि प्रतीक्षा सूची में 31 लाभुकों का नाम शामिल है।

इस संबंध में जब नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने कोई जानकारी नहीं है।

अगर पार्षद के परिवार के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना की सारे शर्तों को नियमानुसार पूरा करते हैं तो वो योग्य लाभुक कहलाएंगे।

ईओयू सॉल्वरों के मोबाइल का खंगाल रहा कॉल डिटेल

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

लखीसराय। गत 21 जून को उजागर हुए नीट यूजी पुनर्परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले की जांच में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने अपनी रणनीति में अहम बदलाव किया है। गुरुवार को ईओयू की टीम पहले जेल में बंद सॉल्वरों को रिमांड पर लेने की तैयारी में थी, लेकिन अंतिम समय में जांच की दिशा बदलते हुए पहले डिजिटल साक्ष्य मजबूत करने का निर्णय लिया गया।

इसके तहत टीम ने तीनों कांडों के अनुसंधान पदाधिकारियों के साथ मिलकर जब्त मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और अन्य तकनीकी जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, जांच के दायरे में लखीसराय मंडल कारा में बंद 12 मेडिकल छात्र (सॉल्वर), एक मूल परीक्षार्थी और 17 बायोमेट्रिक कर्मियों के मोबाइल फोन शामिल हैं। इन मोबाइलों की काल हिस्ट्री, चैट रिकॉर्ड, लोकेशन, आपसी संपर्क, डिजिटल भुगतान, बैंकिंग एवं यूपीआई लेनदेन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है।

जांच के दौरान कुछ नए तकनीकी इनपुट और संदिग्ध संपर्क भी सामने आए हैं, जिन्हें फिलहाल गोपनीय रखा गया है, ताकि जांच प्रभावित न हो।ईओयू सूत्रों के मुताबिक, मुख्यालय स्तर से निर्देश मिला है कि रिमांड पर लेने से पहले उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों का पूरा विश्लेषण कर लिया जाए। इसके बाद आरोपितों से पूछताछ के दौरान उनके बयानों का सीडीआर, चैट और अन्य इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों से मिलान किया जाएगा। इससे पूछताछ अधिक प्रभावी होगी और विरोधाभासी बयानों की तुरंत पुष्टि की जा सकेगी।

जांच एजेंसी का मानना है कि डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद होने वाली पूछताछ से पूरे फर्जीवाड़ा नेटवर्क, फरार मास्टरमाइंड, आर्थिक लेनदेन के स्रोत और परीक्षा में शामिल अन्य सहयोगियों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। यही वजह है कि ईओयू अब तकनीकी जांच को प्राथमिकता देते हुए पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

एक ही परिवार के 10 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

गोपालगंज। जिले से फूड पॉइजनिंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कीरतपुरा गांव में फटे हुए दूध से बना खाद्य पदार्थ खाने के बाद एक ही परिवार के 10 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। बीमारों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सभी को इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। परिजनों के अनुसार, अनिल सहनी और रजानति देवी के घर में फटे हुए दूध से एक खाद्य पदार्थ तैयार किया गया था। परिवार के सभी लोगों ने उसे खाया। खाने के कुछ ही देर बाद एक-एक कर सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। सबसे पहले बच्चों ने पेट में तेज दर्द और उल्टी की शिकायत की। इसके बाद महिलाओं और अन्य सदस्यों को भी चक्कर आने लगे और वे कमजोरी महसूस करने लगे। स्थिति गंभीर होते देख परिजन बिना देर किए सभी को गोपालगंज सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। इस घटना में सबसे अधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं। बीमार होने वालों में प्रिया कुमारी (14 वर्ष), सिमरन कुमारी (11 वर्ष), प्रियांशु कुमारी (12 वर्ष), ऋषभ कुमार (1 वर्ष), अभिराज कुमार (2 वर्ष), मोनालिसा

कुमारी (11 वर्ष), ऋतिक कुमार (5 वर्ष), अतुल कुमार (9 वर्ष), मनीषा (30 वर्ष) और रजानति देवी (35 वर्ष) शामिल हैं।

सदर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में तैनात चिकित्सक डॉ. पंकज कुमार ने बताया कि अस्पताल पहुंचने के समय मरीजों की हालत चिंताजनक थी, लेकिन समय पर इलाज शुरू होने से अब सभी की स्थिति स्थिर है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में यह मामला फूड पॉइजनिंग का प्रतीत हो रहा है। आशंका है कि फटे हुए दूध में हानिकारक बैक्टीरिया पनपने के कारण सभी की तबीयत बिगड़ी। फिलहाल सभी मरीज खतरे से बाहर हैं और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। सटीक कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक मेडिकल जांच कराई जा रही है।

मेले में नहीं सतायेगी बिजली

मुंगेर। श्रावणी मेला के दौरान कच्ची कांवरिया पथ पर बिजली आपूर्ति निर्बाध रहेगी। इसे लेकर विभाग आपूर्ति में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है। विभाग के वरीय अधिकारियों ने जिला सीमा स्थित कंमराय मोड़ से असरगंज के खूबलाल महाविद्यालय तक कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण कर विद्युत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण दल में पटना से आए मुख्य अभियंता राजकुमार, मुंगेर कार्यपालक अभियंता दिलीप कुमार, भागलपुर के कार्यपालक अभियंता पंकज कुमार, तारापुर अनुमंडल के सहायक विद्युत अभियंता रविंद्र कुमार तथा असरगंज के कनीय अभियंता पंकज कुमार शामिल थे। निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता ने कांवरिया पथ किनारे ट्रांसफार्मरों की घेराबंदी सुनिश्चित करने, हाईटेंशन तारों पर गार्ड वायर लगाने तथा जहां-जहां वाहन पार्किंग और कांवरिया पथ का सड़क से क्रासिंग है, वहां विद्युत लाइनों की विशेष जांच कर आवश्यक मरम्मत कराने का निर्देश दिया।

सर्पदंश से गई महिला की जान

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

जामताड़ा। जामताड़ा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के आगमन और स्वागत का इंतजार किया जा रहा था। अस्पताल परिसर में कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थीं।

इसी बीच सदर प्रखंड की गोपालपुर पंचायत के दूधकेबड़ा गांव की निवासी सेंजली किस्कू, जोकि सर्पदंश से गंभीर हालत में बदहवाश हो चुकी थी।

उसे लेकर स्वजन टोटो से सदर अस्पताल पहुंचे। स्वजनों ने बताया कि मरीज की हालत गंभीर होने पर उन्होंने 108 एंबुलेंस सेवा पर कई बार फोन किया, लेकिन कई बार प्रयास के बाद भी कॉल नहीं लग सका।

काफी प्रयास के बाद भी एंबुलेंस उपलब्ध नहीं होने पर मजबूरी में टोटो से मरीज को अस्पताल लाना पड़ा, लेकिन महिला ने इलाज के दौरान कुछ ही देर बाद दम तोड़ दिया।

एक ओर स्वास्थ्य मंत्री के स्वागत और कार्यक्रम की तैयारियों में अस्पताल प्रशासन व्यस्त था, वहीं दूसरी ओर गंभीर मरीज का टोटो से अस्पताल पहुंचना, वहां मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया।

लोगों ने सवाल उठाया कि जब जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री का कार्यक्रम हो रहा था, तब भी एक गंभीर मरीज को समय पर एंबुलेंस सुविधा क्यों नहीं मिल सकी। इतना ही नहीं सदर अस्पताल के तमाम सीनियर डाक्टर भी गंभीर हालत में पहुंची आदिवासी महिला मरीज का इलाज करने और हाल जानने की बजाय कार्यक्रम में ही व्यस्त रह गए।

यह घटना जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था और 108 एम्बुलेंस सेवा की कार्यप्रणाली और सदर अस्पताल प्रबंधन की ओर से इलाज में बरती जा रही गंभीरता पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी दावों के बावजूद आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में अब भी कई खामियां हैं।

जरूरत इस बात की है कि 108 एंबुलेंस सेवा को प्रभावी बनाया जाए, ताकि गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिल सके और उन्हें टोटो जैसे साधनों का सहारा न लेना पड़े। साथ ही सदर अस्पताल में अबतक आईसीयू की सेवा उपलब्ध ना हो पाने की वजह से भी गंभीर हालत में पहुंच रहे मरीजों को रेफर होने के चक्कर में अपनी जान गंवानी पड़ रही है।

रास्ता बंद होने से भारत-नेपाल सीमा पर ट्यूबवेल के सहारे किसान कर रहे धान रोपनी स्थिति तनावपूर्ण, लोगों ने काटा बवाल

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

अररिया। भारत-नेपाल सीमा पर गुरुवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, जब नेपाल के मोरंग जिले के रानी भंसार क्षेत्र में स्थित बैरियर संख्या-03 से आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई। इस निर्णय का स्थानीय व्यापारियों और सीमावर्ती नागरिकों ने विरोध किया। विरोध-प्रदर्शन के बाद नेपाल प्रशासन ने बंद मार्ग को पुनः खोल दिया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो गई।

जानकारी के अनुसार, जोगबनी से सटे रानी भंसार क्षेत्र का यह मार्ग वर्षों से दोनों देशों के सीमावर्ती नागरिकों के लिए आवागमन का प्रमुख रास्ता रहा है। इस मार्ग का उपयोग स्थानीय लोग दैनिक जरूरतों, छोटे कारोबार और सामाजिक गतिविधियों के लिए करते हैं।

गुरुवार को आम नागरिकों की आवाजाही बंद किए जाने की सूचना मिलते ही अरुण सिनेमाझदुर्गा मंदिर मार्ग के दर्जनों दुकानदार और स्थानीय लोग सीमा क्षेत्र में एकत्र हो गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सीमा क्षेत्र की सुरक्षा और तस्करी पर रोक लगाना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके नाम पर आम लोगों की आवाजाही रोक देना उचित नहीं है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस मार्ग पर निर्भर सैकड़ों छोटे दुकानदारों और व्यवसायियों की आजीविका सीधे प्रभावित होगी। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि वर्षों से यह रास्ता भारत और नेपाल के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का महत्वपूर्ण माध्यम रहा है।

प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नेपाल प्रशासन के फैसले पर नाराजगी जताई। स्थिति को देखते हुए संबंधित अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। इसके बाद आम लोगों के लिए मार्ग को फिर से खोल दिया गया, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सीमा पर प्रभावी निगरानी और तस्करी रोकने के उपाय जरूरी हैं, लेकिन ऐसे निर्णयों में सीमावर्ती आबादी के हितों और उनकी आजीविका का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लोगों ने प्रशासन से भविष्य में ऐसे फैसले लेने से पहले स्थानीय प्रतिनिधियों और व्यापारियों से बातचीत करने करने की मांग की है।

महिला की लाश बरामद

सहरसा। जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बनमा ईटहरी थाना क्षेत्र के मनिया स्थित तिलावे नदी से गुरुवार सुबह 45 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आक्रोशित लोगों ने सोनवर्षा-महेशखुट मुख्य मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया। करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद सिमरी बख्तियारपुर के एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर के आश्वासन पर लोगों ने सड़क जाम समाप्त कर दिया।

मृतका की पहचान बनमा ईटहरी थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या-4 निवासी मीना देवी, पति नरेश यादव के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि मीना देवी बुधवार शाम करीब चार बजे घर से निकली थीं और उसके बाद से लापता थीं। परिवार ने काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका।

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

आरा। भोजपुर जिले में मई माह में 49.70 मिमी वर्षा हुई, जो सामान्य वर्षा से 173 प्रतिशत अधिक रही। इसके विपरीत जून माह में वर्षा का आंकड़ा सामान्य से काफी कम रहा। इससे किसानों को निराशा हुई। जून माह में 41.44 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 61.87 प्रतिशत कम है।

ऐसे में मई में अच्छी वर्षा के बावजूद जून में अपेक्षित बारिश नहीं होने से किसान अब आर्द्रा नक्षत्र में अच्छी वर्षा की उम्मीद लगाए बैठे हैं, ताकि धान की रोपनी का कार्य गति पकड़ सके। हालांकि, जिनके पौधे सूख रहे हैं, वे हौसला और जज्बा दिखाते हुए रोपनी शुरू कर रहे हैं।

मई माह की भीषण गर्मी और जून के अधिकांश दिनों तक तेज धूप के बाद अब आसमान में काले बादलों की आवाजाही और बीच-बीच में हो रही हल्की वर्षा ने किसानों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। किसान अब झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे हैं, ताकि धान की रोपनी समय पर शुरू की जा सके।

जिले के पीरो, तरारी और सहार प्रखंडों में रोहिणी नक्षत्र के दौरान डाले गए धान के बिचड़े (नर्सरी) अब पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। दूसरी ओर, नासरीगंज नहर से भोजपुर जिले के लिए लगातार 750 क्यूसेक सोन का पानी छोड़ा जा रहा है।

इसके कारण कोईलवर वितरणी समेत अन्य नहरों में पर्याप्त जल उपलब्ध है। इससे किसानों को सिंचाई में राहत मिली है, लेकिन रोपनी के लिए खेतों को

पूरी तरह तैयार करने के लिए अच्छी वर्षा की आवश्यकता बनी हुई है।

पीरो प्रखंड के तार गांव के किसान सिद्धनाथ सिंह ने बताया कि धान की नर्सरी तैयार हो चुकी है। किसान खेतों की जुताई, पाटा चलाने, मेड़ों की मरम्मत और पानी रोकने की व्यवस्था में जुटे हैं। गांवों में सुबह से शाम तक खेतों में किसानों की चहल-पहल बढ़ गई है। कहीं ट्रैक्टर से खेत तैयार किए जा रहे हैं तो कहीं अंतिम चरण की तैयारियां चल रही हैं।

जिला कृषि पदाधिकारी डॉ. नीरज कुमार ने बताया कि खरीफ मौसम की कृषि गतिविधियां तेज हो गई हैं। हल्की बारिश से खेतों में नमी बनी है, लेकिन बेहतर उत्पादन के लिए लगातार और अच्छी वर्षा आवश्यक है। उन्होंने किसानों से मौसम के अनुसार रोपनी की तैयारी पूरी रखने की अपील की है।

मानसून की सुस्त रफ्तार और पर्याप्त बारिश नहीं होने से संदेश प्रखंड क्षेत्र में किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। बारिश के अभाव में खेत सूखे पड़े हैं और कई जगह अकाल जैसे हालात बनने लगे हैं। ऐसे में किसान अपने स्तर पर प्रयास कर जज्बा और हिम्मत दिखाते हुए धान के बिचड़े को बचाने और रोपनी शुरू करने में जुट गए हैं।

वीबी-जी राम जी : 15 दिनों में रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता के दावेदार होंगे मजदूर : मंत्री

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

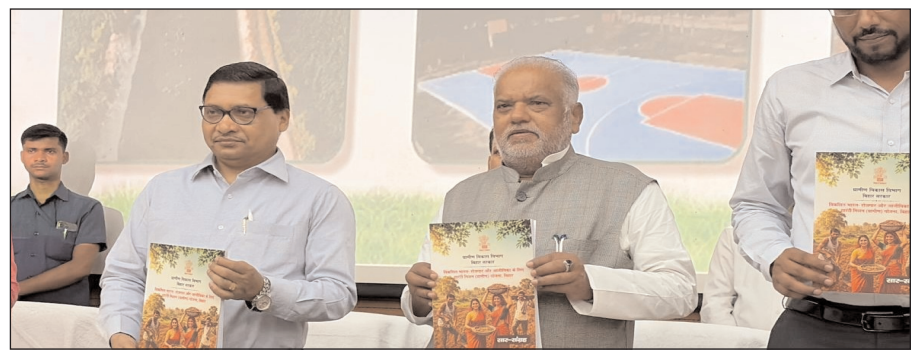

पटना। विकसित भारत-ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका गारंटी अधिनियम, 2025 (वीबी-जी राम जी) का गुरुवार को पटना के अभिवेशन भवन में भव्य शुभारंभ किया गया। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बतौर मुख्य अतिथि विभागीय मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मनरेगा के 20 वर्षों के लंबे सफर के बाद अब वीबी-जी राम जी के रूप में नई यात्रा की शुरुआत हुई है। उन्होंने बताया कि इस नई योजना में कामगारों को कई तरीके के लाभ होंगे। इसमें मुख्य रूप से रोजगार के लिए आवेदन करने वाले कामगारों को निर्धारित समय के भीतर (15 दिन) में काम नहीं दिए जाने पर उन्हें सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राज्य कैबिनेट की 1 जुलाई को हुई बैठक में विकसित भारत-जी राम जी योजना, बिहार 2026 के अंतर्गत अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपये रोजाना करने को मंजूरी दी गई। श्री कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रथम 30 दिनों के लिए बेरोजगारी भत्ते का दर एक चौथाई और शेष वित्तीय वर्ष के लिए आधा निर्धारित है। अकुशल कामगारों को भुगतान की गई बेरोजगारी भत्ता राशि का वहन राज्य सरकार करेगी।

और इसकी वसूली उत्तरदायी पदाधिकारी, अभिकरणों से 30 दिन के भीतर की जाएगी। मंत्री श्री कुमार ने बताया कि अकुशल मजदूरों का मास्टर रोल बंद होने पर मजदूरी का भुगतान 15 दिन में नहीं होने पर बकाया राशि का 0.05 फीसदी प्रतिदिन के हिसाब से स्वतः क्षतिपूर्ति देय होगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा में केंद्र सरकार मांग आधारित फंडिंग करती थी जबकि वीबी-जी राम जी में राज्यों की जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय और पिछड़ापन के आधार पर वित्तीय वर्ष के शुरुआत में ही प्रत्येक राज्य के लिए एक निश्चित बजट बनाने का प्रावधान है। वीबी-जी राम जी योजना में ग्राम पंचायतों को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं एवं विकास इंडेक्स, संसाधनों के आधार पर ए, बी, सी यानी तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विकेंद्रित और स्थानीय योजनाओं को बेहतर बनाने के साथ विकसित भारत 2047 के अनुरूप काम करना है। मंत्री श्री कुमार ने कार्यक्रम में उपस्थिति विभागों के पदाधिकारी, जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन ग्रामीण विकास के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि वीबी-जी राम जी योजना न सिर्फ हमारे प्रदेश के लिए बल्कि देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिक परिवारों के जीवन को बदलना की क्षमता रखती है। श्री कुमार के अनुसार मनरेगा और नई योजना वीबी-जी राम जी में कई भिन्नता है। उन्होंने बताया कि मनरेगा में जहां एक वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी मिलती थी वहीं इस नई योजना में अकुशल कामगारों को 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाएगी। कहा कि मनरेगा में अकुशल मजदूरी की समस्त राशि का वहन केंद्र सरकार करती थी, लेकिन वीबी-जी राम जी में अकुशल मजदूरी मद में 40 फीसदी राशि राज्य सरकार वहन करेगी। श्री कुमार ने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना में नौ महीने के लिए केंद्रांश के रूप में 6715 करोड़ 83 लाख रुपये आवंटित हुए हैं। इसी तरीके से इस योजना को मूर्तरूप देने की दिशा में इसी समयावधि के लिए राज्य सरकार ने 4477 करोड़ 22 लाख रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अभी तक राज्य भर में 20 करोड़ से भी अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में 1.25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में राज्य में किए गए पौधरोपण का ही नतीजा है कि आज हरित क्षेत्र नौ फीसदी से बढ़कर 16 फीसदी तक पहुंच चुका है। आने वाले समय में 33 फीसदी के लक्ष्य को छूने पर विभाग तेजी से काम कर रहा है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने अकुशल कामगारों के कल्याण और विकसित बिहार की अवधारणा को समर्पित वीबी-जी राम जी योजना के शुभारंभ करने पर मंत्री श्री कुमार का आभार व्यक्त किया। कहा कि ग्रामीण विकास के लिए योजना एक बहुत बड़ी पहल है। इस नई योजना में सिर्फ विकास की परिकल्पना है।

राम मंदिर से जुड़ी कथित अनियमितता की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर की जाए कड़ी कार्रवाई : संतोष कुमार सुमन

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (से.) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी कथित चोरी एवं अनियमितता के मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सदियों के संघर्ष, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, सनातन संस्कृति की अस्मिता और भारत की सांस्कृतिक चेतना का सर्वोच्च प्रतीक है। इसके निर्माण और प्राण-प्रतिष्ठा ने विश्वभर में भारत की सनातन परंपरा का गौरव बढ़ाया है। संतोष कुमार सुमन ने कहा कि ऐसे पवित्र स्थल से जुड़ी किसी भी कथित चोरी या अनियमितता को केवल आपराधिक घटना नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं और विश्वास प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि जांच पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरी होनी चाहिए तथा जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जांच में कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पद, प्रतिष्ठा या प्रभाव कितना भी बड़ा क्यों न हो, दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की गरिमा, श्रद्धालुओं का विश्वास और सनातन संस्कृति का सम्मान किसी भी व्यक्ति से बड़ा है तथा न्याय बिना किसी पक्षपात के होना चाहिए। संतोष कुमार सुमन ने यह भी कहा कि कुछ विपक्षी दल इस मामले को आधार बनाकर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, सनातन परंपरा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सामाजिक विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी कथित अपराध की निष्पक्ष जांच और दोषियों को दंड मिलना आवश्यक है, लेकिन एक घटना के आधार पर पूरे सनातन समाज, उसकी परंपराओं या किसी सामाजिक संगठन को कठघरे में खड़ा करना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि लगभग एक शताब्दी से सामाजिक जीवन में कार्य कर रहे संगठनों की विश्वसनीयता का आकलन किसी एक घटना से नहीं किया जा सकता। विपक्ष को इस संवेदनशील विषय पर राजनीतिक लाभ लेने के बजाय जांच पूरी होने और सत्य सामने आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

भारत मंडपम, नई दिल्ली में प्लास्टिक रीसाइक्लिंग एवं सततता पर तीसरे वैश्विक सम्मेलन का शुभारंभ

प्लास्टिक कचरे की वैश्विक समस्या से निपटने के लिए समन्वित एवं एकजुट प्रयास आवश्यक : तेजवीर सिंह

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के सहयोग से आयोजित प्लास्टिक रीसाइक्लिंग एवं सततता पर तीसरे वैश्विक सम्मेलन एवं अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का आज भारत मंडपम, नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। प्लास्टिक रीसाइक्लिंग एवं सततता के क्षेत्र में भारत के प्रमुख मंच के रूप में स्थापित इस चार दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के सचिव तेजवीर सिंह ने किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए तेजवीर सिंह ने कहा कि प्लास्टिक अपशिष्ट आज एक वैश्विक चुनौती है जिससे निपटने के लिए सभी देशों, उद्योगों और हितधारकों के समन्वित एवं एकजुट प्रयास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विश्वभर में प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या के समाधान के लिए अलग-अलग स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन समय की आवश्यकता है कि सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ की वैश्विक प्लास्टिक संधि जैसे वैश्विक ढांचों के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र संधि प्लास्टिक के उत्पादन, उपयोग तथा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक समान और बाध्यकारी वैश्विक व्यवस्था विकसित करने का प्रयास है। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सचिव ने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर के बेस्ट प्रैक्टिशेस से सीखते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में नवीन एवं प्रभावी प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए।

प्लास्टिक बैग पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा : प्रेम कुमार

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर लोगों से प्लास्टिक बैग के उपयोग में कमी लाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया। प्रेम कुमार ने कहा कि प्लास्टिक बैग पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा हैं। इनका विघटन अथवा पुनर्चक्रण सामान्यतः संभव नहीं होता जिसके कारण यह लंबे समय तक पर्यावरण को प्रदूषित करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण मानव निर्मित वैश्विक समस्या बन चुका है, जो पर्यावरण, जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस का उद्देश्य प्लास्टिक बैगों के उपयोग के खिलाफ सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह दिवस लोगों को प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण के प्रति सचेत करने तथा इसके उपयोग को कम करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम कुमार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने लोगों से दैनिक जीवन में कपड़े, जूट अथवा अन्य पर्यावरण-अनुकूल थैलों का उपयोग करने और एकल-उपयोग प्लास्टिक से दूरी बनाने की अपील की।

अब सौर ऊर्जा से लैस होंगे राज्य के कोल्ड स्टोरेज, कृषि विभाग दे रहा अनुदान

राज्य में किसानों को मिलेगा सस्ता कोल्ड स्टोरेज, रुकेगी फलों और सब्जियों की बर्बादी

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

पटना। अब बागवानी फसलों से जुड़े किसानों की चिंता जल्द दूर होगी। इसके लिए बिहार सरकार राज्य में सस्ते कोल्ड स्टोरेज की सुविधा बढ़ाने के लिए योजना लेकर आई है। कृषि विभाग का उद्यान निदेशालय राज्य कोल्ड स्टोरेज संबंधी योजना के तहत इच्छुक किसानों, उद्यमियों, कंपनियों या फर्मों को 50 प्रतिशत का भारी अनुदान दे रहा है। माना जा रहा है कि इससे राज्य के छोटे और मध्यम किसानों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। चतुर्थ कृषि रोडमैप के अंतर्गत बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए नए कोल्ड स्टोरेज के निर्माण तथा कार्यरत कोल्ड स्टोरेजों में सोलर पैनल की स्थापना एवं सोलर पैनल कूल चैंबर के लिए अनुदान की योजना चलाई जा रही है। कोल्ड स्टोरेज में सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना के लिए बिहार कृषि ऐप पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत राज्य के वर्तमान में मौजूद 50 कोल्ड स्टोरेज इकाइयों को सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित किया जाएगा, ताकि बिजली पर निर्भरता कम की जा सके और किसानों को सस्ती दर पर भंडारण की सुविधा प्राप्त हो सके। सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की अनुमानित लागत अधिकतम 35 लाख रुपये है जिस पर 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 17.50 लाख रुपये प्रति कोल्ड स्टोरेज सहायता अनुदान दिया जाएगा। वहीं, इसका लाभ लेने वाले कोल्ड स्टोरेज मालिक वर्तमान दर से न्यूनतम 25 प्रतिशत कम दर पर किसानों के उत्पाद का भंडारण करेंगे। यह योजना राज्य के उन 12 जिलों के लिए लाई गई है जो कोल्ड स्टोरेज की सुविधा के मामले में पिछड़े हुए हैं। ये 12 जिले हैं–मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल तथा शिवहर। लाभुकों का चयन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा। इस पहल से न सिर्फ किसानों को सस्ता कोल्ड स्टोरेज मिलेगा, बल्कि फलों और सब्जियों की बर्बादी भी रुकेगी। साथ ही, राज्य में मजबूत वैल्यू चेन सिस्टम तैयार होगा जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। माना जा रहा है कि सरकार की इस पहल से किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी।

यात्रियों के लिए एसबीआइ एनसीएमसी कार्ड लांच

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

पटना। मलाहीपकड़ी मेट्रो स्टेशन पर एसबीआइ की नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवाओं की शुरुआत के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल और आसान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम उपलब्धि हासिल की है। इस उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एसबीआइ के चीफ जनरल मैनेजर अनुराग जोशी शामिल हुए और उन्होंने संयुक्त रूप से यात्रियों के लिए एसबीआइ एनसीएमसी कार्ड लान्च किया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा, बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, पटना मेट्रो के एमडी संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी, एसबीआइ के जनरल मैनेजर योगेंद्र शेल्के, डिप्टी जनरल मैनेजर मनीष कुमार सिंह और डिप्टी जनरल मैनेजर संजीव कुमार नाथ के साथ-साथ एसबीआइ और पटना मेट्रो के अधिकारी भी मौजूद थे। एसबीआइ एनसीएमसी कार्ड को यात्रियों को सुविधाजनक, सुरक्षित और कैशलेस यात्रा का अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है। पटना मेट्रो में आसान यात्रा की सुविधा देने के अलावा इस कार्ड का इस्तेमाल कई तरह के रिटेल और डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए भी किया जा सकता है जिससे भारत सरकार के 'वन नेशन, वन कार्ड' (एक देश, एक कार्ड) के विजन को बढ़ावा मिलता है। इस लांच के साथ, एसबीआइ पटना मेट्रो के लिए एनसीएमसी सेवाएं देने वाले शुरुआती बैंकों में से एक बन गया है।

राज्य में अब तक कुल 0.39 करोड़ लोगों की हुई टीबी जांच

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

पटना। बिहार में टीबी जांच के लिए कुल लक्षित आबादी 2.76 करोड़ है, जिसमें से अब तक 14 प्रतिशत यानी केवल 0.39 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जा सकी है। अधिकांश जिले अभी भी 20 प्रतिशत से कम स्क्रीनिंग कवरेज पर हैं। मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने आगामी 14 अगस्त 2026 तक 1 करोड़ टीबी स्क्रीनिंग के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे पूरी तरह 'मिशन मोड' में संचालित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय अभियान की सफलता के लिए सभी संबंधित सरकारी विभागों और जिलाधिकारियों के बीच सुदृढ़ आपसी समन्वय जरुरी है।

कविता के माध्यम से डॉ. आनन्द रंजन झा ने समाज की दोहरी मानसिकता पर उठाए तीखे सवाल

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

वैशाली। प्रख्यात शिक्षाविद्, समाजसेवी एवं साहित्यकार डॉ. आनन्द रंजन झा की नवीन कविता 'चलाकियों के शहर में' इन दिनों सोशल मीडिया और साहित्यिक जगत में व्यापक चर्चा का विषय बनी हुई है। यह कविता वर्तमान समाज में बढ़ती स्वार्थपरता, छल-कपट, अवसरवाद और दोहरे चरित्र पर गहरा प्रहार करती है तथा पाठकों को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है। डॉ. झा ने कहा कि आज के दौर में रिश्तों की आत्मीयता और विश्वास लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। लोग सामने अपनापन दिखाते हैं, लेकिन अवसर आने पर वही लोग रिश्तों

और विश्वास को सबसे अधिक आहत करते हैं। उन्होंने कहा कि साहित्य केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि समाज का दर्पण है जो समय-समय पर लोगों को सच का सामना करने का साहस देता है। उन्होंने अपनी कविता 'चलाकियों के शहर में' में लिखा चलाकियों के शहर में, नफरतों के ढेरे हैं, यहां लोग तेरे मुंह पर तेरे, मेरे मुंह पर मेरे हैं।

चेहरों पर मुस्कान सजी, दिल में मगर अंधेरे हैं, रिश्तों की इस भीड़ में देखो, कितने लोग लुटेरे हैं। बातों में मिठास बहुत है, नीयत में जहर भरे हैं, सच की राह पर चलने वाले, अक्सर यहां अकेले हैं। हर कोई अपना कहता है, हर कोई साथ निभाता है, वक्त पड़े तो वही लोग, सबसे पहले मुंह फेरे हैं। दौलत, शोहरत, स्वार्थ की खातिर, बिकते यहां जमीर हैं, ईमानों के बाजारों में, सपनों के भी डेरे हैं। फिर भी उम्मीदों का दीपक, दिल में जलाए रखना तुम, अंधियारों के बीच कहीं, कुछ लोग अभी भी सवेरे हैं। चलाकियों के शहर में, नफरतों के ढेरे हैं, यहां लोग तेरे मुंह पर तेरे, मेरे मुंह पर मेरे हैं। डॉ. आनन्द रंजन झा ने स्पष्ट किया कि यह कविता किसी व्यक्ति, संस्था या समूह पर कटाक्ष नहीं है, बल्कि समाज में तेजी से विकसित हो रही उस मानसिकता पर प्रश्न उठाती है जहां रिश्तों से अधिक स्वार्थ और ईमानदारी से अधिक अवसरवाद को महत्व दिया जाने लगा है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से आह्वान किया कि वे सत्य, विश्वास, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाएं तथा समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनें।

महिलाएं भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर करने लगी शिकायतें : डीजी

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। राज्यभर से किसी पद पर बैठे भ्रष्ट लोकसेवकों के खिलाफ निगरानी ब्यूरो में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शिकायत करने लगी हैं। 2025 में 8 महिलाओं ने आगे बढ़कर भ्रष्ट लोकसेवकों के बारे में घूस मांगने की शिकायत निगरानी ब्यूरो से की। जबकि इस वर्ष जून तक ही 8 महिलाओं की शिकायतें आ गई हैं। यह संभव हो सका है, निगरानी ब्यूरो में चौबीस घंटे किसी भ्रष्ट लोकसेवकों के खिलाफ शिकायत करने की सुविधा बहाल होने और लगातार हो रही कार्रवाई की वजह से लोगों में एक भरोसा कायम होने के कारण। वर्ष अंत तक इसकी संख्या बढ़ेगी। ये बातें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक (डीजी) जितेंद्र सिंह गंगवार ने कही। वे गुरुवार को शहर के ज्ञान भवन में आयोजित बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने किया। इस मौके पर उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत अन्य मंत्री, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी विनय कुमार समेत अन्य मौजूद थे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने निगरानी ब्यूरो के नए लोगो का अनावरण भी किया। इसके गठन के करीब 80 वर्ष बाद इस ब्यूरो को अपना लोगो मिला है जो इसे अपना खास पहचान प्रदान करता है। डीजी श्री गंगवार ने कहा कि निगरानी ब्यूरो में भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 25 वर्षों यानी वर्ष 2000 से 2024 तक सालाना औसतन 72 एफआईआर होती थी। पिछले वर्ष इसमें 70 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और एफआईआर की यह संख्या बढ़कर 122 हो गई। मौजूदा वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में इसमें दो गुणा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी तरह ट्रैप के मामले में पिछले 25 वर्षों में सालाना औसतन 49 होते थे, जो 2025 में बढ़कर 101 हो गई और इस वर्ष इसमें तीन गुणा की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इसी तरह सजा दिलाने की मुहिम में भी काफी तेजी आई है। पिछले 25 वर्षों के दौरान सालाना औसतन 5.6 आरोपियों को सजा दिलाई गई, लेकिन सिर्फ पिछले वर्ष 30 आरोपियों को सजा दिलाई गई। इसमें छह गुणा की बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष सजा दिलाने की दर इससे कहीं आगे पहुंच जाएगी। महानिदेशक ने कहा कि अवैध तरीके से संपत्ति जमा करने वाले लोक सेवकों के खिलाफ भी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। अब तक भ्रष्टाचारियों की 102 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें 32 करोड़ रुपये की संपत्ति अंतिम रूप से जब्त कर ली गई है। महानिदेशक ने कहा कि शिक्षकों की वर्ष 2006 से 2015 के बीच हुई बहाली में गड़बड़ी की जा रही है। इसमें अब तक 3.50 लाख शिक्षकों के 6.70 लाख प्रमाण-पत्रों की जांच हो गई है, जिसमें 1830 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। कुछ मामलों की जांच चल रही है। इस जांच में नेपाल के अलावा दूसरे राज्यों के भी 378 बोर्ड या विश्वविद्यालय से विभिन्न तरह के डिग्रियों की जांच कराई गई है।

डॉक्टर्स डे पर चिकित्सक एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हुए सम्मानित

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। बिहार के सबसे पुराने एवं प्रतिष्ठित सामाजिक संगठनों में से एक रोटरी क्लब ऑफ पटना ने नए रोटरी वर्ष 2026-27 की पहली बैठक के अवसर पर डॉक्टर्स डे एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे का गरिमामय आयोजन किया। इस अवसर पर समाज एवं राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 15 प्रख्यात चिकित्सकों तथा 3 विशिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सम्मानित किया गया। सम्मानित चिकित्सकों में डॉ. सत्यजीत सिंह, डॉ. रविशंकर सिंह, डॉ. चिरंजीव खंडेलवाल, डॉ. अरविंद कुमार, डॉ. लाल बहादुर सिंह, डॉ अनुजा मिश्रा, डॉ. संजीव कुमार, डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार, डॉ. सुनीता कुमारी, डॉ. तन्वी सिंह, डॉ. अभिषेक कुमार, डॉ. दयानिधि कुमार, डॉ. माला सिंह, डॉ. रवीन्द्र नाथ टैगोर, डॉ. शिप्रा भारती तथा डॉ. आर. वी. सिंह शामिल थे। इसी अवसर पर सीए शैलेन्द्र कुमार, सीए अंजू शर्मा एवं सीए राजीव कुमार को भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्लब अध्यक्ष डॉ. रवि कुमार सिन्हा ने कहा कि चिकित्सक और चार्टर्ड अकाउंटेंट समाज के ऐसे स्तंभ हैं जो निःस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करते हैं। क्लब के सचिव डॉ. दयानिधि कुमार ने कहा कि रोटरी का प्रत्येक नया वर्ष सेवा, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व के नए संकल्प के साथ प्रारंभ होता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न मामलों की समयबद्ध और निष्पक्ष जांच हो

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और उत्पीड़न-मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से गुरुवार को पॉश कार्यस्थल पर महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विभिन्न विभागों की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। मौके पर महिला एवं बाल विकास निगम की प्रबंध निदेशक डॉ. प्रीति ने कहा कि पॉश कार्यशाला को महज औपचारिकता नहीं मानना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनों की जानकारी प्रदान करना तथा शिकायतों के प्रभावी निस्तारण की व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने आईसीसी सदस्यों से आह्वान किया कि उनके पास आने वाली प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई करें तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित करें।

प्रतिभागियों को 'कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013' के प्रमुख प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रत्येक संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। यदि किसी विभाग के कार्यालय अलग-अलग स्थानों पर हैं तो प्रत्येक प्रशासनिक इकाई में अलग-अलग समिति गठित की जाएगी। समिति की अध्यक्षता संबंधित संस्थान की वरिष्ठ महिला कर्मचारी करेंगी जबकि अन्य सदस्यों का मनोनयन नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी स्थानीय समिति का गठन करते है, जो 10 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों तथा नियोक्ता के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई करती है। कार्यशाला में लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा स्पष्ट की गई।

शारीरिक स्पर्श, यौन संबंध बनाने का दबाव या अनुरोध, अश्लील या यौन संकेत वाली टिप्पणियां, अश्लील साहित्य, तस्वीरें या अन्य आपत्तिजनक सामग्री दिखाना तथा किसी भी प्रकार का शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर मढ़ौरा की डॉ. निशान्धिता राज सम्मानित

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2026 के अवसर पर मढ़ौरा की बेटी एवं सुप्रसिद्ध फिजियोथैरेपिस्ट डॉ. निशान्धिता राज को निशुल्क भौतिक चिकित्सा शिविर के आयोजन तथा अपने क्षेत्र में रियायती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, बिहार विधान परिषद सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व सलाहकार विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा कुलाधिपति दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय पद्मभूषण डॉ सीपी ठाकुर, पूर्व केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री श्री अश्वनी चौबे तथा पूर्व विधान पार्षद एवं विभागाध्यक्षा, हिंदी विभाग, पटना विमेंस कॉलेज, प्रो. किरण घई के द्वारा डॉ वैद्यनाथ मिश्रा सम्मान से सम्मानित किया गया। मौके पर डॉ. निशान्धिता राज ने बताया कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस पर इस प्रकार का सम्मान पाना मेरे लिए अविस्मरणीय एवं प्रेरणादायी क्षण है। चिकित्सा सेवा पर हर एक व्यक्ति का एक समान अधिकार होना चाहिए और मुझे यह सम्मान इस दिशा में कार्य करने के लिए और अधिक प्रेरित कर किया है। मेरा भी प्रयास समाज के हर तबके को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का रहेगा। कार्यक्रम में चिकित्सा शोध एवं सामाजिक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया।

संपादकीय

नई ईवी नीति- इलेक्ट्रिक वाहनों से घटेगा प्रदूषण या बढ़ेंगी आम लोगों की मुश्किलें?

दिल्ली की सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन की बदहाली छिपी नहीं है। इसे बेहतर बनाने के लिए किसी भी सरकार ने ऐसे कदम नहीं उठाए हैं, ताकि लोग निजी वाहनों के बारे में न सोचें। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति के जरिए अगर दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या पर काबू पाने में मदद मिलती है, तो इसे एक बेहतर उपाय माना जाएगा। इसमें कोई दोराय नहीं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गहराती समस्या के मद्देनजर इसकी मुख्य वजहों की पहचान और उनसे निपटने के लिए ठोस उपाय करना जरूरी है। मगर इस क्रम में सरकार जिन नीतियों का सहारा लेना चाहती है, वे व्यापक जनहित में हों, यह सुनिश्चित किया जाना भी वक्त का तकाजा है।देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण एक अहम समस्या के रूप में चिंता का मुद्दा बना रहता है। इसके लिए सड़क पर चलने वाले वाहनों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। खासतौर पर दुपहिया वाहनों की बढ़ती संख्या न केवल सुव्यवस्थित यातायात, बल्कि प्रदूषण के लिहाज से अपेक्षया ज्यादा बहस के केंद्र में रहती है।इन्हीं बिंदुओं के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सोमवार को नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत अगले वर्ष जनवरी से सिर्फ ई-ऑटो यानी इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का ही पंजीकरण होगा। साथ ही, जनवरी 2028 से सिर्फ ई-दुपहिया वाहनों का ही पंजीकरण कराया जा सकेगा। नई नीति के तहत अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सड़क-कर और पंजीकरण शुल्क में छूट की व्यवस्था भी की गई है।जाहिर है, सरकार ने एक तरह से नीतिगत तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के क्रम में एक ठोस फैसला किया है, लेकिन चूंकि इसका वैसे लोगों के जीवन पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है, जिनकी रोजी-रोटी इन वाहनों से जुड़ी होती है, इसलिए फिलहाल इसके कई अन्य पहलुओं पर बहस जारी है।हालांकि यह भी एक तथ्य है कि दिल्ली में पिछले कई वर्षों से लगातार प्रदूषण की वजह से हालात बेहद चिंताजनक होते गए हैं, तो इसमें वाहनों की खासी भूमिका रही है। मगर इसमें कारों और अन्य वाहनों के बरक्स दुपहिया और तिपहिया वाहनों की कितनी भूमिका है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। खासतौर पर इसलिए भी कि दिल्ली में तिपहिया वाहन आमतौर पर सीएनजी से चलते हैं। एक समय पेट्रोल और डीजल वाहनों के धुएं से होने वाला प्रदूषण व्यापक चिंता का विषय बना था और उस समय सीएनजी वाहनों के जरिए दिल्ली की हवा को स्वच्छ करने के दावे किए गए थे। लेकिन आज भी दिल्ली में वायु प्रदूषण की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। वहीं, इलेक्ट्रिक कचरा आज विश्वभर में पर्यावरण के सामने एक नई चुनौती बन रहा है।यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इस नीति के केंद्र में फिलहाल जिन दुपहिया और तिपहिया वाहनों को रखा गया है, वे बड़ी संख्या में साधारण लोगों की आजीविका और आवागमन का मुख्य सहारा रहे हैं। नई नीति की अनिवार्यता की स्थिति में अपने वाहन को इलेक्ट्रिक प्रणाली में बदलना कम आयवर्ग के लोगों के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन सकता है।दूसरी ओर, दिल्ली की सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन की बदहाली छिपी नहीं है।

देखा जाये तो दशकों तक भारतीयों का खून बहाने वाला पाकिस्तान अब पानी की कमी होने पर कांप रहा है और वहां के नेता गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंधु पाकिस्तान की जीवनरेखा है और भारत पानी को हथियार बना रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अपने पानी, अपनी संप्रभुता और अपने भविष्य की रक्षा करेगा। पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसद्दिक मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि जो हाथ उनके पानी को छुएंगे, उन्हें काट दिया जाएगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी भारत पर पानी रोकने का आरोप लगाते हुए आक्रामक बयान दिए।

पानी पाकिस्तान का बंद हुआ है, मगर गला यहां के 'शांति दूतों' का क्यों सूख रहा है?

(नीरज कुमार दुबे)

देखा जाये तो दशकों तक भारतीयों का खून बहाने वाला पाकिस्तान अब पानी की कमी होने पर कांप रहा है और वहां के नेता गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंधु पाकिस्तान की जीवनरेखा है और भारत पानी को हथियार बना रहा है।

पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस दृढ़ता के साथ पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखानी शुरू की है, उससे इस्लामाबाद की सत्ता, सेना और वहां के कथित लोकतांत्रिक चेहरे बुरी तरह बौखला गए हैं। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के भारत के फैसले ने पाकिस्तान की नसों में ऐसा डर भर दिया है कि वहां के नेता लगातार धमकियां दे रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रो रहे हैं और दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने उनके अस्तित्व पर हमला कर दिया है।

देखा जाये तो दशकों तक भारतीयों का खून बहाने वाला पाकिस्तान अब पानी की कमी होने पर कांप रहा है और वहां के नेता गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंधु पाकिस्तान की जीवनरेखा है और भारत पानी को हथियार बना रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अपने पानी, अपनी संप्रभुता और अपने भविष्य की रक्षा करेगा। पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसद्दिक मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि जो हाथ उनके पानी को छुएंगे, उन्हें काट दिया जाएगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी भारत पर पानी रोकने का आरोप लगाते हुए आक्रामक बयान दिए। पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री इशाक डार ने दुनिया को डराने की कोशिश की कि यदि सिंधु जल संधि नहीं बची तो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की पूरी विश्व व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी।

लेकिन पाकिस्तान के इन आंसुओं के पीछे छिपा सच पूरी दुनिया जानती है। पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवादी कहां से आए थे? जम्मू-कश्मीर में दशकों से आतंकवाद को कौन पालता रहा है? भारत के सैनिकों और नागरिकों का खून बहाने के लिए हथियार, प्रशिक्षण और धन कौन देता रहा है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करके यह स्पष्ट कर दिया कि अब नई दिल्ली पुरानी नीति पर नहीं चलेगी। यदि पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बनाए रखेगा तो उसे हर मोर्चे पर कीमत चुकानी होगी। भारत ने पश्चिमी नदियों पर अपने अधिकार वाले जल के उपयोग को तेज करने का फैसला किया है। यह कोई युद्ध नहीं, बल्कि अपने अधिकारों का प्रयोग है।

साथ ही सबसे बड़ा सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो भारत में बैठकर पाकिस्तान से वार्ता की मांग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक सौ से अधिक तथाकथित बुद्धिजीवियों, नेताओं और सामाजिक हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाहबाज शरीफ को पत्र लिखकर बातचीत बहाल करने, वीजा सेवाएं शुरू करने, दूतावास सामान्य करने और यहां तक कि कश्मीर पर फिर से बातचीत करने की मांग की है। इस पत्र पर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मीरवाइज उमर फारूक और कुछ अन्य भारतीय हस्तियों के हस्ताक्षर भी हैं।

इन लोगों से देश पूछना चाहता है कि आखिर पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है? जो देश भारत में आतंकवादी भेजता है, हमारे नागरिकों की हत्या करवाता है, सीमा पार से गोलियां चलाता है, उसी देश के लिए इनके दिल में इतनी

बेचैनी क्यों उमड़ती है? भारत ने जब पाकिस्तान का पानी रोकने की दिशा में कदम उठाया तो प्यास पाकिस्तान को लगी, लेकिन गला यहां बैठे तथाकथित शांति दूतों का सूखने लगा। आखिर क्यों? क्या इन लोगों को भारत की सुरक्षा से ज्यादा चिंता पाकिस्तान की खेती और उसकी बिजली व्यवस्था की है?

ये लोग कहते हैं कि वार्ता ही समाधान है। लेकिन देश जानना चाहता है कि आखिर कितनी वार्ताएं हो चुकी हैं? लाहौर बस यात्रा से लेकर आगरा शिखर वार्ता तक और उफा से लेकर शरम अल शेख तक भारत ने हर बार शांति का हाथ बढ़ाया। बदले में मिला क्या? कारगिल, संसद हमला, मुंबई हमला, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम। पाकिस्तान हर बार वार्ता की मेज पर मुस्कुराता है और पीठ पीछे आतंकियों को भेजता है।

आज जब भारत पहली बार कठोर नीति पर डटा है तो देश के भीतर बैठे कुछ लोग बेचैन हो उठे हैं। उन्हें आतंकवाद पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान का पानी रुकने पर दर्द होने लगता है। उन्हें भारत के शहीदों की चिंता कम और इस्लामाबाद की परेशानी ज्यादा दिखाई देती है। यह वही मानसिकता है जिसने दशकों तक भारत को कमजोर नीति में बांध कर रखा।

सच यह है कि सिंधु जल संधि का सबसे ज्यादा लाभ पाकिस्तान ने उठाया। भारत ने वर्षों तक उदारता दिखाई, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता रहा। अब जब नई दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंक और व्यापार, आतंक और वार्ता, आतंक और पानी साथ साथ नहीं चल सकते, तब पाकिस्तान दुनिया भर में सहानुभूति जुटाने निकला है। लेकिन दुनिया भी समझ रही है कि समस्या की जड़ कहां है।

पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है। पानी को लेकर युद्ध चाहता है तो उसे पहले आतंकवाद की फैक्टरी बंद करनी होगी। जब तक उसकी धरती से भारत विरोधी आतंक जारी रहेगा, तब तक कोई भी वार्ता केवल छलावा मानी जाएगी।

बहरहाल, भारत की जनता अब भ्रम में नहीं है। देश समझ चुका है कि शांति की सबसे पहली शर्त सुरक्षा है। और जो लोग पाकिस्तान के लिए आंसू बहा रहे हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि भारत की सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल अब कोई नहीं कर सकता। नया भारत अपने सैनिकों के खून का हिसाब भी लेगा और अपने पानी का अधिकार भी बचाएगा।

'इच्छाधारी' आस्था का चुनावी गणित

(प्रणय विक्रम सिंह)

अयोध्या के संदर्भ में विपक्ष की नई-नई जागी श्रद्धा को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी से एक बहुत बड़ी चूक हो गई है।

वे मारीच, सुबाहु और कालनेमि जैसे दिव्य भेष बदलने वाले मायावियों को त्रेतायुग में ही निपटा गए। उन्हें जरा रुकना चाहिए था। वे आज के युग में आते, तो देखते कि भेष बदलने की यह कला अब केवल राक्षसों की बपौती नहीं रही, इसका लोकतांत्रिक विकास हो चुका है और अब इसके सबसे कुशल अभ्यासकर्ता हमारे राजनेता हैं।

सुना है, कल तक जो लोग भगवान राम को केवल एक अदालती एफेडेविट का 'काल्पनिक पात्र' मानते थे, आज वे चुनाव की आहट सुनते ही हाथ में आस्था का नया-नवेला थर्मामीटर लेकर घूम रहे हैं। वे ट्विटर पर अयोध्या को 'अनुपम और अनुकरणीय धार्मिक नगरी' बनाने की वैसी ही पवित्र कसमें खा रहे हैं, जैसी कसमें एक जेबकतरा अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिए कोट कचहरी में खाता है।

इस दिव्य और त्वरित हृदय परिवर्तन को देखकर मुझे गिरगिटों की मानसिक स्थिति पर तरस आता है। बेचारे डिप्रेशन में होंगे कि जिस हुनर के लिए वे सदियों से बदनाम थे, उसमें कुछ सैफई ब्रांड समाजवादी इंसानों ने पीएचडी कर ली और उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा।

आखिर कोई उस राम-नाम का जाप इतनी पवित्रता से कैसे कर सकता है, जिसके राजनीतिक कुनबे का पूरा इतिहास ही राम-विरोध की खाद पर फला-फूला हो?

आजकल वे फीता लेकर निकले हैं। पूछ रहे हैं कि अयोध्या से गोरखपुर कितनी दूर है? नेताजी, दूरी नापने का यह शौक नया है। पर आप गलत नक्शा देख रहे हैं। अयोध्या से गोरखपुर की दूरी तो उतनी ही है, जितनी सत्य और सनातन के बीच होती है। यानी दोनों आपस में जुड़े हैं। पर आपके 'पारिवारिक सिंडिकेट' और रामराज्य के बीच की दूरी अनंत है, जिसे नापने के लिए आपके पास न तो नैतिक पैमाना है और न ही वैसा चरित्र। अच्छा होता कि आप इस दूरी को नापने से पहले यह बता पाते कि राम के प्रति आपकी खानदानी नफरत और आपके वोटबैंक के लालच के बीच कुल कितने किलोमीटर का फासला है?

जब आदमी को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती दिखती है, तो उसे इतिहास की कड़वी यादें भूलने का 'अल्जाइमर' रोग हो जाता है। लेकिन जनता की याददाश्त बहुत क्रूर होती है, नेताजी। जनता को आज भी याद है कि जब आपके पूज्य पिताजी की हुकूमत थी, तब अयोध्या की पावन गलियों में कोई भजन नहीं गूंज रहा था, बल्कि निहत्थे रामभक्तों का खून बह रहा था। तब आपकी सरकारी मशीनरी मंदिर के पत्थरों को ज़ब्त करने में वैसी ही मुस्तैदी दिखा रही थी, जैसी मुस्तैदी कोई डकैत माल समेटने में दिखाता है। और उसी पावन दौर में, पुलिस थानों और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने पर ऐसा प्रतिबंध था, मानो कंस खुद लखनऊ के सचिवालय में आकर बैठ गया हो।

जो लोग कल तक रामलला के प्राण-प्रतिष्ठा के निमंत्रण पत्र को अछूत मानकर ठुकरा रहे थे, आज वे 'सियाराम-धाम' के पुनरुद्धार का ठेका लेने की बात कर रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे बिल्ली चूहों की सुरक्षा के लिए एक सर्वदलीय समिति बनाने का प्रस्ताव रखे।

राम की सेवा के लिए 'भेष' और 'ट्वीट' बदलने की नहीं, 'भाव' बदलने की जरूरत होती है। पर आपके पास तो वही पुराना हलफनामा है, जो आपने कभी सर्वोच्च न्यायालय में जमा किया था। आपकी पूरी राजनीतिक पूंजी ही यही रही है कि जब तक सत्ता में रहो, हिंदुओं की आध्यात्मिक भावनाओं को वैसे ही कुचलो जैसे रास्ते का कंकड़ कुचला जाता है, और जब चुनाव आ जाएं, तो माथे पर एक लंबा सा छद्म टीका लगाकर 'इच्छाधारी रामभक्त' की मुद्रा में जनता को सम्मोहित करने निकल पड़ो।

मेरी की एक बात हमेशा याद रखिएगा भैयाजी, आप भगवान को धोखा दे सकते हैं क्योंकि वे घट-घट वासी होकर भी चुप रहते हैं, पर जनता को नहीं, क्योंकि वह सब देखकर सही समय पर ईवीएम का बटन दबाती है।

सुना है, आपने तो अयोध्या का राजा ही बदल दिया। जबकि सभी सनातनियों के लिए त्रेता युग से आज तक अयोध्या के राजा श्री रामचन्द्र जी हैं। जो काम लंका का रावण अपनी पूरी दस खोपड़ियों की ताकत लगाकर नहीं कर पाया, वह आपने अपने वोटबैंक को खुश करने के लिए बड़ी सरलता से कर दिया। कई दिनों तक संसद में अपने बगल में उनको बैठाकर घुमाते रहे। राम से इतनी घृणा कि उन्हें अयोध्या के राजा के रूप में स्वीकार करने में आपकी छाती फटने लगती है, इसलिए आपने प्रतीकों का नया बाज़ार सजा लिया। आपका यह दोहरा चरित्र और अतीत उत्तर प्रदेश के हर रामभक्त के सीने में एक गहरे घाव की तरह आज भी टीस रहा है।

याद रखिए, इतिहास की स्याही बहुत पक्की होती है, वह आपके इन बनावटी और सुगठित ट्वीट्स के 'थूक' से नहीं धुलेगी। 10 नवंबर 1990 का वह अंधकारमय काला दिन, निहत्थों का रक्तपात, थानों में जन्माष्टमी पर पाबंदी और पावन पत्थरों का अपमान, यह सब आपके माथे पर वो अमिट कलंक हैं, जिन्हें धोने के लिए यदि आप सरयू का पूरा पानी भी इस्तेमाल कर लें, तो भी कम पड़ेगा।

अयोध्या अब सज चुकी है, दिव्य और भव्य हो चुकी है। वहां अब आपके पाखंड का कोहरा नहीं, बल्कि प्रभु राम का 'परम प्रकाश' जगमगा रहा है। और इतिहास गवाह है कि जब प्रकाश उदित होता है।

ग्राम्य विकास के विरोध में विपक्ष !

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का हालिया निर्णय, जिसमें ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने की व्यवस्था को असंवैधानिक ठहराया गया है, इसी समीक्षा की एक स्वाभाविक परिणति है। लेकिन यहां सहमति और असहमति के विकल्प भी हैं। संविधान में असहमति के बिंदु पर आगे जाने की व्यवस्था भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यों को केंद्र में रखते हुए यह फैसला लिया था तो वह अपने संविधान सम्मत विकल्प भी देखेगी। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार इस न्यायिक निर्णय को राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए आतुर है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार ने एक प्रयास किया था कि किसी भी अवरोध पर गांवों का विकास अवरुद्ध न होने पाए।

(सुरेश बहादुर सिंह)

उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में ग्राम प्रधानों को भयभीत कर विपक्ष न सिर्फ नकारात्मक राजनीति का उदाहरण पेश कर रहा है, बल्कि ग्रामीण विकास में बाधा भी बन रहा है। यह साबित करता है कि जनाधार खो चुके राजनीतिक दल अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।)

एक बड़ा प्रश्न हम सबके समक्ष है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? जवाब बहुत सारे हो सकते है, जैसे कि जनादेश सबसे बड़ी शक्ति है लेकिन बात पूरे लोकतंत्र की हो रही है। जनादेश यह तय करता है कि सत्ता किसकी होगी लेकिन जब लोकतंत्र के बारे में विचार करेंगे तो उसकी असली ताकत संविधान द्वारा निर्धारित संस्थाओं के बीच संतुलन और परस्पर सम्मान के रूप में उभरकर सामने आएगी। शासन जनता के विश्वास से चलता है, किंतु उसकी वैधता संविधान से आती है। इसलिए जब न्यायपालिका किसी प्रशासनिक निर्णय की संवैधानिक समीक्षा करती है, तो वह किसी सरकार की पराजय या विपक्ष की विजय का अवसर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्वाभाविक प्रक्रिया है। दुर्भाग्य से आज न्यायालयों के निर्णय भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनते जा रहे हैं। फैसलों की कानूनी व्याख्या से अधिक उन्हें राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू पर तौला जा रहा है, जिससे समाज में भ्रम और अविश्वास का वातावरण पैदा होता है। ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि न्यायिक निर्णयों को उनकी संवैधानिक भावना के अनुरूप समझा जाए, न कि राजनीतिक प्रचार के औजार के रूप में देखा जाए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का हालिया निर्णय, जिसमें ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने की व्यवस्था को असंवैधानिक ठहराया गया है, इसी समीक्षा की एक स्वाभाविक परिणति है। लेकिन यहां सहमति और असहमति के विकल्प भी हैं। संविधान में असहमति के बिंदु पर आगे जाने की व्यवस्था भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यों को केंद्र में रखते हुए यह फैसला लिया था तो वह अपने संविधान सम्मत विकल्प भी देखेगी। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार इस न्यायिक निर्णय को राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए आतुर है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार ने एक प्रयास किया था कि किसी भी अवरोध पर गांवों का विकास अवरुद्ध न होने पाए। जो विकास कार्य चल रहे हैं, वे रुकने न पाएं। इसमें सरकार का अपना पक्ष विकास का है।

न्यायालय का अपना पक्ष है, लेकिन इसी के साथ एक बड़ा प्रश्न इस बात का भी है कि विपक्ष के दायित्व क्या होने चाहिए थे। न्यायालय की गरिमा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब बात विकास की हो, ग्रामीण जनता के विकास की हो तो विपक्ष का उसमें राजनीतिक स्वार्थ देखना कितना न्यायोचित है, इस पर विचार करना होगा। ऐसे मुद्दों पर संकीर्णता को त्याग कर सरकार का सहयोग देना भी विपक्ष का लोकतांत्रिक कर्तव्य है। लेकिन, न्यायालय के आदेश को सही रूप में जनता तक पहुंचाने के बजाय विपक्ष ने भ्रम, भय और असत्य का एक ऐसा जाल बुनना शुरू कर दिया, जो न ग्राम प्रधानों के हित में है, न ग्रामीण समाज के और न ही इस देश के लोकतंत्र के।

यह समझना आवश्यक है कि विपक्ष कौन से भ्रम फैला रहा है और वास्तविकता क्या है। पहला और सबसे बड़ा भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर असंवैधानिक कार्य किया। विपक्ष की मंशा यह स्थापित करने की है कि सरकार संविधान का उल्लंघन करने की मंशा से काम कर रही थी, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नहीं, सरकार ने वही किया जो कोई भी जिम्मेदार व सजग संस्था करती। क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्राम प्रधान को ही प्रशासक बनाना सर्वाधिक उपयुक्त निर्णय था। फैसले की संवैधानिक व्याख्या एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है।

सरकारें प्रशासनिक निर्णय लेती हैं, न्यायालय उनकी संवैधानिक समीक्षा करता है और यदि न्यायालय किसी व्यवस्था को संविधान के अनुरूप नहीं पाता तो सरकार उस आदेश को स्वीकार करते हुए आवश्यक कदम उठाती है या अपने पक्ष को उचित मानते हुए बड़ी बेंच या शीर्ष अदालत तक जाती है। यही संवैधानिक लोकतंत्र की सुंदरता है और यही उसकी ताकत भी। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच यह संतुलन हमारे संविधान की आत्मा है। जब न्यायालय किसी व्यवस्था की संवैधानिक समीक्षा करता है तो इसका अर्थ यह है कि संवैधानिक व्याख्या का एक नया आयाम सामने आया है। आप सहमत हों तो स्वीकार करें या फिर इसे चुनौती दें।

कोर्ट के आदेश को केंद्र में रखते हुए एक भ्रम यह भी फैलाया जा रहा है कि ग्राम प्रधानों द्वारा किए गए अब तक के सभी कार्य और भुगतान अवैध हो गए हैं। इसे इतने जोर-शोर से फैलाया जा रहा है मानो पिछले पांच सालों में गांवों में हुआ हर निर्माण कार्य, हर सड़क, हर नाली, हर सामुदायिक भवन अब गैरकानूनी हो गया हो। यह न केवल कानूनी दृष्टि से निराधार है, बल्कि अत्यंत गैरजिम्मेदाराना भी है। जब बात गांव के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की हो रही हो, तो उसमें विपक्ष का दायित्व है कि वह सकारात्मक रुख अपनाए। इसे राजनीतिक मुद्दे के रूप में उठाने को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। राजनीतिक अटकलबाजी में वास्तविक तथ्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

इस संदर्भ में एक और बात महत्वपूर्ण है जिसे विपक्ष सायास खड़ा कर रहा है। वह यह कि ग्राम प्रधानों से उनके कार्यकाल में खर्च किए गए धन की वसूली की जाएगी। विपक्ष यह भ्रम फैलाकर उन हजारों ग्राम प्रधानों के मन में भय व आतंक का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है, जिन्होंने ईमानदारी से अपने गांवों की सेवा की है। जो प्रतिनिधि सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में लगे रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर स्वच्छ भारत मिशन तक को गांव-गांव पहुंचाने में अपना योगदान दिया, उन्हें भयभीत करना राजनीतिक दुर्भावना की पराकाष्ठा है।

एक सहज सवाल स्वाभाविक है कि विपक्ष यह भ्रम और भय क्यों फैला रहा है? इसके उत्तर में उन लोगों की प्रवृत्ति को देखना होगा, जिन्हें जनता खारिज कर चुकी है। जिन दलों के पास न कोई रचनात्मक नीति हो, न जनता के विकास का कोई ठोस दृष्टिकोण और न ही सत्ता में रहते हुए ग्रामीण उत्थान का कोई उल्लेखनीय इतिहास हो, उन्हें अदालती आदेश में अपने लिए संभावनाएं नजर आ रही हैं। अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए वे इसे भुनाने की चेष्टा करना चाहते हैं। ग्रामीण लोगों को भ्रमित करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार उनकी विरोधी है। वास्तविकता सबके सामने है। योगी सरकार में पंचायती राज संस्थाएं कितनी सशक्त हुई हैं, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं। अदालत के आदेश पर कोई असंतुलित प्रतिक्रिया न देना न्यायपालिका के प्रति सरकार के सम्मान भाव का परिचायक है और वह इसके लिए प्रतिबद्ध भी प्रतीत होती है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के पास बड़ी बेंच या शीर्ष अदालत में अपील का अधिकार भी है। पंचायतों के विकास कार्य किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने दिए जाएं, यह उसकी प्रतिबद्धता भी है।

लोकतंत्र में न्यायालय की भूमिका संविधान के संरक्षक की है। जब वह किसी व्यवस्था की समीक्षा करता है और उसे परिमार्जित करने का निर्देश देता है, तो यह लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण है। संवैधानिक संस्थाओं का सक्रिय रहना, सजग रहना, यह संदेश देता है कि वे अपने दायित्व निभा रही हैं। न्यायालय का सम्मान, संविधान की रक्षा और गांवों का निर्बाध विकास। इन तीनों को एक साथ चलना चाहिए और इसे सुनिश्चित करना सबकी जिम्मेदारी है। सुशासन न्यायपालिका का सम्मान करता है और जनता के हितों की सुरक्षा भी। इसलिए माना जा सकता है कि सरकार सुसंगत फैसले लेगी, संविधान सम्मत लेगी, जो विपक्ष के भ्रमजाल का जवाब भी होगा। (लेखक पूर्व अपर शासकीय अधिवक्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट) ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं।

एसएसपी ने 785 दागियों को दिलाई शपथ

अपराध छोड़ मुख्यधारा से जुड़ने की दी नसीहत

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

धनबाद। अपराध नियंत्रण, अपराधियों की निगरानी और समाज में शांति एवं कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से धनबाद पुलिस ने गुरुवार को पुलिस लाइन में एक ऐतिहासिक पहल की। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के चिन्हित 785 दागी व्यक्तियों की सामूहिक परेड वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के समक्ष कराई गई। बताया गया कि झारखंड में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में चिन्हित दागी व्यक्तियों की एक साथ परेड आयोजित की गई है। आगे भी यह इस तरह की पेशी समय समय पर की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, परेड में शामिल अधिकांश व्यक्ति विभिन्न आपराधिक मामलों में आरोपित हैं या पूर्व में जेल जा चुके हैं। इन सभी की वर्तमान गतिविधियों की समीक्षा करने, उनका सत्यापन करने तथा भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी दागी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया तथा उनकी अद्यतन जानकारी पुलिस अभिलेखों में दर्ज की गई।

परेड को संबोधित करते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजना नहीं, बल्कि समाज में अपराध को जन्म लेने से पहले रोकना भी है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी गलतियों को सुधारने और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपराध का रास्ता छोड़कर ईमानदारी से सामान्य नागरिक की तरह जीवन व्यतीत करता है तो धनबाद पुलिस उसका पूरा सहयोग करेगी।

एसएसपी ने यह भी घोषणा की कि जिन लोगों का आचरण अच्छा रहेगा, जो लंबे समय तक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे तथा सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, उनका नाम दागी सूची से हटाने पर विचार किया जाएगा। वहीं यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी मुकदमे में गलत कारणों से दर्ज हो गया हो और उसका अपराध से कोई संबंध न हो, तो ऐसे लोगों को अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

हालांकि उन्होंने स्पष्ट चेतावनी भी दी कि यदि कोई व्यक्ति अपराध की दुनिया में दोबारा लौटता है तो उसके विरुद्ध कानून के तहत और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि धनबाद पुलिस अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है तथा किसी भी परिस्थिति में कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा।

इस अवसर पर सभी दागी व्यक्तियों को सामूहिक रूप से शपथ दिलाई गई कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार के अपराध, गैर-सामाजिक गतिविधि अथवा कानून-विरोधी कार्य में शामिल नहीं होंगे। साथ ही वे समाज में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करेंगे।

परेड समाप्त होने के बाद सभी 785 दागी व्यक्तियों की फोटोग्राफी एवं पहचान संबंधी विवरण अद्यतन किए गए। इन आंकड़ों के आधार पर थाना स्तर पर नई दागी सूची तैयार की जा रही है, ताकि चिन्हित व्यक्तियों की गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखी जा सके। धनबाद पुलिस का मानना है कि इस तरह की पहल से अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, अपराधियों की सतत निगरानी तथा समाज में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी।

कैदियों के लिए अनूठी पहल की शुरूआत

चाईबासा। मंडल कारा चाईबासा में बंदियों को सजा काटने के साथ-साथ उनके जीवन को सकारात्मक दिशा देने के लिए अनूठी पहल की शुरूआत की गई है। उपायुक्त मनीष कुमार के निर्देश पर जेल में प्रोजेक्ट परिवर्तन के तहत औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। आरसेटी के सहयोग से आयोजित यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 जुलाई से 11 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। इस दौरान जेल के बंदियों को औषधीय और सुगंधित पौधों की वैज्ञानिक खेती करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि प्रोजेक्ट परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि आपको आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा से सम्मानपूर्वक जोड़ना है।

उन्होंने कहा कि जेल से रिहा होने के बाद यही हुनर आपके लिए रोजगार और सम्मानजनक जीवन का आधार बनेगा।

बिना लाइसेंस के नहीं बेच सकेंगे खाद और कीटनाशक

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

धनबाद। जिले में बिना लाइसेंस के बीज, उर्वरक और कीटनाशकों का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। खरीफ मौसम के दौरान बढ़ती मांग को देखते हुए जिला कृषि विभाग लगातार छापा मार रही है।

गत दिनों बलियापुर में भी छापा मारा गया था। जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक मिश्र ने आम सूचना जारी कर कहा है कि बिना वैध अनुज्ञप्ति के बीज, खाद और कीटनाशकों की खरीद-बिक्री पूरी तरह गैरकानूनी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यवसायियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन में धान के बीज, खाद और कीटनाशकों की मांग बढ़ने के साथ कई व्यापारी और सामान्य राशन दुकानदार बिना लाइसेंस इनका व्यापार शुरू कर देते हैं। इससे नकली खाद, अमानक बीज, प्रतिबंधित कीटनाशकों की बिक्री और जमाखोरी की आशंका बढ़ जाती है, जिसका सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। जिला कृषि कार्यालय ने सभी व्यवसायियों और विक्रेताओं को कारोबार शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से वैध अनुज्ञप्ति लेने का निर्देश दिया है। साथ ही किसानों से अपील की गई है कि वे केवल लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही कृषि सामग्री खरीदें, पक्का बिल अवश्य लें और किसी भी अनियमितता की सूचना तत्काल कृषि विभाग को दें, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

कोर्ट में एक हुए जीवनसाथी, बच्चों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

लातेहार। न्यायालय परिसर में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। लंबे समय से अलग रह रहे कृति देवी और उनके पति जस कुमार उरांव ने आपसी मतभेदों को पीछे छोड़ते हुए फिर से एक साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया।

जैसे ही दोनों ने समझौते पर सहमति जताई और न्यायालय से साथ बाहर निकले, उनके तीनों बच्चे दीपक उरांव, रीमा कुमारी और प्रिया कुमारी के चेहरों पर खुशी साफ झलकने लगी। कुछ देर पहले तक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बना यह परिवार देखते ही देखते फिर से एक छत के नीचे लौटने की उम्मीद के साथ घर के लिए रवाना हुआ।

न्यायालय परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं, कर्मियों और स्वजन ने इस पल का स्वागत किया। यह सफलता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मार्गदर्शन में संचालित मध्यस्थता केंद्र के सतत प्रयासों का परिणाम रही। प्रशिक्षित मध्यस्थ सह बार एसोसिएशन लातेहार के अध्यक्ष लाल अरविंद नाथ शहदेव ने धैर्यपूर्वक दोनों पक्षों की बात सुनी और उन्हें रिश्ते की अहमियत का एहसास कराया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव शिवम चौरसिया, अधिवक्ता रंजन यादव और बिरसा उरांव ने भी लगातार संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। कई दौर की बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अपने विवाद का पटाक्षेप कर दिया। इस समझौते की सबसे बड़ी खुशी उन तीन मासूम बच्चों के हिस्से आई, जिन्हें अब फिर से माता और पिता दोनों का स्नेह एक साथ मिलेगा।

स्वजन ने भी राहत की सांस ली और इसे नई शुरूआत बताया। न्यायालय परिसर में मौजूद लोगों का कहना था कि मुकदमे जीतने से कहीं अधिक सुख परिवार के फिर से जुड़ने में है। जब बिखरे रिश्ते जुड़ते हैं तो सबसे बड़ी जीत इंसानियत की होती है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधिकारियों ने बताया कि मध्यस्थता केंद्र का उद्देश्य केवल विवाद समाप्त करना नहीं, रिश्तों में संवाद कायम कर परिवारों को टूटने से बचाना भी है। यह मामला उसी सोच का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया।

कृति देवी और जस कुमार उरांव के परिवार के फिर से एक होने से यह संदेश भी गया कि धैर्य, संवाद और आपसी विश्वास के सहारे वर्षों पुराने मतभेद समाप्त किए जा सकते हैं। सोमवार को न्यायालय परिसर से विदा हुआ यह परिवार अपने साथ समझौते के साथ एक नई उम्मीद, नया विश्वास व तीन बच्चों के सुनहरे भविष्य की मुस्कान भी लेकर गया।

एसआइआर ने पकड़ी रफ्तार

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

पाकुड़। मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान ने बुधवार को सदर प्रखंड में रफ्तार पकड़ ली।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ घर-घर पहुंचकर मतदाताओं के बीच गणना (इन्यूमरेशन) प्रपत्र का वितरण कर रहे हैं। इस दौरान वालंटियर्स एवं बीएलओ सहायकों ने भी मतदाताओं को प्रपत्र भरने और जमा करने में सहयोग किया।

अभियान की निगरानी बीएलओ पर्यवेक्षक लगातार कर रहे हैं, ताकि प्रत्येक पात्र मतदाता तक गणना प्रपत्र समय पर पहुंचे और उसका संग्रहण भी निर्धारित अवधि में हो सके। वालंटियर्स मतदाताओं को प्रपत्र भरने की प्रक्रिया समझाने के साथ आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध करा रहे हैं।

बीएलओ पर्यवेक्षक नारद मंडल ने रामचंद्रपुर पंचायत के गुलदाहा गांव स्थित बूथ संख्या-347 तथा नवादा पंचायत के बूथ संख्या-350 एवं 354 का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि संबंधित बूथों पर गणना प्रपत्र का वितरण जारी है और मतदाताओं से निर्धारित समय के भीतर प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराने की अपील की जा रही है।

बीडीओ सह सीओ अरविंद कुमार बेदिया ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण एवं संग्रहण कर रहे हैं।

उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि प्रपत्र में सही जानकारी भरें, नवीनतम फोटो चिपकाएं, हस्ताक्षर करें तथा भरा हुआ प्रपत्र बीएलओ को सौंपकर उसकी पावती अवश्य प्राप्त करें।

उन्होंने सभी बीएलओ, बीएलओ सहायकों, वालंटियर्स तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के बीएलए-2 प्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही मतदाता सूची पूरी तरह अद्यतन, पारदर्शी और त्रुटिरहित बन सकेगी।

नदियों से बालू का अवैध खनन जारी, राजस्व को लगाया जा रहा चूना

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

गिरिडीह। बिरनी प्रखंड के विभिन्न नदियों बराकर नदी व इरगा नदी के दलांगी, हरदिया, पंदनाखुर्द, चानो ,रजमनियां , बाराडीह ,झरखी, गारागुरो , खुरजियो, नगलो , जमडीहा, पेशम , विजयडीह आदि घाट में अवैध बालू खनन और परिवहन का कारोबार बेखौफ तरीके से हो रहा है। नाम नहीं छापने के शर्त पर स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि नाम अखबार में छपते ही तस्करों मारपीट व झूठा मुकदमा में फंसा देंगे, प्रशासन भी तस्करों को संरक्षण दे रहा है।

प्रखंड की संबंधित नदियों से प्रतिदिन अवैध रूप से बालू का उठाव कर ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों से खुलेआम परिवहन किया जा रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में न तो एनजीटी के निदेर्शों का पालन होता दिखाई दे रहा है और न ही खनन विभाग या प्रशासन की कार्रवाई का कोई भय बालू माफियाओं में नजर आता है।

दिनदहाड़े नदियों से बालू निकालकर विभिन्न स्थानों दूसरे प्रखंड धनवार देवरी, तिसरी, मरकच्चो, डुमरी, बगोदर, विष्णुगढ़ हजारीबाग तक पहुंचाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि प्रखंड में चल रहे कई सरकारी निर्माण कार्यों में भी ठेकेदार रायल्टी जमा करने के नाम पर अवैध स्रोतों से बालू मंगा रहा है। इससे सरकारी योजनाओं में नियमों के पालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि बालू वैध खनन पट्टों से लाया जा रहा है तो उसकी जांच और सत्यापन होना चाहिए।स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, खनन विभाग से अवैध बालू खनन और परिवहन पर तत्काल रोक लगाने,व दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग हो रहे बालू की जांच कराने की मांग की है, ताकि सरकार व विभाग को राजस्व घाटा न हो।

बराकर नदी के दलांगी घाट में करोड़ों की लागत से बन रहा नवनिर्मित पुल के पास से बालू का अवैध तरीके से उठाव हो रहा है। उसके बाद भी पुल निर्माण विभाग के पदाधिकारी चुप है।

आज गुल रहेगी बिजली

गढ़वा। डंडई विद्युत शक्ति उपकेंद्र में 11 केवी स्विच ब्रेकर लाइन की मेंटेनेंस, साफ-सफाई तथा 33 केवी का नया ब्रेकर लगाने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही चिनिया के 33 केवी फीडर में भी नया आउटगोइंग ब्रेकर स्थापित किया जाएगा। विद्युत विभाग के कर्मी आजाद खान ने बताया कि इस कार्य के कारण आज एवं 3 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक तथा दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि निर्धारित अवधि के दौरान आवश्यक कार्य पहले से निपटा लें तथा विद्युत विभाग के रखरखाव कार्य में सहयोग करें। विभाग ने बताया कि मेंटेनेंस एवं ब्रेकर स्थापना का उद्देश्य विद्युत आपूर्ति को अधिक सुरक्षित, सुचारु और विश्वसनीय बनाना है।

डीआरएम ने संघ की मांगों पर कार्रवाई का दिया आश्वासन

एक सप्ताह के भीतर जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की कही बात

नवबिहार टाइम्स संव्याददाता

धनबाद। रेलवे पार्किंग ठेकेदार द्वारा कथित मनमानी, अवैध वसूली, ई-रिक्शा चालकों के साथ दुर्व्यवहार तथा रेलवे स्टेशन क्षेत्र में अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था के विरोध में झारखंड ई-रिक्शा टोटो संघ द्वारा आज मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, धनबाद के समक्ष गुरूवार को विशाल धरना-प्रदर्शन किया गया। धरना में सैकड़ों की संख्या में ई-रिक्शा टोटो चालक एवं संघ के पदाधिकारी शामिल हुए।

धरना-प्रदर्शन के दौरान ई-रिक्शा चालकों ने रेलवे पार्किंग ठेकेदार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए अवैध वसूली बंद करने, निर्धारित पार्किंग शुल्क लागू करने, वैध रसीद देने, दुर्व्यवहार पर रोक लगाने तथा ई-रिक्शा पार्किंग व्यवस्था को नियमित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लंबे समय से चालक समुदाय को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बार-बार शिकायत एवं ज्ञापन देने के बावजूद रेलवे प्रशासन द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।

धरना के बाद मंडल रेल प्रबंधक, धनबाद द्वारा संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ गोलमेज वार्ता आयोजित की गई। वार्ता में संघ की ओर से रेलवे पार्किंग ठेकेदार द्वारा कथित अवैध वसूली, पार्किंग शुल्क की रसीद नहीं दिए जाने, निर्धारित दरों का पालन नहीं होने, यात्रियों को छोड़ने एवं लेने आने वाले ई-रिक्शाओं से शुल्क वसूली, स्टेशन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले वाहनों से जबरन शुल्क लेने, पार्किंग कर्मियों के दुर्व्यवहार, पार्किंग स्थल की बदहाल स्थिति तथा ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन नहीं बनाए जाने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया।

वार्ता के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने संघ की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया तथा कहा कि एक सप्ताह के भीतर पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ई-रिक्शा पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने एवं चालकों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने की बात भी कही। वार्ता समाप्त होने के बाद संघ के संरक्षक बैभव सिन्हा ने सम्मेलन कक्ष के बाहर धरना स्थल पर प्रतीक्षा कर रहे सैकड़ों ई-रिक्शा चालकों को वार्ता की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आंदोलन की एकता और शक्ति के कारण रेलवे प्रशासन को चालक समुदाय की समस्याओं पर गंभीरता से संज्ञान लेना पड़ा है। डीआरएम द्वारा एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई के आश्वासन की जानकारी मिलते ही उपस्थित चालक साथियों में उत्साह फैल गया और सभी ने एकजुट होकर आंदोलन की सफलता पर खुशी व्यक्त की।

संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि यह धरना केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि ई-रिक्शा चालकों के सम्मान, आजीविका और अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि चालक अब किसी भी प्रकार की मनमानी, धमकी, अवैध वसूली और अपमान को स्वीकार नहीं करेंगे।

संघ के संरक्षक बैभव सिन्हा ने कहा कि झारखंड ई-रिक्शा टोटो संघ ने हमेशा लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखी हैं। आज का विशाल प्रदर्शन यह स्पष्ट संदेश है कि यदि चालक समुदाय के साथ अन्याय होगा, तो संघ संगठित होकर उसका जवाब देगा।

मौके पर उपस्थित पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि डीआरएम द्वारा दिए गए एक सप्ताह के आश्वासन का संघ सम्मान करता है, लेकिन यदि निर्धारित समय के भीतर दोषी पार्किंग ठेकेदार एवं संबंधित कर्मियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तथा ई-रिक्शा पार्किंग व्यवस्था को पारदर्शी और नियमित नहीं किया गया, तो संघ आंदोलन को और व्यापक एवं निर्णायक रूप देगा।

संघ ने रेलवे प्रशासन से मांग की कि पार्किंग ठेकेदार की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कराई जाए, निर्धारित शुल्क का पालन सुनिश्चित हो, प्रत्येक भुगतान पर वैध रसीद दी जाए, केवल यात्रियों को छोड़ने-लेने अथवा स्टेशन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले ई-रिक्शाओं से जबरन शुल्क वसूली बंद हो, पार्किंग स्थल की सफाई एवं रखरखाव हो तथा ई-रिक्शा चालकों के लिए स्पष्ट एवं स्थायी पार्किंग व्यवस्था लागू की जाए। धरना-प्रदर्शन में संघ के संरक्षक बैभव सिन्हा, अध्यक्ष अनिल यादव, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मनोज सिंह, संस्थापक मुन्ना कुशवाहा, शैलेश कुमार, राजू वर्मा, अमित साव, राजेश सिंह, राजेश राम, पवन साव, धर्मेंद्र कुमार, मासूम अली, गुलजार अहमद, विष्णु कुमार सहित बड़ी संख्या में ई-रिक्शा चालक एवं संघ के सदस्य उपस्थित थे।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जिम्मे झारखंड टूरिज्म की ब्रांडिंग

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

दुमका। झारखंड में धार्मिक-पर्यटन को विकसित कर रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में हेमंत सरकार ने पहल तेज कर दी है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाओं को उभार देने के लिए बीते दिन रांची के जोन्हा वाटर फॉल पहुंच कर सोशल मीडिया पर कई तस्वीरों को साझा किए हैं।

इसके बाद नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने राज्य में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए तकरीबन 110 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को आधिकारिक तौर पर एप्रूव किया है जो झारखंड टूरिज्म का स्टेक होल्डर बनकर काम करेंगे।

ये सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर झारखंड की प्राकृतिक संपदा, खूबसूरती, धर्म, पर्यटन, कला व संस्कृति से जुड़े रील्स, वीडियो व अन्य अहम जानकारियों का स्क्रिप्ट तैयार कर डिजिटल माध्यम से इसकी जानकारी जन-जन तक पहुंचाएंगे।

इधर सरकार की मंशा के अनुरूप झारखंड की उपराजधानी दुमका में भी धर्म व पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल आने वाले दिनों तेज होने वाली है। बुधवार को दुमका समाहरणालय में आयोजित जिला पर्यटन संवर्द्धन परिषद की बैठक में कई अहम प्रस्ताव लिए गए हैं।

खास बात यह कि इस बैठक में मौजूद दुमका के सांसद व कई विधानसभा क्षेत्रों से आए विधायकों ने जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण, आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने को लेकर अहम सुझाव दिए हैं।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास के लिए व्यवहारिक एवं दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी। पर्यटन स्थलों तक बेहतर सड़क संपर्क, डिजिटल प्रचार-प्रसार, स्थानीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण, स्थानीय उत्पादों के विपणन तथा पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही स्थानीय युवाओं को पर्यटन गतिविधियों से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा।

सीकेडी 'साइलेंट किलर' के खिलाफ जागरूकता अभियान

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

धनबाद। भारत में क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी सीकेडी एक बड़े स्वास्थ्य संकट के रूप में उभर रही है। देश में 13.8 करोड़ से ज्यादा वयस्क सीकेडी से प्रभावित हैं और हर साल 2.2 लाख नए मरीजों को डायलिस की जरूरत पड़ती है। 2011 से 2023 के बीच 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में सीकेडी के मामले 11.12% से बढ़कर 16.38% हो गए हैं। सबसे चिंताजनक बात ये है कि 90% से अधिक लोगों का निदान तब होता है जब बीमारी अंतिम अवस्था में पहुंच जाती है। इसी 'साइलेंट किलर' से लड़ने के लिए डॉ. मिहिर किडनी केयर हॉस्पिटल पिछले 1 साल से झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के मरीजों को विशेषज्ञ किडनी देखभाल दे रहा है। ये धनबाद का एकमात्र समर्पित किडनी हॉस्पिटल है। डॉ. मिहिर कुमार ने कहा, ₹सीकेडी शुरूआती स्टेज में कोई लक्षण नहीं दिखाती। मरीज को तब पता चलता है जब डायलिस या ट्रांसप्लांट ही विकल्प बचता है। हमारा मिशन है कि हर डायबिटीज और बीपी के मरीज हर साल यूरिन टेस्ट जरूर कराएं।

जापान विज्ञान कार्यक्रम में पहुंची जागृति, झारखण्ड का नाम किया रौशन

स्वाध्याय से हासिल किया मुकाम

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

गोड्डा। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, इस उक्ति को स्थानीय प्लस टू उच्च विद्यालय की पूर्व छात्रा जागृति कुमारी ने सच साबित कर दिखाया है।

साधारण परिवार से आने वाली सरकारी विद्यालय की इस मेधावी छात्रा ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर जापान विज्ञान कार्यक्रम में भाग लेकर न केवल विद्यालय और परिवार, बल्कि पूरे प्रखंड का नाम रोशन किया है।

गुरुवार को विद्यालय परिसर में आयोजित शिक्षक-अभिभावक गोष्ठी सह सम्मान समारोह में जागृति को प्रशस्ति पत्र तथा उनके माता-पिता को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। जागृति कुमारी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि 24 में से 30 जून तक तक छह दिन का जापान प्रवास के दौरान उन्हें जैक्सा स्पेस सेंटर, रिकेन इंस्टीट्यूट सहित कई वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और नवाचार केंद्रों का भ्रमण कराया गया। वहां अंतरिक्ष विज्ञान, आधुनिक तकनीक, सुपर कंप्यूटर और वैज्ञानिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि जापान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेंसी के कार्यक्रम के तहत उन्हें विज्ञान और तकनीक के विभिन्न पहलुओं को करीब से समझने का अवसर मिला। जापान की स्वच्छता, अनुशासन, समय पालन और वहां के लोगों का व्यवहार उन्हें बेहद प्रभावित कर गया।

जागृति शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं। वर्ष 2025 में मैट्रिक परीक्षा में प्लस टू उच्च विद्यालय, पोड़ैयाहाट से प्रखंड में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उन्होंने विद्यालय का गौरव बढ़ाया था। बिना किसी ट्यूशन के केवल स्वाध्याय के बल पर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की।

वर्तमान में वह प्लस टू उच्च विद्यालय, पथरगामा में अध्ययनरत हैं। जागृति के पिता राजेश रंजन मशरूम विक्रेता हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी होने के साथ सिलाई का कार्य करती हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी।जागृति ने केंद्र एवं राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं में भी सफलता प्राप्त की है और वर्तमान में केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति का लाभ ले रही हैं। वर्ष 2025 में उन्हें जागरण जीनियस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।

प्रधानाध्यापक नीतीश कुमार ने कहा कि जागृति ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन के आगे आर्थिक अभाव बाधा नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि जागृति ने विद्यालय, परिवार और पूरे प्रखंड का मान बढ़ाया है। उनका सपना इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना है और वह उसी लक्ष्य को लेकर निरंतर मेहनत कर रही हैं।

समारोह में जागृति के पिता राजेश रंजन ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने बेटी की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। विद्यालय के शिक्षकों के मार्गदर्शन और नियमित अध्ययन की बदौलत ही उनकी बेटी आज इस मुकाम तक पहुंची है। बताया गया कि करीब दो माह बाद बेंगलुरु स्थित आईटी संस्थान में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में भी जागृति को आमंत्रित किया गया है, जिसमें जापान विज्ञान कार्यक्रम में शामिल सभी छात्र-छात्राएं भाग लेंगे।

प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया मल्टी-एसेट एक्टिव एफओएफ

मुंबई, एजेंसी। आप म्यूचुअल फंड के न्यू फंड ऑफर की तालाश में रहते हैं तो आपके लिए निवेश का एक मौका है। प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने प्रूडेंशियल मल्टी-एसेट एक्टिव स्रह्रस्र का एनएफओ लॉन्च किया है। यह एक ओपन-एंडेड 'फंड ऑफ फंड्स' स्कीम है जो मुख्य रूप से एक्टिव इक्विटी-ओरिएंटेड स्कीम, डेट-ओरिएंटेड स्कीम और गोल्ड श्वङ्कस्र/सिल्वर श्वङ्कस्र की यूनिट्स में निवेश करती है।

एनएफओ में कब तक होगा निवेश

प्रूडेंशियल मल्टी-एसेट एक्टिव निवेश के लिए खुल गया है। निवेशक इसमें आगामी 14 जुलाई तक निवेश कर सकेंगे। उसके बाद यह बंद हो जाएगा। बताया जा रहा है कि यह स्कीम मौजूदा बाजार की स्थितियों, वैल्यूएशन संकेतों और मैक्रो-इकोनॉमिक ट्रेंड्स के आधार पर इन एसेट क्लास में अपना एक्सपोजर एडजस्ट करेगी।

एक में कई फायदे

प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एस. नरेन का कहना है 'अलग-अलग एसेट क्लास आर्थिक और मार्केट साइकल के दौरान अलग-अलग तरह से परफॉर्म करते हैं, इसलिए अनुशासित एसेट एलोकेशन लंबे समय के निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। प्रूडेंशियल मल्टी-एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड एक ही पोर्टफोलियो में एक्टिव इक्विटी, डेट और गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर, ईटीएफ को एक साथ लाता है। साथ ही मार्केट की स्थितियों के बदलने पर एलोकेशन को एक्टिव रूप से एडजस्ट करने

के लिए हमारे खास वैल्यूएशन और मैक्रो-इकोनॉमिक मॉडल का इस्तेमाल करता है। इसका मकसद निवेशकों को एक व्यवस्थित और रिसर्च-आधारित निवेश प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न एसेट क्लास में मौजूद अवसरों का लाभ उठाने में मदद करना है, जिससे निवेश का अनुभव अधिक सुसंगत बन सके। ' आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी-एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड एक ही पोर्टफोलियो में एक्टिव इक्विटी, डेट और गोल्ड को एक साथ लाता है।

कैसे होता है अलोकेशन

नरेन का कहना है कि इकोनॉमिक साइकल, महंगाई, ब्याज दरों और मार्केट के मूड के आधार पर अलग-अलग एसेट क्लास का परफॉर्मेंस अलग-अलग होता है। यह स्कीम यह अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करती कि अगली बार कौन-सी एसेट क्लास बेहतर परफॉर्मेंस देगी। बल्कि यह इक्विटी, डेट और गोल्ड में उनकी तुलनात्मक आकर्षकता के आधार पर निवेश का अलोकेशन करती है।

डायवर्सिफिकेशन कैसे होता है

- यह स्कीम तीन अलग-अलग पोर्टफोलियो उद्देश्यों को मिलाती है
- लंबे समय में संपत्ति बनाने की क्षमता के लिए इक्विटी का चयन
- काफी हद तक स्थिर आय के लिए डेट स्कीमों का चयन

डायवर्सिफिकेशन और महंगाई से संभावित बचाव के लिए सोना और चांदी में निवेश

कितना हिस्सा कहां जाएगा : इस फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन फ्रेमवर्क में ये शामिल हैं एक्टिव इक्विटी-ओरिएंटेड स्कीम की यूनिट्स में 30-80 प्रतिशत एक्टिव डेट-ओरिएंटेड स्कीम की यूनिट्स में 10-60 प्रतिशत गोल्ड और/या सिल्वर में 10-30 प्रतिशत।

छह दिन पहले ही आई है ईपीएफओ की नई स्कीम, करीब 7 करोड़ लोगों पर डालेगी असर

नईदिल्ली, एजेंसी। कर्मचारी भविष्य निधि के 7 करोड़ से अधिक मेंबर्स के लिए नई स्कीम 26 जून 2026 से लागू हो गई है। यह 1952 की पुरानी स्कीम की जगह आई है। इसका मकसद नौकरी करते हुए भी जरूरत के समय पैसे निकालने को आसान बनाना, लेकिन बुढ़ापे की बचत को भी सुरक्षित रखना है। ईपीएफ खाते में से जितना पैसा आप निकाल सकते हैं, उसमें से कम से कम 25 प्रतिशत खाते में रहना चाहिए। नियमों के मुताबिक बाकी 75 प्रतिशत पैसा ही निकाला जा सकता है। मान लीजिए अगर आपके खाते में 1 लाख रुपए है, तो 25,000 रुपए (25 प्रतिशत) जमा रहना होगा। बाकी 75,000 रुपए निकासी के लिए उपलब्ध होंगे। तभी जब आप नौकरी छोड़ चुके हों और कम से कम 2 महीने (60 दिन) से बेरोजगार हों। इसमें आपकी और मालिक की प्लस ब्याज की पूरी राशि मिलती है। अगर आपकी कुल नौकरी 10 साल से कम है, तो आप पेंशन का एकमुश्त पैसा निकाल सकते हैं। 10 साल से ज्यादा होने पर आपको स्कीम सर्टिफिकेट मिलेगा और 58 साल की उम्र में मासिक पेंशन मिलेगी। ऊपर बताए गए कारणों (इलाज, शादी, मकान, आपदा) के लिए आप यह फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन तो 3-7 कामकाजी दिन। ऑटो-मोड वाले दावे 72 घंटे में। ऑफलाइन (कागजी) दावे में 20 दिन तक लग सकते हैं। ऑनलाइन मंजूरी के बाद 7 से 15 वर्किंग डेज में पैसा खाते में आ जाता है। हर चरण (सबमिट, अप्रूव, डिस्बर्स) पर आता है।

कई दिन की गिरावट के बाद संभला सोना, चांदी भी हुई महंगी

नईदिल्ली, एजेंसी। पश्चिम एशिया में शांति के लिए अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में तेजी आई है। इससे कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई है। इस बीच सोने की कीमत में आज मिलाजुला रुख देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर सोने की कीमत में मामूली गिरावट आई है जबकि सर्राफा बाजार में अच्छी खासी तेजी दिख रही है। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में सोना 500 रुपये से अधिक गिर गया। 5 अगस्त की डिलीवरी वाला सोना पिछले सत्र में 1,44,430 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था और आज यह 1,43,882 रुपये पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 1,43,795 रुपये तक गिरा। सुबह 10.45 बजे यह 605 रुपये की गिरावट के साथ 1,43,825 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। इंटरनेशनल मार्केट में पिछले सेशन में सोना 23 जून के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा था। स्पॉट गोल्ड 0.7 प्रतिशत बढ़कर 4,057.92 प्रति औंस हो गया। हालांकि, अगस्त डिलीवरी के लिए यूएस गोल्ड फ्यूचर्स 0.3 प्रतिशत गिरकर 4,070.10 पर आ गया। इस बीच स्पॉट सिल्वर 1.6 प्रतिशत बढ़कर 60.06 प्रति औंस हो गई।

अनिल अग्रवाल के 4 शेयरों में तूफानी तेजी

नई दिल्ली, एजेंसी। अनिल अग्रवाल की वेदांता लिमिटेड के कारोबार के बंटवारे के बाद हाल में लिस्ट हुए कंपनी के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। इंट्राडे ट्रेडिंग पर लगी पाबंदी हटते ही इन शेयरों में तूफानी तेजी आई। इसका असर यह हुआ कि ग्रुप की कंपनी वेदांता ऑयल एंड गैस में 20 फीसदी का अपर सर्किट लग गया। 15 जून 2026 को शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद नियम के मुताबिक इन चारों शेयरों को शुरुआती 10

ट्रेडिंग सेशन के लिए टी २ टी सेगमेंट में रखा गया था। इस सेगमेंट में केवल डिलीवरी आधारित काम होता था और इंट्राडे (उसी दिन खरीद-बिक्री) पर रोक थी, साथ ही सर्किट लिमिट भी सिर्फ 5 प्रतिशत थी। अब सामान्य सेगमेंट में आने के बाद इनमें इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू हो गई है, जिससे बाजार में लिक्विडिटी और वॉल्यूम काफी बढ़ गया है।

क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए?

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेशकों को भावनाओं में बहकर ऊंचे स्तरों पर खरीदारी करने से बचना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेदांता के डीमर्जर के बाद इन कंपनियों को लेकर निवेशकों का रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव है। हालांकि, इतनी बड़ी और तेज बढ़त के बाद शॉर्ट-टर्म में थोड़ी मुनाफावसूली हो सकती है। नए निवेशकों को इस तेजी के पीछे भागने के बजाय गिरावट का इंतजार करना चाहिए ताकि जोखिम कम रहे।

एसपी ग्रुप ने टाटा को दिया नया सिरदर्द!

टाटा संस में हिस्सेदारी के बदले जारी करेगा 25,500 करोड़ के बॉन्ड

नई दिल्ली, एजेंसी। टाटा संस देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। इसमें शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप 18.37 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा माइनोरिटी स्टेकहोल्डर है। ग्रुप का कहना है कि वह ?25,500 करोड़ का बॉन्ड इश्यू लाने के लिए टाटा संस में अपनी इक्विटी का एक हिस्सा इस्तेमाल करेगा। इसकी शर्तों के मुताबिक, इश्यू के 18 महीनों के अंदर टाटा संस को

इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की घोषणा करनी होगी या स्क ग्रुप को अपनी ओनरशिप को लेकर टाटा होल्डिंग कंपनी के साथ समझौता करना होगा। ईटी एक रिपोर्ट के मुताबिक एसपी ग्रुप सोमवार को बॉन्ड इश्यू लाने की तैयारी में है। बैंकिंग इंडस्ट्री के एक अधिकारी ने कहा कि बॉन्ड की शर्तों के में ही इस बात को माना गया है कि टाटा संस की हिस्सेदारी का मॉनेटाइजेशन रिपेमेंट के केंद्र में है। आरबीआई के स्पष्टीकरण से टाटा संस की लिस्टिंग की संभावना बढ़ गई है। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इससे एसपी ग्रुप को कुछ राहत मिली है।

लिस्टिंग पर तकरार

आरबीआई ने हाल में अपर-लेयर एनबीएफसी के लिए एक नई परिभाषा लागू की। इसके तहत 1 लाख करोड़ से ज्यादा एसेट वाली कंपनियों के लिए शेयरों की पब्लिक लिस्टिंग जरूरी है। इससे टाटा संस के प्राइवेट बने रहने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। टाटा संस का एसेट बेस 1.75 लाख करोड़ से ज्यादा है। आरबीआई ने इसे अपर लेयर-एनबीएफसी के तौर पर क्लासिफाई किया गया था। टाटा संस में मैज्योरिटी स्टेकहोल्डर टाटा ट्रस्ट्स ने पहले एक प्रस्ताव पास किया था कि टाटा संस को अनलिस्टेड रहना चाहिए। कंपनी के दो वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने लिस्टिंग की वकालत करते हुए कहा कि इसका अच्छा नतीजा होगा। हालांकि टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने लिस्टिंग का कड़ा विरोध किया है। एक सूत्र ने कहा कि बॉन्ड इश्यू सोमवार को लॉन्च किया जाएगा और अगले हफ्ते तक सेटलमेंट होने की उम्मीद है। एसपी ग्रुप के प्रवक्ता ने ईटी के ईमेल पर टिप्पणी के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया। जीरो कूपन, अनलिस्टेड और अनरेटेड नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर इक्विजेन इन्वेस्टमेंट द्वारा जारी किए जाएंगे।

11.5 बिलियन का प्लांट लगाने की तैयारी में गौतम अडानी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस गौतम अडानी एल्युमीनियम सेक्टर में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक अडानी ग्रुप और अबु धाबी की इन्वेस्टमेंट कंपनी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी 11.5 बिलियन का निवेश करके एक बड़ा एल्युमीनियम प्लांट बनाने की योजना बना रहे हैं। इससे भारत की कुल क्षमता में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। अडानी के इस प्लांट से हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और वेदांता एल्युमीनियम को कड़ी टक्कर मिल सकती है। मेटल सेक्टर में अडानी ग्रुप का यह दूसरा वेंचर होगा। गुजरात में उनका कॉपर स्मेल्टर पिछले साल शुरू हुआ था। अडानी अपने बढ़ते इन्फ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के लिए कमोडिटी सप्लाई सुरक्षित करना चाहते हैं। एल्युमीनियम सेक्टर में उतरने की योजना भी उसी रणनीति का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक अडानी और मिलकर ओडिशा में 2 मिलियन टन से ज्यादा सालाना क्षमता वाला एल्युमीनियम स्मेल्टर बनाने के लिए कर्ज इक्विटी के जरिए निवेश करेंगे।

अडानी ग्रुप ने इस बारे में भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। यह भारत के मेटल और मिनरल सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश होगा। यह फैसिलिटी एक इंटीग्रेटेड यूनिट होगी जिसमें स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग दोनों शामिल

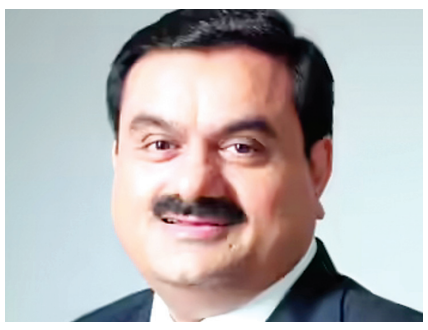

होंगे। साथ ही एल्युमीनियम प्रोजेक्ट में एक कैप्टिव पावर प्लांट भी शामिल होगा। लॉजिस्टिक्स के लिए ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित धामरा पोर्ट का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। इस पोर्ट का मालिकाना हक अडानी ग्रुप के पास है। चीन के बाद भारत दुनिया में एल्युमीनियम का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। पिछले साल भारत का कुल उत्पादन 4.2 मिलियन टन रहा। इस दौरान देश में 5.5 मिलियन टन एल्युमीनियम की खपत हुई। भारत में प्रति व्यक्ति खपत 3.4-3.9 किलोग्राम है जबकि ग्लोबल एवरेज 8-12 किलोग्राम है।

एल्युमीनियम का बाजार

ओडिशा में एल्युमीनियम प्लांट पर 11.5 अरब डॉलर निवेश करेंगे अडानी देश के कुल बॉक्साइट रिजर्व का करीब 60 फीसदी हिस्सा ओडिशा में है चीन के बाद भारत दुनिया में एल्युमीनियम का बड़ा उत्पादक है साल 2047 तक भारत सालाना 37 मिलियन टन का लक्ष्य लेकर चल रहा है

मैन्युफैक्चरिंग पर जोर : सरकार का मैन्युफैक्चरिंग पर जोर है। मांग बढ़ने की उम्मीद में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और वेदांता एल्युमीनियम जैसी कंपनियां भी अपनी क्षमता बढ़ा रही हैं ताकि घरेलू जरूरतें पूरी हो सकें और आयात पर निर्भरता कम हो। ग्लोबल नेचुरल रिसोर्स कंपनी रियो टिंटो, रूस मेटल्स एंड मैटीरियल्स के साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी-पावर्ड एल्युमीनियम प्रोजेक्ट शुरू करने पर विचार कर रही है। इस प्रोजेक्ट को ग्रीनको ग्रुप के फाउंडर्स

रतन टाटा के सबसे करीबी सहयोगी ने छोड़ा फैमिली ऑफिस! टाटा ग्रुप में हड़कंप

नईदिल्ली, एजेंसी। टाटा ग्रुप के दिवंगत चेयरमैन रतन टाटा के सबसे करीबी सहयोगियों में गिने जाने वाले मेहली मिस्त्री ने अब रतन टाटा के फैमिली ऑफिस एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड से भी इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब कुछ महीने पहले ही उन्हें टाटा ट्रस्ट्स से भी हटा दिया गया था। माना जा रहा है कि इस कदम के साथ मेहली मिस्त्री और टाटा ग्रुप के बीच सालों पुराना संबंध लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

मेहली मिस्त्री ने 30 जून 2026 को अपने इस्तीफे का पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने के कारण वह 1 जुलाई 2026 से एसोसिएट्स के निदेशक पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि, उन्होंने अपने पत्र में किसी विवाद का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके इस फैसले को टाटा ग्रुप से लगातार बढ़ती दूरी के रूप में देखा जा रहा है। आरएनटी एसोसिएट्स कोई सामान्य कंपनी नहीं है। इसकी स्थापना

2009 में रतन टाटा ने अपने व्यक्तिगत निवेश के लिए की थी। इसी कंपनी के जरिए रतन टाटा ने देश के कई बड़े स्टार्टअप्स में निवेश किया था। पेटीएम ओला ब्लूस्टोन जैसे कई चर्चित स्टार्टअप्स में एसोसिएट्स की हिस्सेदारी रही है। कंपनी को अपनी आय मुख्य रूप से डिविडेंड और कंसल्टेंसी सेवाओं से होती है। रतन टाटा के निधन से पहले उन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों और निवेशों को व्यवस्थित करने के लिए और का गठन किया था। आज की हिस्सेदारी इन्हीं संस्थाओं के पास है। इन ट्रस्टों में टाटा समूह के कई वरिष्ठ अधिकारी और रतन टाटा के परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं। फिलहाल एसोसिएट्स के बोर्ड में शिरीन जेजीभॉय, डिआना जेजीभॉय, जमशेद पोंचा और सिद्धार्थ शर्मा जैसे सदस्य शामिल हैं। मेहली मिस्त्री मार्च 2023 में इस बोर्ड में शामिल हुए थे, लेकिन अब उन्होंने भी पद छोड़ दिया है। दरअसल, मेहली मिस्त्री और टाटा ट्रस्ट्स के बीच मतभेद पिछले साल सामने आए थे। नवंबर 2025 में उन्हें सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट समेत प्रमुख टाटा ट्रस्ट्स से हटा दिया गया था। इसके बाद उन्होंने इस फैसले को महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के सामने चुनौती दी। दिलचस्प बात यह है कि मेहली मिस्त्री ने साफ किया है कि उनका उद्देश्य टाटा ट्रस्ट्स में दोबारा वापस जाना नहीं है।

रूस ने भारत से खरीदा 60000 टन पेट्रोल, दो बड़े टैंकर भी हुए रवाना, पुतिन के देश में मचा हाहाकार

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत को भर-भरकर कच्चे तेल के टैंकर भेजना वाला रूस पेट्रोल की कमी से तरस रहा है। अब भारत रूस की मदद के लिए आगे आया है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत ने रूस को 60000 मीट्रिक टन पेट्रोल भेजा है। वहीं अभी और पेट्रोल भेजा जा रहा है। दरअसल, यूक्रेन इस समय रूस के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहा है। इससे रूस में ईंधन की भारी किल्लत हो गई है। इससे निपटने के लिए रूस ने अब भारत से समुद्र के रास्ते पेट्रोल का आयात करना शुरू कर दिया है।

ईंधन की करनी पड़ रही राशनिंग: रूस के सभी 11 टाइम जोन में ईंधन की कमी इस कदर फैल गई है कि वहां ईंधन की राशनिंग करनी पड़ रही है। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं और पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच, क्रेमलिन (रूसी राष्ट्रपति कार्यालय) ने मंगलवार को कहा कि वह स्वीकार्य कीमतों पर ईंधन आयात करने के लिए कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है।

भारत से भेजी जा चुकी है पेट्रोल की खेप एक उद्योग सूत्र के अनुसार भारत पहले

ही रूस को कम से कम 60,000 मीट्रिक टन पेट्रोल भेज चुका है। वहीं एक अन्य सूत्र ने बताया कि 30,000 से 40,000 टन की क्षमता वाले दो जहाजों को रवाना किया जा चुका है। तीसरे सूत्र ने खुलासा किया कि रूस पड़ोसी देश बेलारूस सहित कई देशों से हर महीने कुल 4,00,000 टन पेट्रोल आयात करने की योजना बना रहा है। बेलारूस पहले से ही रूस को ईंधन की आपूर्ति कर रहा है। भारतीय रिफाइनरियों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से अन्य स्रोतों से होने वाली आपूर्ति पर पड़े असर को कम करने के लिए रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है।

राष्ट्रपति पुतिन ने मानी किल्लत की बात

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को सरकारी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान स्वीकार किया कि रूसी तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण कुछ क्षेत्रों में ईंधन की कमी हुई है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस स्थिति से निपटा जा रहा है। धड़ाधड़ तिजोरी से निकालकर लोग गला रहे सोना, गोल्ड की डिमांड भी 70 प्रतिशत घटी, क्यों मचा हड़कंप रॉयटर्स की गणना और उद्योग सूत्रों के मुताबिक, बेलारूस ने रेल मार्ग के जरिए रूस को पेट्रोल के निर्यात में भारी बढ़ोतरी की है। जून के पहले पखवाड़े में यह आपूर्ति 70,000 टन से अधिक हो गई, जो मई के पहले पखवाड़े में दर्ज की गई मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। एक तरफ जहां रूस भारत से पेट्रोल खरीद रहा है, वहीं दूसरी तरफ जून महीने में भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल का आयात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है।

एसबीआई का बड़ा डिजिटल अपग्रेड; अब योनो पर एआई फीचर्स, एक साथ खोलें सेविंग, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने बुधवार को अपने 71वें बैंक दिवस के अवसर पर ग्राहकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित कई नई डिजिटल सुविधाएं लॉन्च करने की घोषणा की है। बैंक ने अपने योनो प्लेटफॉर्म को नए ग्राहक अनुभव, एआई-आधारित क्षमताओं और कई उद्योग में पहली बार पेश किए गए फीचर्स के साथ और अधिक उन्नत बनाया है।

एसबीआई ने बताया कि अब नए ग्राहक एक ही डिजिटल प्रक्रिया (3-इन-1 ऑनबोर्डिंग) के जरिए सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ खोल सकेंगे। इससे निवेश की शुरुआत पहले की तुलना में अधिक आसान और तेज हो जाएगी।

ग्राहकों को मिलेंगी ये भी सुविधाएं

पात्र ग्राहक अब बिना बैंक शाखा जाए अपने बचत खाते को ऑनलाइन कॉरपोरेट सैलरी अकाउंट में बदल सकेंगे या पहले से मौजूद सैलरी अकाउंट को भी ऑनलाइन अपग्रेड कर सकेंगे। बैंक ने योनो पर उद्योग में पहली बार सस्टेनेबिलिटी जर्नी नाम का फीचर भी लॉन्च किया है। इसके जरिए ग्राहक डिजिटल बैंकिंग लेनदेन के जरिए होने वाली कार्बन उत्सर्जन में बचत को ट्रैक कर सकेंगे और हर महीने अपना ग्रीन स्कोर भी देख सकेंगे। योनो में फाइनेंशियल फिटनेस स्कोर की भी सुविधा जोड़ी गई है। यह फीचर ग्राहकों को उनके बैंक खातों, लोन, निवेश, बीमा और खर्च के पैटर्न का एकीकृत विश्लेषण उपलब्ध कराएगा, जिससे वे अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।

ये ट्रांजेक्शन भी देख सकेंगे: एसबीआई ने अपने योनो बिजनेस प्लेटफॉर्म पर ईट्रेड सुविधा का भी विस्तार किया है। अब बैंक की पूरी ट्रेड फाइनेंस सेवाएं मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। इसके जरिए कॉरपोरेट और एमएसएमई ग्राहक कहीं से भी सुरक्षित तरीके से इनलैंड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड फाइनेंस से जुड़े लेनदेन देख, ट्रैक और अधिकृत कर सकेंगे। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी।

'बिग बॉस' और 'लॉक अप' से 'अलायंस' की तुलना होने पर बोले कुणाल खेमू

कुणाल खेमू ने कहा कि बिग बॉस ने इंडियन रियलिटी टीवी में अपनी एक अलग पहचान बना ली है और आज हर शो की सफलता को उसी से तुलना करके देखा जाता है। लेकिन उनका मानना है कि 'अलायंस' बाकी शोज से अलग है। दर्शकों को नया स्वाद मिल सके उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा, 'आपको सिर्फ अलग दिखने के लिए अलग होने की जरूरत नहीं है। हम एक फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं और उसे इसलिए चुना गया क्योंकि वह आज के शोज से अलग है। फिल्मों की तरह, जब कोई चीज चलती है तो हर कोई वैसा ही करना चाहता है। रियलिटी शोज इसलिए बनते हैं क्योंकि लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। अगर कोई नहीं देखता, तो ये बनते ही नहीं। हर कोई कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है ताकि दर्शकों को नया स्वाद मिल सके।'

क्यों शो के होस्ट बने कुणाल

कुणाल ने यह भी बताया कि आखिर उन्होंने रियलिटी शो में होस्ट के तौर पर डेब्यू करने का फैसला क्यों लिया। उन्होंने कहा, 'मुझे हमेशा यह जानने की उत्सुकता थी कि ये शोज बनते कैसे हैं और इनके पीछे क्या होता है। सामने बैठकर ड्रामा को अनफोल्ड होते देखना कैसा होता होगा? रियलिटी टीवी को लेकर हमेशा एक सवाल रहता है– क्या ये स्क्रिप्टेड होता है या नहीं? कम से कम अब मुझे इसका जवाब मिल जाएगा।' हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि शो का अनस्क्रिप्टेड होना उनके लिए जरूरी नहीं था, और वह खुले दिमाग के साथ इस प्रोजेक्ट में आए।

बता दें कि 'अलायंस' 26 जून को प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुका है। इस शो में रवि किशन, जैद दरबार, नीति टेलर, मिनी माथुर, डॉली जावेद, कुशाल टंडन, अर्सलान गोनी, पायल गेमिंग, सब्बी सूरी, रुही दोसानी, रिव्वा किशन, डेजी शाह और वंशज जैसे कई कलाकार नजर आ रहे हैं।

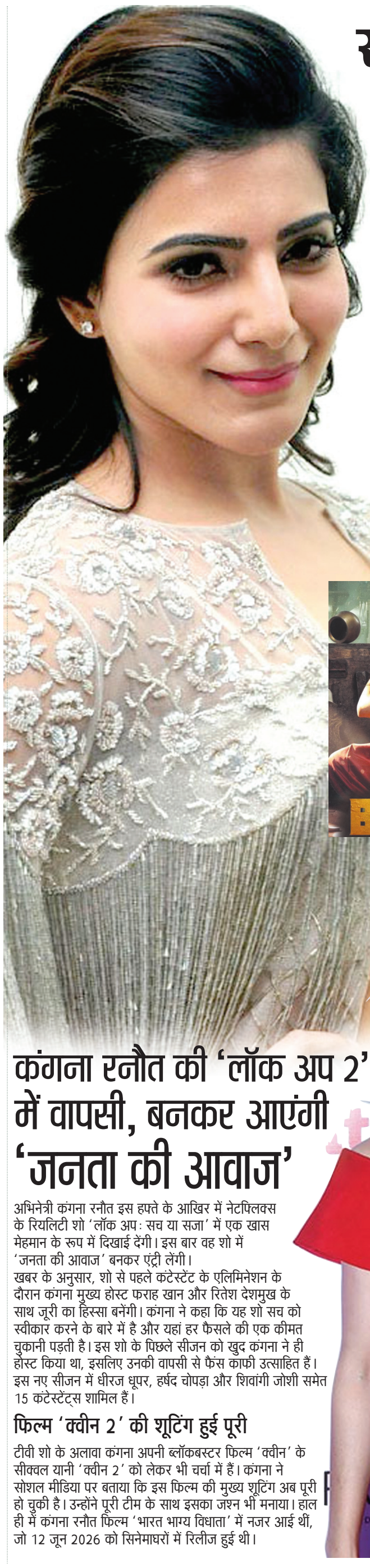

सामंथा के फैंस के लिए खुशखबरी, 'मां इंटी बंगारम' का बनेगा सीक्वल

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'मां इंटी बंगारम' का सीक्वल बनने वाला है। इस बात की पुष्टि खुद फिल्म के राइटर राज निदिमोरू ने की है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा।

'मां इंटी बंगारम' की जबरदस्त सफलता के बाद विजाग में एक ग्रैंड सक्सेस मीट रखा गया था। इसी दौरान राज निदिमोरू ने फैंस को सरप्राइज देते हुए बताया कि फिल्म का दूसरा पार्ट भी आएगा। राज ने पहले वहां मौजूद लोगों से पूछा कि क्या वे इस कहानी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। जैसे ही लोगों ने जोरदार तालियां और चीयर किया, उन्होंने सीक्वल की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, 'मेरे दिमाग में पहले से एक आइडिया है। वही टीम इस पर काम करेगी। पहली बार मुझे किसी फिल्म का दूसरा पार्ट बनाने की प्रेरणा मिली है। इसमें दोगुना मजा और दोगुना एक्साइटमेंट होगा। आगे चलकर मैं इसके बारे में और जानकारी दूंगा।'

'मां इंटी बंगारम' को मिल रहा प्यार

राज ने यह भी बताया कि 'मां इंटी बंगारम' को लोगों से इतना प्यार मिला कि उन्हें अपने पुराने हिट प्रोजेक्ट्स से भी ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि यह फिल्म सीधे दिल को छू गई। नंदिनी रेड्डी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सामंथा रुथ प्रभु के साथ गुलशन देवैया, श्रीमुखी और दिगंत मंचले नजर आए। इस फिल्म को सामंथा, राज निदिमोरू और हिमांशु ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो यह फिल्म महिला लीड पर आधारित फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। पहले हफ्ते में ही इसने भारत में करीब 35 करोड़ रुपये की कमाई की और दुनियाभर में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया।

'मां इंटी बंगारम' की कहानी

1980 के दौर पर आधारित इस कहानी में सामंथा 'स्वर्णा' का किरदार निभा रही हैं, जो अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ एक डॉक्टर से शादी करती है। शुरुआत में उसे ससुराल वालों का प्यार नहीं मिलता, लेकिन धीरे-धीरे वह सबका दिल जीत लेती है। तभी उसका अतीत लौटकर उसकी जिंदगी में उथल-पुथल मचा देता है।

कंगना रनौत की 'लॉक अप 2' में वापसी, बनकर आएंगी 'जनता की आवाज'

अभिनेत्री कंगना रनौत इस हफ्ते के आखिर में नेटफिलक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में एक खास मेहमान के रूप में दिखाई देंगी। इस बार वह शो में 'जनता की आवाज' बनकर एंट्री लेंगी।

खबर के अनुसार, शो से पहले कंटेस्टेंट के एलिमिनेशन के दौरान कंगना मुख्य होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख के साथ जूरी का हिस्सा बनेंगी। कंगना ने कहा कि यह शो सच को स्वीकार करने के बारे में है और यहां हर फैसले की एक कीमत चुकानी पड़ती है। इस शो के पिछले सीजन को खुद कंगना ने ही होस्ट किया था, इसलिए उनकी वापसी से फैंस काफी उत्साहित हैं। इस नए सीजन में धीरज धूपर, हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी समेत 15 कंटेस्टेंट्स शामिल हैं।

फिल्म 'क्वीन 2' की शूटिंग हुई पूरी

टीवी शो के अलावा कंगना अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'क्वीन' के सीक्वल यानी 'क्वीन 2' को लेकर भी चर्चा में हैं। कंगना ने सोशल मीडिया पर बताया कि इस फिल्म की मुख्य शूटिंग अब पूरी हो चुकी है। उन्होंने पूरी टीम के साथ इसका जश्न भी मनाया। हाल ही में कंगना रनौत फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नजर आई थीं, जो 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

पैपराजी पर जमकर भड़कीं नेहा धूपिया

'ये बदतमीजी से बैकशॉट कौन लेता है तुम लोगों में से? कौन लेता है? बंद करो।' सोमवार रात एक इवेंट में शामिल हुई नेहा धूपिया ने सख्ती से यह बात पैपराजी के सामने कही। नेहा इस बात से बहुत नाराज हैं कि कई पैपराजी एक्ट्रेसेस के बैक शॉट लेते हैं, जो बहुत ही खराब ढंग से लिए जाते हैं। वायरल वीडियो में नेहा कहती हैं, 'मेरा बैक शॉट नहीं लेना है। किसी का भी बैक शॉट नहीं लेना है। बोल बोल कर थक गए हैं। बैग उठाकर, किताब उठाकर, पीछे चलकर देख लिया। यह सब नहीं चलेगा अब। बंद करो यह सब। हमलोग बहुत इज्जत से बात करते हैं, आप लोगों से। आप लोग यह सब मत करो।'

यह नई बात नहीं है कि पैपराजी के बैक शॉट लेने की आदत से एक्ट्रेसेस परेशान हैं। पहले भी गौहर खान, भारती सिंह इस मामले पर खुलकर बात कर चुकी हैं। गौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पैपराजी को लताड़ा था। गौहर ने कहा था, 'क्या पैप्स छेड़छाड़ के कल्चर को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं जो लगातार अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं। आप लोग अपनी लिमिट पार नहीं कर सकते हैं।' वहीं कॉमेडियन भारती सिंह ने भी अपने शो 'लाफ्टर शेफ 2' में पैपराजी की क्लास ली थी।

रियलिटी शो 'अलायंस' में एंट्री पर सोहेल खान को क्यों सता रहा डर?

बॉलीवुड एक्टर और फिल्ममेकर सोहेल खान जल्द ही रियलिटी शो 'अलायंस' में शामिल हैं। इस शो को कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं। सोहेल खान कई टीवी शो में बतौर जज तो हिस्सा ले चुके हैं, मगर यह पहला मौका है जब वे प्रतिभागी के तौर पर जुड़ेंगे। हाल ही में अपने नए सफर पर सोहेल खान ने बात की। साथ ही यह भी बताया कि उन्हें एक डर सता रहा है।

मुझे झूठ बोलना नहीं आता

सोहेल ने कहा कि उन्हें गेम खेलना और लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं आता, इसलिए उन्हें डर है कि कहीं वे पहले हफ्ते में ही शो से बाहर न हो जाएं। सोहेल खान ने कहा, 'मैं मतलब ज्यादा सोचता नहीं हूं, मन में जो सच है वही करता हूं, तो मेरा एक ही थोड़ा सा डर है के मुझे झूठ बोलना और गेम्स खेलना नहीं आता। हेरफेर नहीं आता तो मुझे लगता है में पहले हफ्ते ही आउट हो जाऊंगा। कोई भी मुझे ऐसे पकड़ ले सकता है'।

क्यों पसंद आया यह शो

इससे पहले सोहेल ने शो में हिस्सा लेने की पुष्टि करते हुए कहा, 'जब 'अलायंस' का ऑफर मेरे पास आया, तो मैं सचमुच उत्साहित था, क्योंकि यह कोई आम रियलिटी शो नहीं है। इसने मुझे इसलिए आकर्षित किया, क्योंकि यह सिर्फ टास्क जीतने तक नहीं है। यह लोगों, भरोसे और लगातार बदलती स्थितियों के अनुसार खुद को ढालने के बारे में है। मुझे चुनौतियां लेना पसंद है और यह मुझे सही चुनौती लगी। मैं सभी से मिलने को उत्साहित हूं। साथ यही यह भी देखने के लिए कि यह गेम आगे कैसे बढ़ता है'।

कहां देख सकते हैं 'अलायंस'

सोहेल ने आगे कहा, 'मैं एक ऐसे परिवार से हूं, जहां वफादारी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि 'अलायंस' जैसे गेम में नियम अलग होते हैं। समीकरण रातों-रात बदल सकते हैं और भरोसा हर दिन कमाना पड़ता है। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगा। जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। अपना गेम खेलूंगा। बाकी तो फिर समय ही बताएगा'। बता दें कि 'अलायंस' के नए एपिसोड हर दिन दोपहर 12 बजे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होते हैं।

मेरे लिए फिजिकल और इमोशनल दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल

रियलिटी शो से लेकर टीवी और अब ओटीटी तक शालीन भनोट ने अपने करियर में लगातार नए मोड़ देखे हैं। उतार-चढ़ाव, चर्चाओं और निजी जिंदगी पर हुई सार्वजनिक बहसों के बीच उन्होंने एक बात नहीं बदली, जहां जरूरी नहीं होता, वहां वह चुप रहना बेहतर है। अपने किरदारों के लिए सख्त अनुशासन अपनाने वाले शालीन मानते हैं कि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जितना कठिन होता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण मानसिक बदलाव भी होता है। पिछले दिनों अपनी वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' के दूसरे सीजन को लेकर काफी चर्चा में रहे।

अपना दायरा हमेशा मेंटेन करता हूं

शालीन भनोट ने कहा- मेरी जिंदगी के कई फेज पब्लिक डिस्कशन में रहे पर मैंने कोई दूरी नहीं बनाई। दरअसल, मेरी पर्सनल लाइफ मेरी है। मेरा अपना एक दायरा है और मैं उसे हमेशा मेंटेन करता हूं। मैं हमेशा से ऐसा करता आया हूं। प्रोफेशनल लाइफ अपनी जगह है। मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। मैंने कोई दायरा बनाने के बारे में अलग से सोचा भी नहीं है। मेरी पब्लिक मेरी सब कुछ है। आज मेरे करोड़ों फॉलोअर्स हैं। अलग-अलग सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर हैं, उन्हें मेरे बारे में सब पता है। मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है और मैं किसी को जज भी नहीं करता। जहां मुझे नहीं बोलना होता, वहां मैं नहीं बोलता और वैसे ही अपनी पब्लिक को भी नहीं बोलता। बाकी मेरे घर में ना मीडिया वाले घुसते और ना ही फैंस क्योंकि सबकी एक सीमा होती है।

मेरे लिए फिजिकल और इमोशनल दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल हैं। अगर कोई बोले कि दो महीने के अंदर पूरा लुक बदलना है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने करके देखा है इसलिए कह रहा हूं। फिजिकल के अलावा कई बार मेंटली ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। दरअसल, बोला जाता है कि यह नहीं, वो नहीं खाना है, तीन महीने बाद यह करना है। मैंने भी करीब 110 दिन बहुत डिसिप्लिन से काम किया।

तुम करते हो तो कन्हैया मेरा नाम होता है

लोगों को लगा था कि 'बिग बॉस' से पहले मैं जॉबलेस था, जबकि अपनी वेब सीरीज शूट कर रहा था पर मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि लोग कुछ भी बोलें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक ब्लू हेयर थ्योरी पढ़ी थी। वह ऐसी होती है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके नीले बाल बहुत गंदे लग रहे हैं और आपके बाल नीले हैं ही नहीं तो मेरी बात अपने आप व्यर्थ हो जाएगी। ऐसा ही मेरा जीवन है। किसी की बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा ऊपरवाले की कृपा से सब काम होता है। वो कहते हैं ना, 'तुम करते हो तो कन्हैया मेरा नाम होता है।'

पुलिसवालों के प्रति मेरी समझ बहुत बढ़ गई

एक कॉप का कैरेक्टर करने के बाद मेरी उनके प्रति समझ बहुत बढ़ गई है। कई बार हमें लगता है कि एयर होस्टेज का काम सिर्फ पानी और खाना देना है लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब दूसरी तरफ का काम समझते हैं तो पता चलता है कि वह कितना महत्वपूर्ण है। वह आपातकाल परिस्थितियों में आपकी जान बचाती हैं। उन्हें मेडिकल नॉलेज भी दी जाती है। इसी तरह, जब पुलिसवाले को देखते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा, यही उनका काम है लेकिन असल में उनका काम बहुत मुश्किल होता है। उसमें सही और गलत की परख करना मुश्किल है। एक पुलिसवाले के लिए, वो भी एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के लिए यह और कठिन हो जाता है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो होता है, उसे एक सेकेंड में सही और गलत का फैसला करना होता है। कहां गोली मारनी है, हवा में चलानी है, पैर पर हिट करना है, मारना है या नहीं मारना है? यह जजमेंट उसे उसी पल लेना होता है। आप जब इस बात को समझते हो तो पुलिस के लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। उन्हें किसी के जीवन के बारे में फैसला लेना पड़ता है। यह बहुत मुश्किल और ट्रिकी सिचुएशन होती है।

टीवी जो मोहब्बत देता है, वो कोई नहीं दे सकता

टीवी और ओटीटी, दोनों मीडियम अलग हैं। टीवी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। टीवी जो मोहब्बत देता है, वो कोई नहीं दे सकता। इसके जरिए आप हर घर में पहुंच जाते हैं। आज जितना मैं जाना जाता हूं, वह टीवी की वजह से है। वही वेब की एक रिच मार्केट और ऑडियंस है।

शिवम ने तोड़ा अक्षर का रिकॉर्ड

T20- के 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-8 भारतीय

नई दिल्ली। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में चेस्टर ली स्ट्रीट में कप्तान श्रेयस अय्यर और ओपनर अभिषेक शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली जो टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा, लेकिन 7वें नंबर पर बैटिंग करने आए शिवम दुबे ने भी महफिल लूट ली। शिवम ने टीम के लिए फिनिशर का रोल अदा करते हुए 21 गेंदों पर नाबाद 42 रन बनाए और इसके दम पर ही भारत ने 20 ओवर में 7

विकेट पर 189 का स्कोर छूआ। हालांकि ये मैच बारिश की वजह से बिना किसी नतीजे से ही समाप्त हो गया। शिवम ने भारतीय पारी के दौरान आखिरी ओवर में एक शानदार छक्का लगाया और वो भारत की तरफ से टी20आई में 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब रोहित शर्मा और अक्षर पटेल से आगे हैं।

शिवम दुबे ने तोड़ा अक्षर का रिकॉर्ड, कोहली की कर ली बराबरी- शिवम दुबे ने अपनी नाबाद 42 रन की पारी के दौरान 3 छक्के और 2 चौके लगाए। इन 3 छक्कों में से एक छक्का उन्होंने 20वें ओवर में लगाया और वो अब टी20आई में भारत की तरफ से 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में अक्षर पटेल और रोहित शर्मा से आगे हैं जबकि विराट कोहली की बराबरी पर आ गए।

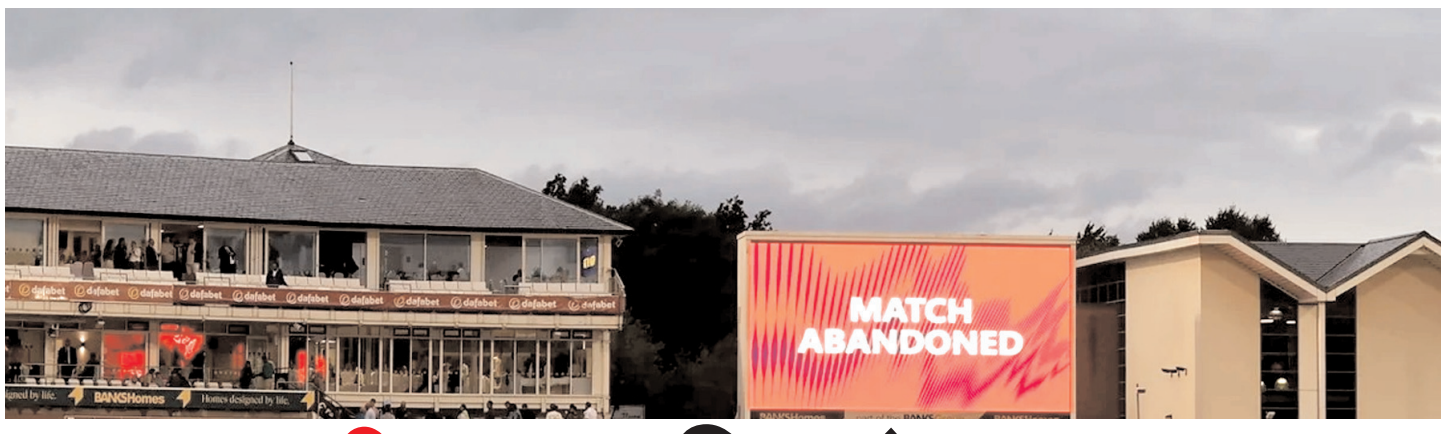

पहला टी20 बारिश के कारण रद्द

श्रेयस अय्यर-अभिषेक शर्मा के पचासे बेकार

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो गया। पहला मुकाबला बुधवार रात (भारतीय समयानुसार) चेस्टर ली स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में हुआ। बारिश के कारण इस मैच में नतीजा नहीं निकल पाया और मुकाबला रद्द हो गया। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी।

भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए। इंग्लैंड को 190 रन का लक्ष्य मिला। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 68 और अभिषेक शर्मा ने 59 रन की पारी खेली। अंत में शिवम दुबे ने नाबाद रहते हुए 21 गेंद पर 42 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए साकिब महमूद ने 33 रन देकर 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर की पारियां भारत के लिए अच्छा संकेत रहीं, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से शृंखला हारने का अहम कारण बल्लेबाजों का खराब फॉर्म था। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत ही नहीं हो पाई, क्योंकि पारी के ब्रेक में ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पांच ओवर खेले जाने के लिए कट ऑफ समय में 40 मिनट से अधिक समय बाकी रहते अंपायरों ने मैच रद्द करने का फैसला किया। पांच मैचों की शृंखला का दूसरा मैच चार जुलाई को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इससे पहले भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। टी20 विश्व चैंपियन टीम ने फिर संजू सैमसन का विकेट जल्दी गंवा दिया जो साकिब महमूद की गेंद पर पॉइंट में टॉम बेंटोन को कैच दे बैठे। इशान किशन भी अभिषेक शर्मा के साथ हुई गलतफहमी के कारण रन आउट हो गए। उस समय तक स्कोर बोर्ड पर सिर्फ छह रन ही टंगे थे।

भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ शृंखला की कहानी को दोहराती दिखी, लेकिन अभिषेक शर्मा ने टीम को दबाव से निकाला। उन्होंने महमूद के ओवर में एक चौका और दो छक्के लगाए। श्रेयस अय्यर ने भी एक चौका जड़कर चौथे ओवर में 21 रन निकाले। महमूद ने अभिषेक को शॉर्टपिच गेंदें डाली, लेकिन वह इसके लिए तैयार थे और बेहतरीन पुल शॉट लगाए। तीसरे विकेट के लिए अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर ने 82 रन की साझेदारी की।

श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान तीसरे T-20 में ही कर दिया कमाल

रोहित, कोहली, धोनी किसी ने नहीं किया था यह कारनामा

कप्तान श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 68 रन की पारी खेली। 47 गेंदों की इस पारी में उन्होंने छह चौके और एक छक्का भी लगाया। यह इंग्लैंड की सरजमीं पर किसी भारतीय कप्तान का टी20 में पहला अर्धशतक था। इससे पहले विराट कोहली ने 2018 में बतौर कप्तान टी20 मुकाबले में 47 रन बनाए थे। अब 8 साल बाद अय्यर ने विराट का यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले टी20 इंटरनेशनल में यहां भारत के लिए रोहित शर्मा, एमएस धोनी, विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने कप्तानी की है। मगर इनमें से कोई भी बतौर कप्तान इंग्लैंड में टी20 का पचासा नहीं लगा पाया। श्रेयस ने अपने तीसरे टी20 इंटरनेशनल में ही बतौर कप्तान यह कमाल कर दिया।

श्रेयस अय्यर का सबसे धीमा पचासा

श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में 38 गेंद पर पचासा पूरा किया। यह उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का 9वां पचासा था और सबसे धीमा भी था। इससे पहले उन्होंने अपने सभी 8 अर्धशतक 38 गेंद से कम में ही बनाए थे। वहीं बतौर कप्तान टी20 इंटरनेशनल में भी यह श्रेयस का पहला अर्धशतक था। इससे पहले आयरलैंड सीरीज में दोनों मुकाबलों में उनका बल्ला नहीं चल पाया था। हालांकि, बतौर कप्तान अय्यर को अपनी पहली जीत का अभी भी इंतजार है।

कप्तान श्रेयस ने की रैना-राहुल की बराबरी

रोहित नंबर 1

T20- में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले टॉप-5 भारतीय कप्तान

भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं खेला जा सका। इस मैच में भारतीय पारी को पूरी हो गई, लेकिन बाद में बारिश की वजह से इंग्लैंड बैटिंग नहीं कर पाया और मैच बिना किसी नतीजे के ही समाप्त हो गया। हालांकि भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन का अच्छा स्कोर बनाया जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी का भी अहम योगदान रहा। बतौर कप्तान

श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाया और टीम इंडिया की डूबती नैया को पार लगाने का काम किया। श्रेयस ने 68 रन की पारी खेली जबकि अभिषेक शर्मा ने भी उनका भरपूर साथ निभाया और 59 रन की अहम पारी खेलते हुए टीम को मजबूत स्थिति में लाने का काम किया। श्रेयस अय्यर ने अपनी पारी के दम पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 5000 रन भी पूरे कर लिए साथ ही साथ वो टी20आई में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले भारतीय कप्तानों की लिस्ट में सुरेश रैना और केएल राहुल के साथ आ गए।

श्रेयस की की रैना-राहुल की बराबरी

अभिषेक बने नंबर 1

T20- में पूरे किए सबसे तेज 100 छक्के

नई दिल्ली। अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में बेहतरीन शुरुआत की है। उन्होंने 20 गेंद पर ही अपना अर्धशतक पूरा किया। इस पारी में अपना दूसरा छक्का लगाते ही अभिषेक ने 100 टी20 इंटरनेशनल छक्के

भी पूरे कर लिए। वह इस फॉर्मेट में 100 छक्कों का आंकड़ा पार करने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज बने। जबकि दुनियाभर में गेंदों के लिहाज से उन्होंने सबसे तेज 100 छक्के टी20 इंटरनेशनल में लगाए हैं।

अभिषेक शर्मा ने वेस्टइंडीज के एविन लुईस का रिकॉर्ड तोड़ा और 785 गेंद पर अपने 100 टी20 इंटरनेशनल छक्के पूरे किए। वह इस मामले में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए।

अभिषेक शर्मा का 11वां अर्धशतक

अभिषेक ने इस मैच में 24 गेंद पर 59 रन की बेहतरी पारी खेली। इस पारी में उन्होंने छह चौके और चार छक्के लगाए। अभिषेक शर्मा के टी20 इंटरनेशनल करियर का यह 11वां अर्धशतक है। आयरलैंड के खिलाफ भी पहले मैच में उन्होंने 49 रन बनाए थे। वह एकमात्र सेट खिलाड़ी पहले मैच में नजर आए थे। सैम करन ने इस मैच में उन्हें अपना शिकार बनाया। आमने-सामने की बात करें तो तीन में से दूसरी बार करन ने अभिषेक का विकेट लिया है।

● रिकॉर्ड, गोल और विरासत

27 की उम्र में मेसी और एम्बाप्पे, महानता की दौड़ में कौन आगे?

केवल आंकड़ों का मुकाबला नहीं रह जाता, बल्कि दो पीढ़ियों के दो असाधारण खिलाड़ियों की महानता का आकलन बन जाता है।

एक ओर 27 की उम्र तक लियोनल मेसी ने 573 मैचों में 440 गोल और 185 असिस्ट के साथ ऐसा मानक स्थापित कर दिया था, जिसे आज भी फुटबॉल के सबसे ऊंचे बेंचमार्क में गिना जाता है। दूसरी ओर, किलियन एम्बाप्पे 518 मैचों में 362 गोल और 126 असिस्ट के साथ पहले ही विश्व कप विजेता बन चुके हैं और अपनी पीढ़ी के सबसे सफल गोलस्कोररों में से एक हैं।

नई दिल्ली। फुटबॉल में महानता सिर्फ गोलों, असिस्ट या ट्रॉफियों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि कोई खिलाड़ी अपने दौर पर कितना गहरा असर छोड़ता है। यही वजह है कि जब 27 साल की उम्र में लियोनल मेसी और किलियन एम्बाप्पे के करियर की तुलना की जाती है, तो यह

विश्व कप: जहां होती है महानता की परीक्षा

फुटबॉल में अगर किसी एक मंच पर महानता की सबसे बड़ी परीक्षा होती है तो वह फीफा विश्व कप है। फीफा विश्व कप में लियोनल मेसी को किलियन एम्बाप्पे सबसे कड़ी चुनौती देते नजर आते हैं। लियोनल मेसी ने अब तक पांच विश्व कप में 28 मैच में 18 गोल किए हैं। दूसरी ओर किलियन एम्बाप्पे ने विश्व कप के 16 मैचों में ही 16 गोल दाग चुके हैं। यानी गोल करने की रफ्तार के मामले में फ्रांसीसी स्टार अर्जेंटीनी दिग्गज से कहीं आगे हैं। दिलचस्प यह है कि किलियन एम्बाप्पे लियोनल मेसी के विश्व कप गोलों की बराबरी से केवल दो गोल दूर हैं और उनके सामने अभी पूरा 2026 विश्व कप मौजूद है। यदि वह अपनी मौजूदा लय बरकरार रखते हैं तो विश्व कप के कई रिकॉर्ड उनके नाम हो सकते हैं। कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लियोनल मेसी ने सिर्फ गोल नहीं किए, बल्कि निर्णायक मौकों पर अपनी टीम को विश्व चैंपियन भी बनाया। साल 2022 विश्व कप में उन्होंने कप्तान के रूप में अर्जेंटीना को वह ट्रॉफी दिलाई, जिसका इंतजार देश 36 वर्षों से कर रहा था। यही उपलब्धि उनकी विरासत को अलग स्तर पर पहुंचा देती है।

जिस नीदरलैंड्स को हराया, उसकी ही सड़कों पर मोरक्को के फैंस ने मनाया जीत का जश्न

हालांकि, लियोनल मेसी ने वापसी की, हार नहीं मानी और फिर ऐसा अध्याय लिखा जिसने उन्हें फुटबॉल इतिहास के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। साल 2021 में कोपा अमेरिका, 2022 में फाइनलिसिमा और फीफा विश्व कप, 2024 में एक और कोपा अमेरिका। यही वजह है कि लियोनल मेसी और किलियन एम्बाप्पे की तुलना केवल गोलों और रिकॉर्डों की नहीं, बल्कि संघर्ष, निरंतरता, उपलब्धियों और विरासत की भी है। यही इस मुकाबले को फुटबॉल की सबसे दिलचस्प बहसों में से एक बनाता है।

हैरी केन का डबल धमाल

इंग्लैंड ने राउंड ऑफ 16 में की एंट्री

नई दिल्ली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में बुधवार को इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हराया और राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। इस मुकाबले में बढ़त कांगो ने बनाई थी और सभी इंग्लिश फैंस की टेंशन बढ़ा दी थी। इसके बाद हैरी केन ने अपना जलवा दिखाया और 75वें व 86वें मिनट में गोल करते हुए इंग्लैंड को विजयी लीड दिलाई। अब प्री-क्वार्टरफाइनल में इंग्लैंड का सामना 6 जुलाई को मेक्सिको के साथ होगा।

कांगो के लिए ब्रायन सिपेंगा ने मैच के 7वें मिनट में ही कांगो के लिए ऐतहासिक गोल दागा था। फिर इंग्लैंड की टीम ने पहले हाफ में जद्दोजहद की लेकिन गोल नहीं कर पाए। दूसरे हाफ का भी आधा समय बीत चुका था और इंग्लिश टीम के फैंस का तनाव बढ़ रहा था। इस दौरान जूड बेलिंगहम और मार्कस रशफोर्ड की कोशिशें नाकाम हुईं। कांगो के गोलकीपर लियोनेल मपासी ने बेहतरीन खेल दिखाया और इंग्लैंड के स्ट्राइकर्स को खूब छकाया।

हैरी केन के जादू से जीता इंग्लैंड

पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट में पहुंची कांगो की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पहले 10 मिनट के अंदर ब्रायन के गोल ने उन्हें फ्रंटफुट पर ला दिया था। इसके बाद बिसाका और योने विसा ने कई बेहतरीन प्रयास किए। गोलकीपर मपासी ने गेंद को अपने गोल पोस्ट तक नहीं जाने दिया। फिर दूसरे हाफ के आधे टाइम के बाद इंग्लैंड के दिग्गज हैरी केन का जादू देखने को मिला। हैरी केन ने 75वें मिनट में अपना और इंग्लैंड के लिए इस मैच का पहला गोल दागा और 68 मिनट के इंतजार के बाद स्कोर को 1-1 किया। फिर इस गोल के 11 मिनट बाद ही उन्हें एक और मौका मिला, फिर 86वें मिनट में केन ने अपना दूसरा गोल किया। इसी के साथ अंत में इंग्लैंड ने 2-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। अब मेक्सिको से उसकी तगड़ी भिड़ंत अगले राउंड में होनी है।

'इंग्लैंड में मेरा सही से इस्तेमाल नहीं हुआ...'

शार्दुल ठाकुर का आरोप, घेरे में कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर

नई दिल्ली। भारतीय ऑलराउंडर और मुंबई की टीम के कप्तान शार्दुल ठाकुर का एक बड़ा बयान बुधवार (1 जुलाई 2026) को सामने आया है। शार्दुल ने पिछले साल इंग्लैंड में हुए दौरे का जिक्र किया और बताया कि उनका सही से उस दौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया था। उस दौरे पर नवनियुक्त कप्तान शुभमन गिल कमान संभाल रहे थे। शार्दुल के बयान के बाद एक बार फिर से कोच गौतम गंभीर की रणनीतियां चर्चा में आ गई हैं। भारतीय ऑलराउंडर के आरोपों का सीधा निशाना कप्तान और कोच पर ही है।

शार्दुल ठाकुर ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एक इवेंट में कहा, '2024-25 जैसे सीजन (जब शार्दुल ने 9 मैचों में 35 विकेट झटके थे) के बाद मुझे लगता था कि मुझे कई मैच और खेलने चाहिए थे जिससे अंतर पैदा हो सकता था। जब मैं इंग्लैंड में था तो मेरी बॉलिंग का सही से इस्तेमाल नहीं हुआ। बल्लेबाजी में हां मेरी

गलती थी, मैंने कई गलत शॉट खेले थे लीड्स में, लेकिन मैनचेस्टर में मैंने अच्छी बैटिंग की थी (पहली पारी में 41 रन बनाए थे)। 'उन्होंने आगे कहा, 'ओवरकास्ट कंडीशन थीं वहां, बॉल स्विंग हो रही थी और बाउंस भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उस स्पेल में जैसे-तैसे विकेट बचाया था। फिर बाद में पिच फ्लैट हो गई थी और हम मैच बचा पाए थे। अगर मैं वह पारी नहीं खेल पाता तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था। मैं जरूर कहूंगा कि मुझे कम बॉलिंग करवाई गई और जब करवाई गई गलत समय पर करवाई गई। मेरे मुताबिक कुछ कैलकुलेशन की गलतियां हुई थीं। ' कप्तान और कोच से इस बारे में बात करने पर शार्दुल ने बताया, 'नहीं मेरा मतलब है कि ऐसी बातों के लिए आप कप्तान या कोच से बात नहीं करते हैं।

शार्दुल ठाकुर ने इंग्लैंड में दो टेस्ट मैचों में सिर्फ किए थे 27 ओवर

आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर ने पिछले साल (2025 में) इंग्लैंड दौरे पर पहले टेस्ट (लीड्स में) पहली पारी में सिर्फ 6 ओवर डाले थे। उस दौरान उन्होंने 38 रन दिए थे और एक भी विकेट नहीं मिला था। जबकि भारतीय गेंदबाजी में इस पारी में 100.4 ओवर फेंके गए थे। फिर दूसरी पारी में भी उन्होंने पारी के कुल 82 ओवर में से सिर्फ 10 ओवर डाले और 51 रन देकर दो विकेट भी लिए। भारत को इस मुकाबले में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वह अगले दो मैचों से बाहर हो गए और चौथे टेस्ट में मैनचेस्टर में वापस आए और पहली पारी में 11 ओवर सिर्फ डाले और 55 रन देकर एक भी विकेट नहीं ले पाए। यह मुकाबला ड्रा हुआ था। पूरी सीरीज में सिर्फ तीन पारियों में शार्दुल ने गेंदबाजी की थी और पूरे दौरे पर सबसे कम गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ियों में से एक थे। उनके नाम 13 टेस्ट मैचों में 33 विकेट दर्ज हैं। दो टेस्ट मैचों में उन्होंने सिर्फ 27 ओवर गेंदबाजी की और 144 रन दिए।

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली में 5 दिन देरी से हुई मॉनसून की एंट्री, कई इलाकों में बारिश

नई दिल्ली, एजेंसी। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल के बाद आखिरकार मानसून दिल्ली पहुंच गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून 27 जून को आने वाला था लेकिन यह दिल्ली में पांच दिन की देरी से 2 जुलाई को पहुंचा है। मानसून के आगमन से ही आज सुबह ही दिल्ली और आसपास के इलाके के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आज सुबह ही दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में तेज धूलभरी हवाएं चलने के बाद मामूली बारिश हुई। बारिश के बाद से ही पूरे दिल्ली-एनसीआर का मौसम सुहाना बना हुआ है। हालांकि बारिश ज्यादा न होने से लोग उमस महसूस कर रहे हैं लेकिन रोजाना होने वाली तेज धूप से उन्हें राहत मिल गई है।

खाली होगा दिल्ली जिमखाना क्लब? केंद्र ने नोटिस जारी कर 7 जुलाई तक मांगा जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को एक कारण बताओ

नोटिस जारी किया है और 7 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इस नोटिस के जरिए सरकार ने क्लब से पूछा है कि उसके खिलाफ क्यों न बेदखली का आदेश जारी किया जाए। दरअसल, क्लब पर यह आरोप है कि वह नई दिल्ली के सफदरजंग रोड पर स्थित संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा जमाए हुए है। गौरतलब है कि 26 मई को जिमखाना क्लब को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि बेदखली की कार्रवाई केवल कानूनी नोटिस देने के बाद ही होगी। दरअसल, बीते दिनों केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को अवैध जमीन खाली करने का आदेश दिया था, जिसे जिमखाना क्लब ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी।

सर्विस लेन अतिक्रमण पर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, एमसीडी को उचित निर्णय लेने का आदेश

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की एक कालोनी में सर्विस लेन को घेरने के कारण आपात

सेवाओं तक पहुंच बंद होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका का दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को निपटारा कर दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने रिकार्ड पर लिया कि याचिकाकर्ता इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को प्रतिवेदन दिया गया है। उक्त तथ्यों को देखते हुए पीठ ने एमसीडी को निर्देश दिया कि याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर लेकर इस पर उचित निर्णय करें। विचार करने से हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। जनहित याचिका में कहा गया कि इलाके में लोगों ने अपनी बालकनी और सर्विस लेन को लोहे की ग्रिल से घेर लिया है। इसके कारण फायर फाइटर्स जैसी इमरजेंसी सेवाओं तक पहुंच नहीं हो पा रही थी।

दिल्ली में फीस बढ़ाने से पहले अब पैरेंट्स की मंजूरी जरूरी

15 जुलाई तक हर स्कूल में बनेगी रेगुलेशन कमेटी

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी में निजी स्कूलों की फीस को लेकर वर्षों से उठते रहे विवादों के बीच शिक्षा निदेशालय ने फीस निर्धारित करने की पूरी प्रक्रिया को अभिभावकों की भागीदारी से जोड़ दिया है।

अब निजी स्कूल केवल अपने स्तर पर फीस बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर उसे लागू नहीं कर सकेंगे। फीस बढ़ाने या संशोधित करने का हर प्रस्ताव पहले स्कूल स्तर पर गठित होने वाली स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी के सामने रखा जाएगा, जिसमें सबसे अधिक सदस्य अभिभावकों के होंगे। समिति की मंजूरी के बाद ही प्रस्ताव आगे बढ़ सकेगा।

निदेशालय ने इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया जारी करते हुए सभी निजी स्कूलों को 15 जुलाई तक गठित करने का निर्देश दिया है। यह व्यवस्था दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 के तहत लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य फीस निर्धारण में पारदर्शिता लाना और मनमानी बढ़ोतरी पर रोक लगाना है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक स्कूल को सबसे पहले पैरेंट-टीचर एसोसिएशन (पीटीए) बनानी होगी। इसके बाद पांच अभिभावकों और तीन शिक्षकों का चयन खुली लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉट्स) से किया जाएगा। इस प्रक्रिया की निगरानी शिक्षा विभाग का नामित अधिकारी करेगा। ड्रॉ की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, पूरी कार्यवाही का लिखित रिकार्ड तैयार होगा और चयनित

सदस्यों की सूची स्कूल की वेबसाइट व नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करनी होगी। इससे चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह के पक्षपात या हस्तक्षेप की संभावना कम होगी। दरअसल, अब तक फीस बढ़ोतरी को लेकर सबसे बड़ा आरोप यही लगता रहा है कि निर्णय केवल स्कूल प्रबंधन लेता है और अभिभावकों को बाद में सिर्फ सूचना दी जाती है। नई व्यवस्था इस प्रक्रिया को उलट देती है। अब स्कूल प्रबंधन को अगले तीन वर्षों की प्रस्तावित फीस संरचना, पिछले तीन वर्षों के ऑडिटेड वित्तीय दस्तावेजों के साथ 31 जुलाई तक स्स्त्रऋष्ट के समक्ष पेश करनी होगी। समिति स्कूल के खर्च, आय, वित्तीय जरूरत और प्रस्तावित बढ़ोतरी का परीक्षण करेगी। आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकेगा। निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया गया है कि चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। यदि लाटरी में यह प्रतिनिधित्व नहीं बनता है तो प्रतीक्षा सूची से सदस्यों को शामिल कर कानूनी शर्त पूरी की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने दिया हाई कोर्ट का हवाला शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के 28 फरवरी 2026 के आदेश का भी हवाला दिया है।

पाकिस्तान में 125 साल पुराना गुरुद्वारा तोड़ने की कोशिश पर सिख नाराज

नई दिल्ली, एजेंसी। पाकिस्तान में फारूखाबाद में 125 वर्ष पुराने गुरुद्वारा साहिब के भवन को गिराने के प्रयास किया गया। कुछ हिस्से को नुकसान भी पहुंचा है।

इससे सिखों में भारी नाराजगी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) ने नाराजगी जताते हुए इस मामले को भारत के विदेश मंत्रालय के समक्ष उठाया है। विदेश मंत्रालय ने कमेटी को आश्वासन दिया है कि इस गंभीर मामले को तत्काल पाकिस्तान सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। डीएसजीएमसी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि फारूखाबाद स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की 125 वर्ष पुराने भवन को गिराने का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों के विरोध के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो सका, लेकिन यह अत्यंत गंभीर और चिंताजनक मामला है। डीएसजीएमसी एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश से मुलाकात कर पूरे मामले से उन्हें अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें यह भी बताया कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अक्सर सिख समुदाय पर हमलों और अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में पाकिस्तान में एक गुरुद्वारे के सेवादार और उनकी पत्नी की हत्या का मामला भी सामने आया था। इसके अलावा गुरुद्वारों पर हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो बेहद चिंता का विषय हैं। उन्होंने बताया कि संयुक्त सचिव ने पूरे मामले को गंभीरता से सुना और प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि भारत सरकार इस मुद्दे को तत्काल पाकिस्तान सरकार के समक्ष उठाएगी तथा ऐसे हमलों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का दबाव बनाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों, विशेषकर सिख समुदाय के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे, उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त सचिव ने आश्वस्त किया कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी सहित सभी सिख संगठनों एवं संस्थाओं की शिकायतों को भारत सरकार गंभीरता से लेती है।

दो दिन में 6.89% मतदाताओं तक पहुंचे एन्युमरेशन फॉर्म, 32109 का डिजिटल डेटा तैयार

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में दो दिन में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तीसरे चरण के तहत बुधवार तक 6.89 प्रतिशत मतदाताओं को एन्युमरेशन फार्म बांट दिए गए हैं। जिसमें सर्वाधिक दक्षिणी पूर्वी जिले

में 0.44 प्रतिशत है। मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में एक करोड़ 45 लाख 10, 298 मतदाताओं में से 9,99,773 प्रतिशत को एन्युमरेशन फार्म बांटे जा चुके हैं। जिसमें से 32,109 का फार्म को डिजिटल डेटा तैयार भी कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में एसआइआर के तहत मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जिसके तहत बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जा रहे हैं। यह सिलसिला 29 जुलाई तक चलेगा। वैसे, इस अभियान के तहत लोग खुद भी आनलाइन माध्यम से अपना सत्यापन कर रहे हैं तथा उसकी जानकारी बूथ लेवल अधिकारी को दे रहे हैं। इससे सत्यापन की प्रक्रिया आसान हो गई है। दूसरे दिन भी जगह-जगह जहां आरडब्ल्यूए व सामाजिक संगठनों की मदद से लगाए गए कैंपों में बूथ लेवल अधिकारी मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करते रहे। वहीं, घर-घर जाने की प्रक्रिया में कम उत्साह देखने को मिला।

विभाग में कैजुअल कपड़े पहने तो खैर नहीं', सीएम रेखा गुप्ता के छापे के बाद व्यापार एवं कर विभाग का सख्त सर्कुलर

नई दिल्ली, एजेंसी। व्यापार एवं कर विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान उचित वेशभूषा, कार्यालयीन शिष्टाचार और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि यह सर्कुलर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आकस्मिक निरीक्षण के बाद जारी किया गया है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी ड्यूटी के दौरान उचित, साफ-सुथरे, संयमित और शालीन वेशभूषा पहनें। कैजुअल या अनुचित कपड़े पहनने से बचें। कार्यालय में सहकर्मियों तथा आगंतुकों के साथ पेशेवर और शिष्ट व्यवहार करें। अधिकारी केवल अपने निर्धारित वर्कस्टेशन (कुर्सी/डेस्क) पर ही कार्य करें। बिना अनुमति के किसी अन्य कर्मचारी की कुर्सी या डेस्क पर कब्जा न करें। कार्यालय में साफ-सफाई, व्यवस्था और अनुकूल कार्य वातावरण बनाए रखें। शाखा प्रमुख एवं वार्ड प्रभारी अपने अधीन सभी कर्मचारियों से इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये कदम कार्यस्थल पर अनुशासन मजबूत करने, सरकारी कार्यालयों की सार्वजनिक छवि सुधारने और लोक सेवकों से अपेक्षित पेशेवर स्तर बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कार्रवाई हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आईटीओ स्थित विभागीय

कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया था। उन्होंने ऑफिस टाइम में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई थी। मौजूद स्टाफ से रिपोर्टिंग समय के बारे में पूछताछ की और विभाग के अटेंडेंस रिकॉर्ड का विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की थी। सीएम ने कार्यालय की बुनियादी सुविधाओं का भी जायजा लिया और मरम्मत-रखरखाव कार्यों पर सवाल उठाए।

कतर की मध्यस्थता रंग लाई: दोहा में यूएस-ईरान वार्ता से बढ़ी उम्मीद, 14 सूत्रीय समझौते पर हुई सकारात्मक चर्चा

दोहा, एजेंसी। कतर के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार कतर और पाकिस्तान ने दोहा में अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों के साथ अलग-अलग बैठकें संपन्न कीं। जिनमें 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) से संबंधित मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई। गुरुवार को एक एक्स पोस्ट में कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार और विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता माजेद अल अंसारी ने कहा कि वार्ता लेक ल्यूसर्न शिखर सम्मेलन के परिणामों पर आधारित थी। यह ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता के अंतिम यात्रा के बाद जारी रहेगी। तसनीम न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान के कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजेम रारीबाबादी ने कहा 'हमने दोहा बैठक में लेबनान में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में

अमेरिका की विफलता का मुद्दा उठाया था।' उन्होंने आगे कहा कि कतर के अधिकारियों के साथ बैठकों में 6 अरब अमेरिकी डॉलर के एक हिस्से के खर्च से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही इस बैठक में यह सहमति हुई कि घोषित जरूरतों के आधार पर, आवश्यक वस्तुओं की खरीद की जाएगी। उन्हें ईरान के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अंतिम यात्रा 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक के अलग- अलग स्थानों पर करने की योजना हैं। बता दें कि खामेनेई की मृत्यु 28 फरवरी को ईरान के साथ अमेरिका-इस्राइल युद्ध के पहले दिन एक हवाई हमले में हुई थी। इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण अच्छी तरह चल रहा है।

भारत के 100 रुपए उज़्बेकिस्तान में बन जाते हैं 13,000 से ज्यादा

ताशकंद, एजेंसी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है, जहां भारत के सिर्फ 100 रुपये के बदले करीब 13,000 से 15,000 तक मिल सकते हैं। जी हां, यह देश न तो वियतनाम है, न इंडोनेशिया दरअसल यह उज़्बेकिस्तान है, जो इन दिनों भारतीय पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। हालांकि, हजारों की संख्या में स्थानीय मुद्रा मिलने का मतलब यह नहीं है कि भारतीय रुपया वहां बेहद मजबूत है। इसके पीछे की असली वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।

उज़्बेकिस्तान की मुद्रा उज़्बेक सोम है। मौजूदा विनिमय दर के अनुसार, 100 भारतीय रुपये के बदले लगभग 13,000 से 15,000 उज़्बेक सोम मिल सकते हैं। पहली नजर में यह आंकड़ा काफी बड़ा लगता है और ऐसा महसूस हो सकता है कि भारतीय रुपया वहां बहुत ज्यादा मजबूत है। हालांकि, इसकी असली वजह कुछ और है। उज़्बेकिस्तान की मुद्रा की एक यूनिट की कीमत भारतीय रुपये की तुलना में काफी कम है। इसी कारण कम भारतीय रुपये भी हजारों उज़्बेक सोम में बदल जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय रुपये की खरीदने की क्षमता बहुत अधिक है, बल्कि यह वहां की मुद्रा के मूल्य को

दर्शाता है। समय-समय पर बदलती रहती है, इसलिए मिलने वाली राशि में भी बदलाव संभव है।

भारतीय पर्यटकों के बीच बढ़ रही है उज़्बेकिस्तान की लोकप्रियता: पिछले कुछ सालों में उज़्बेकिस्तान भारतीय यात्रियों की पसंदीदा विदेशी जगहों में शामिल हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहां का कम यात्रा खर्च और ऐतिहासिक विरासत है।

यहां होटल, लोकल ट्रांसपोर्ट और भोजन का खर्च कई यूरोपीय और पश्चिमी देशों की तुलना में काफी कम माना जाता है। यही कारण है कि कम बजट में विदेश घूमने की योजना बनाने वाले लोग इस देश को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके अलावा, उज़्बेकिस्तान अपनी सिल्क रोड की ऐतिहासिक विरासत, शानदार मस्जिदों, नीले गुंबदों वाले स्मारकों और पारंपरिक मध्य एशियाई व्यंजनों के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

चीन में 200 रूसी सैनिकों की सीक्रेट ट्रेनिंग; पुतिन के करीबी ने दी मंजूरी

बीजिंग, मास्को, एजेंसी। रूस और चीन के बढ़ते रक्षा सहयोग को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने गोपनीय रूसी दस्तावेजों के आधार पर दावा किया है कि वर्ष 2025 में करीब 200 रूसी सैनिकों ने चीन में विशेष सैन्य प्रशिक्षण लिया। हालांकि, चीन ने इस दावे को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है, जबकि रूस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2025 में रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलौसोव ने एक आंतरिक आदेश जारी कर रूसी सैन्य प्रतिनिधिमंडल को चीन भेजने की मंजूरी दी थी। बताया गया है कि प्रशिक्षण लगभग तीन सप्ताह तक चला और इसमें कम से कम चार रूसी और चीनी जनरल भी शामिल थे। यह प्रशिक्षण चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सैन्य सुविधाओं में आयोजित किया गया। रॉयटर्स के मुताबिक, इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल सुरक्षा था। रूसी सैनिकों को परमाणु, रासायनिक और जैविक हमलों से बचाव, रेडिएशन और केमिकल रिकॉनिसेंस तथा वेंटिलेशन सिस्टम को प्रदूषण से सुरक्षित रखने जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सैनिकों ने परमाणु रिएक्टर के मॉडल पर व्यावहारिक अभ्यास किया। दूसरी ओर, चीन के विदेश मंत्रालय ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि卐संबंधित आरोप पूरी तरह निराधार हैं। चीन ने दोहराया कि यूक्रेन युद्ध पर उसका रुख नहीं बदला है और वह खुद को शांति वार्ता का समर्थक तथा मध्यस्थ मानता है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय और क्रेमलिन ने इस रिपोर्ट पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि रॉयटर्स की रिपोर्ट सही साबित होती है, तो यह भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है।

पनामा नहर पर कब्जा कर रहा चीन, ट्रंप ने दी खुली चेतावनी

बोले- ऐसा कभी नहीं होने देंगे

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर पनामा नहर और चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पनामा नहर का नियंत्रण सौंपकर बड़ी गलती की थी और अब चीन इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। उन्होंने यह बयान नॉर्थ डकोटा में थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह के दौरान दिया। इस दौरान उन्होंने जन्मसिद्ध नागरिकता और राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी अपनी राय रखी।

ट्रंप ने कहा कि जब अमेरिका ने पनामा नहर का नियंत्रण पनामा को सौंपा तो उसके बाद वहां से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क कई गुना बढ़ा दिया गया। उनके अनुसार, इससे पनामा को भारी आर्थिक फायदा हुआ। ट्रंप ने दावा किया कि अब चीन इस अहम समुद्री मार्ग पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने रणनीतिक हितों से जुड़ा यह मुद्दा किसी भी कीमत पर

नजरअंदाज नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा कि पनामा नहर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है।

उनका दावा है कि चीन इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन को पनामा नहर पर नियंत्रण या प्रभाव स्थापित नहीं करने देगा। उन्होंने पनामा नहर का नियंत्रण पनामा को सौंपने के पुराने फैसले को गलत बताया।

ट्रंप के अनुसार, नियंत्रण मिलने के बाद पनामा ने जहाजों से वसूले जाने वाले ट्रांजिट शुल्क में कई बार बढ़ोतरी की। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका के हितों को नुकसान हुआ और पनामा को आर्थिक फायदा मिला।

ट्रंप ने दोहराया कि उनकी सरकार की प्राथमिकता अमेरिका के रणनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना है। पनामा नहर का मामला आखिर क्या है? आसान भाषा में समझिए पनामा नहर एक कृत्रिम जलमार्ग है, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इससे जहाजों को पूरे दक्षिण अमेरिका का लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ता और हजारों किलोमीटर की दूरी बच जाती है। दुनिया के व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इससे समय, ईंधन और परिवहन लागत कम होती है। इसलिए इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में गिना जाता है। चीन की कंपनियां पनामा नहर के दोनों ओर स्थित दो बड़े बंदरगाहों का संचालन करती हैं। अमेरिका को डर है कि इससे चीन इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। दोनों महासागरों के जलस्तर में थोड़ा अंतर है। इसलिए पनामा नहर में लॉक यानी बड़े जलद्वार बने हैं।

एसआइआर कार्य में लाएं गति और गुणवत्ता, डिजिटाइजेशन को भी समान गति से आगे बढ़ाएं : उपायुक्त अजय नाथ झा

बोकारो /नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। गुरूवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीई) सह उपायुक्त अजय नाथ झा ने चंदनकियारी प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्र क्षेत्रों का निरीक्षण कर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत संचालित गणना प्रपत्र वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अभियान की सफलता प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंचने और समयबद्ध एवं त्रुटिरहित कार्य निष्पादन पर निर्भर है। इसलिए सभी बीएलओ एवं संबंधित पदाधिकारी समन्वय के साथ कार्य करते हुए गुणवत्ता और गति दोनों सुनिश्चित करें।

बीएलओ को सक्रिय सहयोग देने के लिए वोलेंटियर्स शिक्षक को दिए निर्देश

निरीक्षण के क्रम में डीईओ सह डीसी प्रखंड के बांसगाड़ी स्थित बूथ संख्या-178 पहुंचे, जहां उन्होंने बीएलओ तुलसी कुमार सिंह दे से गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि फॉर्म वितरण एवं संग्रहण के साथ-साथ डिजिटाइजेशन कार्य को भी समान गति से आगे बढ़ाया जाए। साथ ही प्रतिनियुक्त वोलेंटियर्स शिक्षक को विद्यालय अवधि समाप्त होने के बाद फ्रेंड, फिलॉसफर एवं गाइड की भूमिका निभाते हुए बीएलओ को सक्रिय सहयोग देने का निर्देश दिया। कहा कि एसआईआर महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके उपरांत डीईओ सह डीसी प्रखंड के संथाल लाघला स्थित बूथ संख्या-117 पहुंचे, जहां बीएलओ राजकुमारी हेंब्रम द्वारा किए जा रहे एसआईआर कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि गणना प्रपत्रों का वितरण एवं संग्रहण संतोषजनक ढंग से हो रहा है, जबकि डिजिटाइजेशन कार्य अपेक्षाकृत धीमी गति से चल रहा है। इस पर उन्होंने संबंधित कर्मियों को कार्ययोजना बनाकर डिजिटाइजेशन में तेजी लाने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय वर्मा, अंचल अधिकारी रवि आनंद, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं की जमीनी स्थिति का लिया फीडबैक

एसआईआर अभियान के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त श्री अजय नाथ झा ने ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने जनवितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण, आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली तथा विद्यालयों के संचालन के संबंध में ग्रामीणों से फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने उपस्थित बीडीओ/सीओ को निर्देश दिया कि आमजन को सभी सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बातचीत के क्रम में उपायुक्त ने जब योजना से मिलने वाली राशि के उपयोग के बारे में पूछा, तो ललिता हांसदा ने मुस्कुराते हुए कहा, "सर, पर्सनल खर्चा निकल जाता है, कुछ बचा भी लेती हूं।" लाभुक की यह सहज प्रतिक्रिया योजना के सामाजिक प्रभाव को दशार्ती है, जिससे महिलाओं को दैनिक जरूरतों की पूर्ति के साथ-साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता और बचत की भावना को भी बल मिल रहा है।

अवैध हथियार सहित दो अपराधी गिरफ्तार

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। बोकारो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संभावित आपराधिक वारदात को होने से पहले ही नाकाम कर दिया है। जरीडीह थाना क्षेत्र से पुलिस ने 19-19 साल के दो युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपी लूट और रंगदारी की वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। बोकारो के जरीडीह थाना क्षेत्र के तिरो टोला रजवारडीह में देर रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। सूचना थी कि दो युवक अवैध हथियार लेकर किसी बड़ी आपराधिक घटना की योजना बना रहे हैं। इसके बाद एसडीपीओ बेरमो (तेनुघाट) के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 19 वर्षीय विक्रम कुमार दास और 19 वर्षीय विक्रम कुमार कपरदार को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उनके घर से छज्जे और तकिए के नीचे छिपाकर रखे गए दो देशी रिवाल्वर, दो देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने ये अवैध हथियार कुछ महीने पहले बंगाल की ओर से आए दो अज्ञात लोगों से खरीदे थे। पुलिस के मुताबिक दोनों इन हथियारों के बल पर रंगदारी और लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने सभी हथियार जब्त कर लिए हैं और दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। साथ ही हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क की भी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि समय रहते की गई इस कार्रवाई से एक बड़ी आपराधिक घटना टाल दी गई।

बाइट नाथू सिंह मीणा, एसपी बोकारो

फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन आरोपियों के संपर्क में और कौन-कौन लोग थे।

संक्षिप्त समाचार

जेसीआई बोकारो जज्बा ने मिडकॉन में 21 पुरस्कार जीतकर बढ़ाया बोकारो का गौरव

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। लखनऊ स्थित मेवा रिसॉर्ट में आयोजित जेसीआई इंडिया के मिडकॉन (मिड ईयर कॉन्फ्रेंस) में जेसीआई बोकारो

जज्बा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जज्बा ने कुल 21 पुरस्कार अपने नाम किए। यह सम्मान संस्था द्वारा पिछले छह महीनों में समाज सेवा, नेतृत्व विकास, प्रशिक्षण, नवाचारपूर्ण परियोजनाओं तथा संगठनात्मक उत्कृष्टता के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए मिला है। जेसीआई बोकारो जज्बा की इस उपलब्धि ने पूरे बोकारो का गौरव बढ़ाया है। यह सफलता संस्था के सभी सदस्यों की कड़ी मेहनत, समर्पण, अनुशासन, टीमवर्क तथा वरिष्ठ मार्गदर्शकों के निरंतर सहयोग का परिणाम है। अध्यक्षा विनीता कुमार ने इस अवसर पर कहा कि यह उपलब्धि पूरे चैप्टर के प्रत्येक सदस्य के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं एवं सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान आगे भी समाज सेवा और नेतृत्व विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा देगा। संस्था भविष्य में भी जनहित एवं सामुदायिक विकास के लिए इसी उत्साह के साथ कार्य करती रहेगी।

वायरल वीडियो के आधार पर सिपाही निलंबित

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। वायरल वीडियो मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने वायरल वीडियो में दिख रहे आरक्षी को निलंबित कर दिया है। विदित हो कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो में एक युवक को वर्दी पहने पुलिसकर्मी और उनके साथ एक अन्य युवक के द्वारा पिटाई की जा रही है। यह वीडियो बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत नया मोड़ स्थित पेट्रोल पंप के नजदीक की है। यह घटना बुधवार देर शाम की है। इसमें मार खा रहा युवक स्थानीय हैसाबातु मुखिया का पुत्र है और इस युवक को पीट रहे पुलिसकर्मी सिटी थाना का सिपाही और उसका पुत्र है। इस मामले में मार खा रहा युवक की ओर से सिटी थाने में प्राथमिकी गई इसके विरुद्ध पुलिस अधीक्षक बोकारो के द्वारा आरक्षी पुलिस इकरार खान को निलंबित किया गया है मारपीट का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है जिस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है।

यातायात पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया, 29 ऑटो जब्त

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। बोकारो स्टील सिटी में ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सघन वाहन जांच अभियान चलाया। सेक्टर-4 स्थित एलआईसी मोड़ और गांधी चौक पर चलाए गए इस अभियान में करीब 150 वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान 29 ऑटो को जब्त कर थाना परिसर में रखा गया है। बोकारो ट्रैफिक इंस्पेक्टर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सेक्टर-4 के एलआईसी मोड़ और गांधी चौक पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान दोपहिया, चारपहिया और ऑटो समेत करीब 150 वाहनों के कागजात और अन्य आवश्यक

दस्तावेजों की जांच की गई। नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विशेष जांच अभियान चलाया गया। जिन वाहनों के दस्तावेज अधूरे या नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान 29 ऑटो को जब्त कर सेक्टर 4 थाना परिसर में रखा गया है। पुलिस सभी वाहनों के दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है। जांच पूरी होने के बाद जिन वाहनों में अनियमितता पाई जाएगी, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटते हुए जुमार्ना लगाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

बीएसएल के कोक ओवन विभाग ने उत्पादन एवं बिक्री में बनाए नए कीर्तिमान

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। बोकारो इस्पात संयंत्र के कोक ओवन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही तथा जून 2026 में उत्पादन एवं बिक्री के क्षेत्र में कई नई उपलब्धियां हासिल कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है. जून 2026 में कोक ओवन द्वारा प्रतिदिन औसतन 531 ओवन पुशिंग दर्ज की गई, जो अब तक का सर्वोच्च मासिक प्रदर्शन है. इससे पूर्व मार्च 2026 में प्रतिदिन 530 ओवन पुशिंग का रिकॉर्ड स्थापित किया गया था. वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कोक ओवन विभाग ने प्रतिदिन औसतन 526 ओवन पुशिंग कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. इससे पहले वित्तीय वर्ष 2023 -24 के पहली तिमाही में

प्रतिदिन 513 ओवन पुशिंग का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया गया था। कोल केमिकल्स की बिक्री में ऐतिहासिक उछाल के साथ कोक ओवन विभाग ने जून 2026 माह में कोल केमिकल्स की बिक्री का एक नया रिकॉर्ड बनाया जो अब तक की सर्वाधिक मासिक बिक्री है. इससे पूर्व सितंबर 2024 में मासिक बिक्री का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कोल केमिकल्स की कुल बिक्री का सर्वश्रेष्ठ कीर्तिमान भी स्थापित किया गया है. इससे पूर्व वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कोल केमिकल्स की बिक्री का रिकॉर्ड स्थापित किया गया था. कोक ओवन विभाग की ये उपलब्धियाँ न केवल उत्पादन दक्षता और परिचालन उत्कृष्टता को दशार्ती हैं, बल्कि यह टीम के अथक और समर्पित प्रयासों का भी जीवंत परिणाम हैं और भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरणास्त्रोत बनेंगी.

बीएसएल में 'स्पर्श - वेलफेयर वॉकः केयर एंड कनेक्ट' का आयोजन

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। बोकारो स्टील प्लांट में कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों के कल्याण, सहभागिता तथा कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 'स्पर्श -वेलफेयर वॉकः केयर एंड कनेक्ट' पहल के अंतर्गत आरएमएचपी विभाग में वेलफेयर वॉक का आयोजन किया गया. इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों से उनके कार्यस्थल पर सीधा संवाद स्थापित कर उनके अनुभवों को समझना, उपलब्ध कल्याणकारी सुविधाओं का आकलन करना तथा आवश्यक सुधारों एवं नई पहलों की संभावनाओं की पहचान करना है. इस वेलफेयर वॉक का नेतृत्व मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) ने किया. उनके साथ आरएमएचपी, सीईडी एवं मानव संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा संबंधित विभागों की टीम

ने आरएमएचपी विभाग के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया. भ्रमण के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने कर्मचारियों एवं ठेका श्रमिकों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया. इस दौरान कार्यस्थल की परिस्थितियों, उपलब्ध कल्याणकारी सुविधाओं तथा उनके प्रभावी उपयोग का अवलोकन किया गया और इन्हें और अधिक सुदृढ़ बनाने एवं नए वेलफेयर उपायों को लागू करने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया. इस अवसर पर कार्यस्थल को और अधिक सुरक्षित, समावेशी एवं संवेदनशील बनाने के संबंध में कई उपयोगी सुझाव भी प्राप्त हुए.

पेटरवार प्रखंड कार्यालय के प्रधान सहायक को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा

तेनुघाट (बोकारो)/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। बेरमो अनुमंडल स्थित पेटरवार प्रखंड कार्यालय में धनबाद एसीबी के टीम ने गुरुवार दोपहर एक बजे छापेमारी की। छापेमारी में प्रखंड कार्यालय में प्रधान सहायक के पोस्ट पर कार्य कर रहे गुलाम रसूल को आठ हजार रिश्वत लेते धनबाद एसीबी की टीम ने रंगे हाथो गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उनके आवास पर भी छापेमारी की गई। गिरफ्तार गुलाम रसूल को अपनी गाड़ी से एसीबी धनबाद ले गई। खबर है कि ग्राम पंचायत ओरदाना दक्षिणी मे पंचायत समिति मद से ओरदाना 10+2 उच्च विद्यालय मे शौचालय का निर्माण कार्य होना था, जिसके लिए प्रक्कलित राशि दो लाख 45 हजार रुपए की योजना प्रेमजीत सिंह पिता स्व. देवेंद्र सिंह, सचिव मुकेश कुमार शर्मा के नाम से स्वीकृत था। उक्त योजना के निमार्णाधीन भवन का बिल पास करने के नाम से पैसे की मांग की जा रही थी। इसी को लेकर प्रेमजीत सिंह के द्वारा धनबाद एसीबी से सम्पर्क किया ज्ञावत। इस मामले में एसीबी प्रखंड विकास पदाधिकारी के उर्दू अनुवादक सह अतिरिक्त प्रभार प्रधान सहायक को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। साथ ही महत्वपूर्ण

दस्तेवेज भी एसीबी धनबाद ले गई। वही ज्ञात हो कि वर्ष 2014-15 मे रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड मे गुलाम रसूल मनरेगा से सुनयोजित तरीके से 74,62,632 रुपए की निकासी करने का आरोप है। जो न्यायलय मे विचाराधीन है। वही रामगढ़ के पूर्व उपायुक्त चंदन कुमार ने उप विकास आयुक्त के प्रतिवेदन के आधार पर गुलाम रसूल के विरुद्ध अनिवार्य सेवा निवृत का दंड दिया था। वहीं इस घटना को लेकर पेटरवार प्रमुख शारदा देवी एवं उप प्रमुख सीमा देवी ने उर्दू अनुवादक सह अतिरिक्त प्रभार प्रधान सहायक गुलाम रसूल की शिकायत 2024 में बोकारो उपायुक्त को लिखित आवेदन देकर की थी। साथ ही तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार महतो को पंचायत समिति की बैठक में भी गुलाम रसूल के बारे में शिकायत की। मगर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किसी तरह का कार्रवाई नहीं की।

बोकारो में नमकीन फैक्ट्री सील, ट्रेड मार्क को लेकर की गई कार्रवाई

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। बोकारो में ट्रेडमार्क विवाद को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। पिंड्राजोड़ा थाना क्षेत्र में संचालित एक नमकीन और फिंगर पापड़ फैक्ट्री पर फूड इंस्पेक्टर ने छापेमारी कर फैक्ट्री को सील कर दिया है। आरोप है कि फैक्ट्री में 'श्री ओम' नाम से ऐसे उत्पाद तैयार और बेचे जा रहे थे, जो 'ओम' ब्रांड से मिलते-जुलते हैं। हालांकि फैक्ट्री संचालक ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उन्होंने ट्रेडमार्क के लिए आवेदन कर रखा है। बोकारो के पिंड्राजोड़ा थाना क्षेत्र स्थित चोरा बस्ती में संचालित कन्हा फूड प्रोसेसिंग नमकीन और फिंगर पापड़ फैक्ट्री पर फूड इंस्पेक्टर ने छापेमारी कर फैक्ट्री को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान जांच में पाया गया कि फैक्ट्री के पास खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का लाइसेंस तो है, लेकिन जिस ट्रेडमार्क नाम से उत्पाद बाजार में बेचे जा रहे थे, उससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई 'ओम' ब्रांड की लीगल टीम के आईपी इन्वेस्टिगेशन रीजनल ऑफिसर ततन बनर्जी की शिकायत के बाद की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पिछले करीब दो वर्षों से 'श्री ओम' नाम से ऐसे उत्पाद बाजार में बेचे जा रहे हैं, जिनसे उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और मूल ब्रांड के कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है। फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि ट्रेडमार्क विवाद उनके विभाग के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। हालांकि खाद्य गुणवत्ता की जांच के लिए नमकीन और अन्य उत्पादों के सैंपल लिए गए हैं तथा एहतियातन फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कन्हा फूड प्रोसेसिंग के संचालक मिथिलेश प्रसाद ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने 'श्री ओम' नाम से ट्रेडमार्क के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। उनका दावा है कि शिकायतकर्ता के पास 'ओम' नाम का ट्रेडमार्क है, जबकि उनका आवेदन 'श्री ओम' नाम के लिए है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस और संबंधित विभाग कर रहे हैं। फिलहाल फैक्ट्री सील कर दी गई है और खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अब जांच रिपोर्ट और ट्रेडमार्क से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

हस्तशिल्पियों के साथ चौपाल कार्यक्रम का आयोजन

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, हस्तशिल्प सेवा केंद्र, देवघर द्वारा कढ़ाई क्राफ्ट के हस्तशिल्पियों के साथ 'चौपाल' का बोकारो जिला के स्किल ट्रेनिंग सेंटर जैनामोड में आयोजन किया गया। चौपाल का उद्देश्य हस्तशिल्पियों के बीच विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं पर परिचर्चा और जागरूकता करना है।

चौपाल में शिल्पी पहचान पत्र, प्रशिक्षण, गांधी शिल्प बाजार, स्वयं सहायता समूह, ई-कॉमर्स पोर्टल, प्रधानमंत्री बीमा योजना, मुद्रा लोन, इत्यादि विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण हस्तशिल्प सेंटर देवघर के प्रभारी तथा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) शत्रुघ्न कुमार ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को साझा किया और योजनाओं के बारे में विस्तृत से बताया। उन्होंने हस्तशिल्पियों से विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न मार्केटिंग इवेंट्स एवं अन्य आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आग्रह किया।

बोकारो पुलिस ने छिनतई करने वाले दो गिरोहों का किया पदार्फाश, पांच अपराधी गिरफ्तार

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। बोकारो पुलिस ने शहर में महिलाओं के गले से चेन छिनतई करने वाले दो गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। जिसमें एक गिरोह अंतरराज्यीय है जबकि दूसरा इंटर डिस्ट्रिक्ट गिरोह है। गिरोह का पदार्फाश करते हुए पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लूटा गया सोने जैसा लॉकेट, 48 हजार रुपये नकद, एक बाइक, मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों ने बोकारो समेत गिरिडीह, रामगढ़ और धनबाद में कई चेन स्नैचिंग की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जांच के दौरान तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर सेक्टर-4 थाना क्षेत्र में 23 जून को लक्ष्मी मार्केट के सामने हुई चेन स्नैचिंग मामले में ओडिशा के जाजपुर निवासी भोला दास को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ समेत कई जिलों में सात महिलाओं से चेन छिनतई की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की। जबकि दूसरे गिरोह ने चास थाना क्षेत्र

में 30 जून को प्रभात होटल के पास महिला से लॉकेट झपटने की घटना की जांच में गठित एसआईटी ने चार अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने 25 जून को रानी सती क्लॉथ स्टोर के सामने हुई चेन स्नैचिंग की घटना में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गिरफ्तार अपराधियों में भोला दास, राणा उर्फ रजनीश सिंह, बिट्टू कुमार सिंह, श्रवण सिन्हा और परमानंद कुमार वर्मा शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने जैसा लॉकेट, बिना नंबर की बाइक, 48 हजार रुपये नकद, मोबाइल फोन और बाइक की चाबी बरामद की है। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह के सदस्यों पर झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की तलाश में जुटी है।

कक्षा मॉनिटरिंग को सुदृढ़ बनाकर शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। शिक्षा परियोजना बोकारो द्वारा 131 सीआरपी एवं बीआरपी के लिए तीन बैचों में दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण की अध्यक्षता एडीपीओ उदय कुमार सिंह द्वारा की गई। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों की विषयगत समझ को सुदृढ़ करना तथा कक्षा अवलोकन के लिए ई-विद्या वाहिनी एप्लिकेशन में दिए गए। संकेतकों पर उनकी स्पष्ट समझ विकसित करना था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विद्यालय भ्रमण के दौरान प्रतिभागी कक्षा का प्रभावी एवं सूक्ष्म अवलोकन कर सकें, सही जानकारी दर्ज करें तथा शिक्षकों को रचनात्मक सुझाव एवं शैक्षणिक सहयोग प्रदान कर सकें। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस में प्रतिभागियों

के साथ बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान, नई पाठ्यपुस्तकों की समझ, प्रभावी कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं, शिक्षण-अधिगम सामग्री के उपयोग, पुस्तकालय संचालन तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। द्वितीय दिवस में ई-विद्या वाहिनी एप्लिकेशन के प्रभावी उपयोग, उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार, विकल्पों के अर्थ तथा उनसे संबंधित विभिन्न कक्षा परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही कक्षा की शिक्षण गुणवत्ता के साथ-साथ बच्चों के सीखने के स्तर का आकलन करने के लिए स्पॉट असेसमेंट की प्रक्रिया एवं उसके महत्व पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान एडीपीओ उदय कुमार सिंह ने विद्यालय एवं कक्षा की गुणवत्तापूर्ण मॉनिटरिंग, ई-विद्या वाहिनी प्लेटफॉर्म के सुव्यवस्थित उपयोग, सही एवं तथ्यात्मक जानकारी दर्ज करने तथा शिक्षकों को प्रभावी शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने इस कार्य के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान की गहन समझ विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त एपीओ श्री अभिनव कुमार सिन्हा ने ई-विद्या वाहिनी से प्राप्त आंकड़ों के प्रभावी उपयोग पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इन आंकड़ों के आधार पर आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी तथा क्लस्टर एवं प्रखंड स्तरीय बैठकों में शैक्षणिक चर्चाओं और अकादमिक सहयोग को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान जिला मास्टर ट्रेनर मनोज कुमार उपाध्याय, रूम टू रीड संस्था से जिला अकादमिक समन्वयक सिद्धार्थ पटेल, राज्य परियोजना कार्यालय से अनुप्रिया रावत एवं कुलदीपक परमार भी उपस्थित रहे।

स्वत्वाधिकारी,
प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक कमल किशोर द्वारा डी.बी. कॉर्प. लि. के लिए भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, गोविंदपुर मेन रोड, अशोक नगर, केजी आश्रम, धनबाद (झारखंड) से मुद्रित तथा प्लांट नंबर-31, कॉपरेटिव कॉलोनी, बोकारो स्टील सिटी, जिला बोकारो (झारखंड) से प्रकाशित। संपादक कमल किशोर, नवबिहार टाइम्स (दैनिक), सत्येंद्र नगर, औरंगाबाद (बिहार),
स्थानीय संपादक :
मनोज विशाल
फोन नंबर-
9431145865
8210783623
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या :
JHAHIN/2017/72655
E-mail-
nbtimesbihar@gmail.com